

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)



(खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुबाध प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का
हिन्दी संस्करण

रविवार, 25 मई, 1990/4 ज्येष्ठ, 1912११११

का
शुद्ध-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
21	2	"रासा सिंह रावत" के स्थान पर "प्रो० रासा सिंह रावत" प्रदिये।
39	नीचे से 2	"रीतालाल" के स्थान पर "रीतलाल" प्रदिये।
54	5	"आदिवासी" के स्थान पर "अनिवासी" प्रदिये।
59	4	"राजेश्वरी" के स्थान पर "राजशेखर" प्रदिये।
59	नीचे से 2	"श्रौर" के स्थान पर "और" प्रदिये।
61	16	"मण्णिराव" के स्थान पर "माण्णिराव" प्रदिये।
83	14	"केम्मना" के स्थान पर "केम्मन्ना" प्रदिये।
89	नीचे से 7	"युननाइटेड" के स्थान पर "युनाईटेड" प्रदिये।
111	5	"सन्त" के स्थान पर "सनत" प्रदिये।
122	18	"हरिश्चक्र" के स्थान पर "हरिश्चक्र" प्रदिये।
130	14	"कर्यदल" के स्थान पर "कार्यदल" प्रदिये।
134	10	"हरिश्चक्र" के स्थान पर "हरिश्चक्र" प्रदिये।
150	16	"पूजिगत का सामान" के स्थान पर "पूजिगत सामान" प्रदिये।
164	5	"राज्य-वार" के स्थान पर "राज्य-वार" प्रदिये।
175	1	"इपात" के स्थान पर "इस्पात" प्रदिये।
176	7	"इपात" के स्थान पर "इस्पात" प्रदिये।
207	नीचे से 10	"शास्त्री" के स्थान पर "शास्त्री" प्रदिये।
212	7	"पोठदुखे" के स्थान पर "पोटदुखे" प्रदिये।

विषय-सूची

नवम मासा, खंड 6,	दूसरा सत्र 1990 : 911 12 (शक)
अंक 49,	शुक्रवार, 25 मई, 1990 4 ज्येष्ठ, 1912 (शक)
विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	2-24
*तारांकित प्रश्न संख्या: 986 से 990	
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	24-220
बारांकित प्रश्न संख्या: 991 से 1007	24-39
अतारांकित प्रश्न संख्या: 10401 से 10633	39-220
निधन सम्बन्धी उल्लेख	220 224
श्री विद्वनाथ प्रताप सिंह	221
प्रो० एन० जी० रमा	221
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	221-222
श्री गोमनाथ चटर्जी	222
श्रीमती गीता मुखर्जी	222

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित—चिन्ह इस बात का सूचक है कि समा में उस प्रश्न का उस ही सदस्य ने पूछा था।

	पृष्ठ
डा० तन्त्रि दुरै	223
श्री नानी मट्टाचार्य	223
श्री इक़्बालीम-मुन्नेमान सेट	223
प्रो० संप्रदीप सोज	223
कुमारी मायाबली	224
श्री चित्त बसु	224

लोक सभा

शुक्रवार, 25 मई, 1990/4 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर सभ्येत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : क्या मैं समूची सभा से अनुरोध कर सकता हूँ। एक गम्भीर मामला उठाया गया है। आज साप्ताहिक 'दिकरेंट' में कश्मीर के राज्यपाल द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कश्मीर के सभी मुसलमानों को आतंकवादी बताया है और कहा है, "सबसे पहले मैं उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ"...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी आप प्रश्न-काल चलने दीजिये।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : आज हम कश्मीर पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैं प्रश्न-काल को निलंबित करने के लिये नहीं कह रहा हूँ? मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रश्न-काल के प्रस्ताव सबसे पहले कश्मीर पर चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गेहूं की मूसी का निर्यात

*986 श्री के. एस. राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं की मूसी का निर्यात करने के लिये कोई विशेष प्रक्रिया बनाई है;
(ख) यदि हां, तो क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण को इस मामले में अधिक शक्तियां दी गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीधरन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा हॉल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) गेहूं की मूसी को आयात एवं निर्यात नीति भाग-11 की सूची 2 भाग ख की अनुसूची 1 में एक ऐसी मद के रूप में दर्शाया गया है, जिसके निर्यात पर वार्षिक उच्चतम सीमा की शर्त है। इस मद की उच्चतम सीमा रिलीज करने की क्रियाविधि प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

वर्ष 1989-90 में गेहूं की मूसी के लिये उच्चतम सीमा 10,000 मी. टन थी जिसका कार्य कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को सौंपा गया था और इसके लिये पिछली आयाम और निर्यात नीति खण्ड II के पैरा 12 (3) के अनुसार एक विशेष क्रिया-विधि निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में सक्षिप्त मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं।

वर्ष 1990-91 के लिये गेहूं की मूसी के निर्यात की सीमा और क्रियाविधि अभी अधिसूचित की शानी है।

अनुबन्ध

वर्ष 1989-90 में गेहूं की मूसी के निर्यात के लिये "विशेष" क्रियाविधि (सी०सी०आई०एण्ड ई० द्वारा 31.1.90 को जारी किये गये आदेश 31.3.90 तक बंध)

यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नीति-पुस्तिका के खण्ड 1 के पैरा 12 (3) की शर्तों के अनुसार गेहूं की मूसी के निर्यात के लिये एक विशेष क्रियाविधि तैयार की जाए :—

(1) गेहूं की मूसी के निर्यात के लिये उच्चतम सीमा निर्धारित करने का कार्य कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली (एपीडा) को दिया जावेगा।

(1990-91-92)

(II) निर्यातकों को अपनी संविदाओं का पंजीकरण कराना होगा जिसके समर्थन में एपीडा के साथ 100% अपरिवर्तनीय साख पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(III) निर्यात नीति 1988-91 (भाग II) के खण्ड VI में निर्धारित नियमों के अनुसार निर्यातक एक बैंक गारंटी एपीडा को प्रस्तुत करेंगे जो सरकार के पक्ष में बांड के जरिये अपरिवर्तनीय साख पत्र के एक प्रतिशत एफ.ओ.बी. मूल्य के बराबर होगी।

(IV) एपीडा किसी भी निर्यातक को कुल उच्चतम सीमा के 10% से अधिक आबंटित नहीं करेगा।

(V) उक्त शर्तें पूरी करने पर एपीडा, पहले-आओ-पहले-वाओ आधार पर निर्यातकों को उच्चतम सीमा की स्लिप जारी करेगा, जिसमें पूरे ब्योरे दिये होंगे, जैसे निर्यातक का नाम, आदेश और अपरिवर्तनीय साख पत्र की संख्या तथा तारीख, स्वीकृत मात्रा, एफ.ओ.बी. मूल्य और गन्तव्य स्थान।

(VI) एपीडा सम्बन्धित पलन लाइसेंसिंग अधिकारियों को बैंक गारंटी सहित रिलीज सलाह भेजेगा, जो एपीडा से यह प्राप्त करने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि 48 बंटों के अंदर निर्यात लाइसेंस जारी किया जाये और यह 31 मार्च, 1990 तक वैध होगा।

(VII) समूचा निर्यात, निर्यात-लाइसेंस की वैध अवधि के अन्दर ही किया जायेगा। ऐसा न करने पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(VIII) दिनांक 31 मार्च, 1990 के बाद संविदाओं का कोई पंजीकरण नहीं होगा और न ही एपीडा किसी निर्यात की अनुमति देगा, चाहे उच्चतम सीमा अप्रयुक्त ही रह गई हो।

ज्यों ही उच्चतम सीमा पूरी हो जाती है, एपीडा इस तथ्य की जानकारी वाणिज्य मंत्रालय, ई.पी. (एपी-II) अनुभाग को देगा।

श्री के० एस० राव : मैंने मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये जबाब को देख लिया है। समाचार पत्रों में पहले ही सूचना प्रकाशित हो चुकी है। कुछ और बातों के साथ उसी बात को दोहराया गया है।

यह देखा गया है कि शुरुआत में उच्चतम सीमा 10,000 टन निर्धारित की गई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सीमा किसी बैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गई है क्योंकि देश में गेहूँ और मूसी का पर्याप्त उत्पादन होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा गेहूँ उत्पादकों को बेहतर मूल्य देने की मंशा पर आधारित है अथवा मात्राओं की उपलब्धता पर?

श्री अरविश बोरन : 10,000 मीट्रिक टन की यह सीमा कृषि मंत्रालय के ज्ञाता विभाग

तथा साथ प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहमति से निर्धारित की गई है।

हम जब कभी किसी वस्तु का निर्यात करते हैं तो हमारा मुख्य बल विदेशी मुद्रा अर्जन पर होता है। इन मामले में भी हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री के. एस. राव : आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या निर्यात के लिये उपलब्ध कुल मात्रा पर विचार किया जाता है अथवा नहीं। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था।

मेरा दूसरा प्रश्न चावल की भूसी के सम्बन्ध में है, आन्ध्र प्रदेश में चावल की भूसी से तेल निकालने वाली मिलें अनेक बार इसकी कमी महसूस करती हैं। चावल की भूसी, खल तथा तेन के निर्यात की क्षमता भी बहुत अधिक है। इससे पहले चावल मिल मालिकों के संघ तथा घान उत्पादकों ने सरकार से निवेदन किया है कि उन्हें इन्डोनेशिया, बंगलादेश आदि देशों से, जहाँ यह सस्ती दर पर उपलब्ध होती है, चावल की भूसी के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये तथा वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि देश में इनने ही मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जाती है तथा यह मिल मालिकों के अतिरिक्त राष्ट्र के हित में है। यदि मंत्री महोदय की मंशा विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिये उच्चतम सीमा 10,000 टन निर्धारित करने की है तो चावल मिल मालिकों को चावल की भूसी के आयात तथा तेल और खली के निर्यात की अनुमति देकर पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की जा सकती थी। सरकार ने चावल के आयात के सम्बन्ध में कोई निणय को क्यों नहीं लिया है ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न दोहराया है। कृषि मन्त्रालय गेहूँ की भूसी जैसी वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में निर्णय करता है। हम केवल उनकी मांग और सहमति प्राप्त करते हैं।

जहाँ तक चावल की भूसी का सम्बन्ध है, तत्काल जबाब देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। प्रश्न गेहूँ की भूसी से संबंधित है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि देश में चावल की भूसी के आयात पर रोक लगी हुई है।

श्री ए. चार्स : मैं जानता हूँ कि प्रश्न वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित है। लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि गेहूँ की भूसी का भारत में साथ प्रसंस्करण एककों द्वारा उचित ढंग से प्रसंस्करण किया जाये तो हमारे साथ उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या साथ प्रसंस्करण विभाग को उचित निर्देश दिए जायेंगे ताकि गेहूँ की भूसी का कच्चे माल के रूप में निर्यात करने के बजाए इसके प्रसंस्करण की संभावना को सुनिश्चित किया जा सके और इस संसाधित योजना के रूप में आयात किया जा सके ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : गेहूँ की भूसी का दो कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता है। एक पशुओं के भोजन में दूसरा साथ के रूप में। हमने भारत में इस संभावना की जांच नहीं की है। हम मास्यनीय सदस्य द्वारा उठये स्ये इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री एम बाणा रेड्डी : विगत वर्ष के निर्यात के लिये 10,000 टन गेहूं की मूसी का कोटा निर्धारित किया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह लक्ष्य पूरा किया जायेगा अथवा नहीं। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : 1989-90 में निम्नलिखित दो कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये परंतु आयात नहीं किया गया—

(1) आशा प्योर मिनाकेमा (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई।

(2) आर.ई.पी.एल. इन्जीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

1989-90 में निर्यात प्रभावी नहीं हो सका। पहली कम्पनी ने निर्यात लाइसेंस नहीं लिखा है और दूसरी कम्पनी ने निर्यात लाइसेंस की वैधता के कार्यकाल में वृद्धि की मांग की है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन घाबळ : मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस देश में छोटे छोटे उद्योग चलाये के लिये राईस ब्रान की आवश्यकता है, जो निर्यात नहीं हो पाते हैं उस आचार पर हिन्दुस्तान में कोई मिल, उद्योग चलाना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अरंगिल श्रीधरन : मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में इस सभा में बताया था कि देश में चावल की मूसी के निर्यात पर रोक है इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात में कृषि उत्पादों का अंश

*987. **श्री चाङ्गमाई वेण्मणुस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) वर्ष 1990-91 के लिये कितना निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार की नीति क्या है;

(ख) इस लक्ष्य में कृषि वस्तुओं के निर्यात का कितना अंश है; और

(ग) कुल निर्यात में कृषि पर आधारित उद्योगों का अंश बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पथटन मंत्री (श्री अरुण कुमार मेहता) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1990-91 के लिये वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य 36,000 करोड़ रुपये है। इस नीति का उद्देश्य मुख्यतः औद्योगिक क्षमता में सुधार करके निर्यातों को व्याव-

साथिक रूप से अर्थक्षम बनाना, प्रतियोगी कीमतों पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना अवस्थापना को सुदृढ़ करना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बागान और समुद्री उत्पाद सहित कृषि मर्चों का योगदान कुल लक्ष्य का 15% से 16% तक होने का अनुमान है।

(ग) कृषि मर्चों के निर्यात बढ़ाने के लिये मूल नीति में निर्यात बेसी माल सृजित करना, मूल्य बर्धित रूपों में निर्यात को बढ़ावा देना, आयातक देशों में ग्राह्यता बढ़ाने के लिये क्वालिटी और पैकेजिंग में सुधार करना, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास और साथ ही विपणन संवर्धन, सांविधिक बोर्डों/प्राधिकरणों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा क्वालिटी नियंत्रण अभिकरणों के जरिए क्वालिटी कंट्रोल और संस्थागत सहायता का प्रावधान बनाए रखना शामिल होगा।

[हिन्दी]

श्री चम्पूनाई वेंकटेश्वर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया 1990-91 में निर्यात का लक्ष्य 36 हजार करोड़ रुपये है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 1989-90 में यह लक्ष्य कितना था और गत वर्ष की तुलना में यह रकम ज्यादा है या कम है और उन मुद्दों में जो योगदान है उसमें कौन-कौन-सी चीजें शामिल हैं?

[अनुवाद]

श्री अचय कुमार नेहरू : 1989-90 में 27,682 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि 1988-89 में यह 20,302 करोड़ रुपये था। रुपये के सन्दर्भ में हमारी विकास दर 36.5 प्रतिशत तथा अमेरिकी डालर के सन्दर्भ में 15.7 प्रतिशत है। आंकड़े बहुत अधिक हैं, मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ परन्तु इसमें समय लगेगा। भारत के निर्यात में अनुमानित 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहाँ तक 1990-91 के लिए जिसमें हमने 36,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, कुल निर्यात का सम्बन्ध है, कृषि तथा समुद्री उत्पादों का 15.88 प्रतिशत निर्यात हुआ है जो 5,610 करोड़ रुपये के बराबर है।

प्रो० के० बी० चामस : महोदय, समुद्री उत्पादों का निर्यात एक ऐसा प्रमुख स्रोत है जिसके द्वारा हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। मन्त्री महोदय बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्री उत्पादों की दो प्रमुख समस्याएँ हैं। पहली, मछली पकड़ने में विदेशी नौकाओं का इतना प्रयोग किया जा रहा है कि हमें 5% मछलियाँ भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिये सरकार स्वदेशी मछली पकड़ने की नौकाओं के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी? दूसरी, हमारे कुछ निर्यातक गुणवत्ता के प्रति आगस्त नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात की कुछ मर्चें, जिन्हें विदेशों को भेजा जाता है, वापस लौट आती हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन दो बातों की—पहली मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं और दूसरी निर्यात की जाने वाली मछलियों की गुणवत्ता की जाँच करेगी।

श्री अचय कुमार नेहरू : माननीय सदस्य ने कुछ बड़ी तर्क संगत बातें कही हैं। हमारे सामने कुछ समस्याएँ दूसरे देशों की मछली पकड़ने की नौकाओं, जो हमारे समुद्री क्षेत्र में आती हैं, के

सम्बन्ध में है। परन्तु यह गम्भीर समस्या नहीं है। इनका प्रतिशत बहुत कम है। विगत कुछ वर्षों में हमने कुछ नौकाओं को ज्वस्त कर लिया है। परन्तु हमारे पास मछली पकड़ने की नौकाओं की कमी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्री उत्पादों में झींगा मछली का निर्यात होता है। जहाँ तक झींगा का सम्बन्ध है, यह देश में हो खारे पानी में पैदा की जा रही है। जहाँ तक निर्यात का संबंध है, यदि आप समुद्री उत्पादों के निर्यात पर ध्यान दें तो आप यह समझ सकते हैं कि विगत वर्ष उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। वंसी वृद्धि नहीं हुई है जैसी हम चाहते थे। उसके लिये हम बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य बाजार जापान और अमेरिका हैं। अमेरिका के साथ हमारी कुछ समस्याएँ गुणवत्ता के संबंध में हैं। हम अपने निर्यातकों को समझा रहे हैं कि उन्हें प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण बनाये रखना चाहिये। समुद्री उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या केवल हमारे मामले ही नहीं है बल्कि अन्य देश भी इसमें ग्रस्त हैं। यदि आपकी दो से लेकर तीन प्रतिशत तक समस्या है तो यह सहनीय है। यदि यह पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो यह बड़ी गम्भीर समस्या हो जाती है। कुछ उपाय किये गये हैं। गुणवत्ता योजना का पालन न करने वाले निर्माताओं से इसके अनुपालन के लिये कहा गया है।

श्री नानी भट्टाचार्य : महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सभा को सूचित करें कि क्या इस निर्यात लक्ष्य का मूल्यांकन 36,000 करोड़ रुपये है? मसाले और बागान समेत कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में क्या विचार है? यह पहला भाग है। दूसरे, पूर्वी यूरोप तथा अन्य देशों को निर्यात की संभावना का पता लगाते तथा लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल ही में वहाँ की ताकतों के एकीकरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : जहाँ तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को विगत तीन वर्षों के आँकड़े बताना चाहता हूँ। उत्पादों का उल्लेख करते समय हम बागान और समुद्री उत्पादों को भी शामिल कर लेते हैं। 1988-89 में 3,556 करोड़ रुपये के उत्पाद का निर्यात हुआ था। विगत वर्ष हमने 4,434 करोड़ रुपये के उत्पाद का निर्यात किया गया। बालू वर्ष में हमारा निर्यात 5610 करोड़ रुपये है। यदि आप प्रत्येक उत्पाद जैसे मसाले, काजू, तम्बाकू, दालें, खली के आँकड़े चाहते हैं, तो वह मैं आपको दे सकता हूँ। यदि आप 36,000 करोड़ रुपये में से प्रतिशत निर्यात के सम्बन्ध में देखें तो कृषि उत्पादों का कुल निर्यात प्रतिशत, कुल निर्यात का 15.88 प्रतिशत है। जहाँ तक पूर्वी यूरोप में आये बदलाव का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इससे हमारे निर्यात पर मूलतः अमर पड़ेगा। हमें किसी समस्या का अंदेश नहीं है। जो भी बजट हमने निर्धारित किया है, उसमें हमने पूर्वी यूरोप को भी ध्यान में रखा है। ऐसे देश बढ़न कम हैं जो हमसे दुर्लभ मुद्रा में व्यापार करना चाहते हों। हमने यह कहा है कि यदि वह दुर्लभ मुद्रा में मुगलान करना चाहते हैं तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। अतः किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मणलाल शीना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से लहसुन की खेती का जा रहा है, उसका सागत मुख्य और उसका जो बीज है, वह लगभग 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बँटता है

परन्तु जब किसान उसको बाजार में बेचने जाता है तो उसको 190 रुपए से लेकर 400-500 रु० बिंदल का भाव मिल रहा है, किसानों का इसमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। क्या भारत सरकार कृषि वस्तुओं में लहसुन का निर्यात करने का इरादा भी रखती है या नहीं रखती तो उसका मूल्य निर्धारण करके यह बताएं कि काश्तकारों को उसके हिसाब से कितनी क्षति नागन मूल्य के हिसाब से हो रही है और उसको किस तरह से मीट प्राउट करने का सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय की ओर से उत्तर नहीं दे सकता। मूलतः इन समस्याओं को वहीं देखते हैं। यदि वह कुछ और क्षत्र हमें दे सके फिर हम... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस लहसुन के भाव में किसानों को तीन-तीन, चार चार हजार रुपए प्रति बीघा का नुकसान हो रहा है तो इसको आप निर्यात करेंगे क्या ? -- (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोर्शा जी, आपको मैं नहीं बुलाया, आप बैठ जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश से सब्जियों, फलों और अन्य समुद्री उत्पाद की अल्पकालीन निर्यात सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर सकता हूँ कि वह हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तन करने के लिए नागरिक विमानन मन्त्री से बात करें।

श्री अरुण कुमार नेहरू : मैं नहीं जानता। जहाँ तक हवाई माल वहन के स्थान का सम्बन्ध है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ लेकिन, ऐसा करना मेरे कार्यक्षेत्र के बाहर होगा। मैं नहीं समझता कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इसमें कोई सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि सम्बन्धी सारी चीजें पैदा होती हैं। मैं वाणिज्य मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि इतना सामान पैदा होने के बावजूद कौन-कौन से सामान हमारे देश में आयात किये जाते हैं और उस आयात को रोकने के लिये क्या-क्या कदम सरकार उठा रही है।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, निर्यात किए गये वस्तुओं में से किसी का भी आयात नहीं

किया जा रहा है। आयात तभी किया जाता है जब किसी माल की कमी होती है। ताड़ के तेल 'पाम आबल' जैसी वस्तु की यदि थोड़ी कमी होती है, तब उसका आयात किया जाता है। चार-पांच वर्ष पूर्व हम ताड़ के तेल के एक मिलियन टन के तीन-चौथाई भाग का आयात करते थे। आज हम एक सौ टन का भी आयात नहीं कर रहे हैं। हम खाद्यान्नों का बहुत कम आयात करते हैं। यह तभी है, जब हमारे पास कमी थोड़ी ही हो। अन्वेषा जब हमारे पास अधिक माल होता है तो हम निर्यात करते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभी कृषि उत्पादों के लिए कृषि मन्त्रालय ही वस्तु की अधिकता बताता है और तभी हम निर्यात करते हैं। अतः, जब तक वस्तु की अधिकता का उनसे पता न लगे भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है।

डा० असीम बाला : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कृषि उत्पादों का निर्यात कुल निर्यात का 15 से 16 प्रतिशत है। यहाँ मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पशु संबंधी निर्यात का प्रतिशत क्या है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, इसकी अनग-अलग पांच सौ मर्चे हैं। हमें प्रत्येक मद की प्रतिशतता निकालनी होगी। (व्यवधान)

डा० असीम बाला : महोदय, मैं चाहता था कि पशु संबंधी निर्यात का प्रतिशत मुझे बताया जाये।

श्री अरुण कुमार नेहरू : हम ऐसा ही करेंगे।

श्री एस० बी० चोरट : महोदय, मेरा प्रश्न मुख्य उत्तर के भाग 'ग' से संबंधित है उत्तर में यह दिया गया है,

"कृषि मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात के लिए अतिरिक्त मण्डार कायम करने की नीति अपनानी होगी।"

कपास और सूत दो ऐसी मर्चे हैं, जो निर्यात वेशी माल को सृजित करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कपास के निर्यात के लिए निवेदन किया है। केन्द्र सरकार ने कपास और सूत का निर्यात बन्द कर दिया है। क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और महाराष्ट्र सरकार को कपास और सूत के निर्यात की अनुमति देगी ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, यह वस्त्र मन्त्रालय से सम्बन्धित मामला है।

श्री बाल गोपाल बिज : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, चीना, चीनी का निर्यात विदेशी मुद्रा का एक बड़ा जरिया बन गया है। लेकिन, जापान ने भारत से चीना-चीनी के आयात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में इसकी गुण-वत्ता खराब रही है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भारतीय बाजार को खराब करने में गन्नाधारी व्यापारियों का हाथ पड़ा है।

श्री अश्व कुमार नेहरू : महोदय, मेरे क्याल में माननीय सदस्य की जानकारी पूर्णतया गलत है। जापान ने आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। दर असल जापान हमारा सबसे बड़ा बाजार है। हम लगभग 300-400 करोड़ रुपये मूल्य के समुद्री उत्पादों को उन्हें बेच रहे हैं।

जहां तक गलाघारी माइनों का सम्बन्ध है, मुझे नहीं मालूम कि श्रींगा के निर्यात से उनका क्या सम्बन्ध है। कई सौ पार्टियां भारत से श्रींगा का निर्यात कर रहीं हैं। लेकिन, हमें किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

श्री जार्ज कर्नाडीय : मेरे माननीय मित्र ने अरब सागर के जल में मछली पकड़ने का उल्लेख किया है। मेरी जानकारी के अनुसार विदेशी राष्ट्र निश्चित तौर पर सागर में 'पुसियन नावों' के साथ मछली पकड़ रहे हैं, जो आधुनिकतम उपकरणों से युक्त हैं और जिनमें रेफ्रिजरेशन की सुविधा भी है, जो एक बार में हमारे जल में दो महीने से अधिक समय तक रहती हैं।

मेरे माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि यदि हमारे पास आधुनिकतम उपकरण नहीं हैं, तो क्या हम अन्य देशों से हमारे कर्मचारियों को इन नावों के संचालन का प्रशिक्षण देने का अनुरोध कर सकते हैं जिससे निर्यात व्यापार में हिस्से को बढ़ाया जा सके विशेषकर टूना मछली के निर्यात को।

श्री अश्व कुमार नेहरू : महोदय, हमारा किसी अन्य से मछली मारने के लिए आधुनिकतम उपकरण खरीदने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक हमारी जल सीमा का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष प्रकार के जहाजों की जानकारी है, जो हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं, तब हम इस मामले को देख सकते हैं। हमें इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कुछ मंत्रचालित नौकायें आई हैं, कुछ यंत्रचालित नौकायें पकड़ी भी गई हैं। इसके आगे ज्यादा मछली नहीं पकड़ी जा रही है।

जहां तक टूना मछली का सम्बन्ध है, हमने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। हम टूना मछली को पकड़ने को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन, रेफ्रिजरेटिड जहाज हमारे जल में आ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बिलीय सिंह छुरिया : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हम टोटल 36 हजार करोड़ रुपये का यहाँ से माल दूसरी कंट्रीज में भेजेंगे। हम जो माल बाहर भेजते हैं उसके बारे में एक ठो कम्प्लेंट बहुत सारी आती है कि जो माल यहाँ का पसन्द किया जाता है वह माल नहीं भेजा जाता है। एथीकल्वर प्रोड्यूस यहाँ से बाहर भेजने के लिए नकद बना था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सारी प्राइवेट पार्टियों को लक्ष्य करके जो हमारी ऐसी एजेंसी हैं उनके जरिये से माल बाहर भेजेंगे? ताकि बाहर से कोई कम्प्लेंट नहीं आवे और जो माल पसन्द किया जाए, वही उनको भेजा जाए। प्राइवेट पार्टियाँ एक ठो मात्र समय पर यहाँ भेजेंगी और दुसरे फुट

और सम्झियां रास्ते में खराब हो जाती हैं। इससे हमारी सार्वजनिक गिरती है। क्या आप क्वेबेक जैसी संस्था के जरिये से माल बाहर भेजेंगे ?

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार मेहता : महोदय जब हम ताजी सम्झियों और कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं, तो कुछ मात्रा में गुणवत्ता में कमी की शिकायतें आती ही हैं। यह शिकायतें सरकारी और निजी दोनों तरफ से की गई हैं। लेकिन, मैं नहीं समझता कि सरकार को इसे पूर्ण रूप से बेचे के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकता है अथवा न ही इससे समस्या का समाधान होगा। सत्य है कि हमें जहाज पर सदान से पूर्व निरीक्षण को सुधारना होगा। हमें लोगों को यह बात समझानी होगी कि यदि उनके माल को रद्द कर दिया तो उन्हें दुबारा निर्यात आदेश नहीं मिलेगा।

श्री लोक नाथ चौधरी : ऐसा लगता है कि समुद्री उत्पाद का निर्यात हमारे निर्यात का एक बड़ा भाग है और भारत सरकार इसका निर्यात बढ़ाकर हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहती है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूँ कि समुद्री उत्पाद जैसे अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? शींगा मछली के अलावा अन्य प्रकार की मछलियां भी हैं। और वे बेकार हो गए हैं क्योंकि उन्हें संसाधित नहीं किया गया। इसके अलावा, अन्य समुद्री उत्पाद भी हैं जिन्हें संसाधित किया जा सकता है और उनका निर्यात किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो जाल-पोत मालिक दिवालिये हो रहे हैं, उनकी सहायता करने का वाणिज्य मन्त्रालय का क्या कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं। शींगा मछलियों के अलावा अन्य किस्म की मछलियां भी हैं जिन्हें निर्यात करने की योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए। दूसरा, मैं उड़ीयन लौह अयस्क खानों के बारे में जानना चाहता हूँ जिनकी विदेशी बाजारों में अच्छी मांग थी। लेकिन इन लौह अयस्क खानों को बन्द किया जा रहा है क्योंकि अब निर्यात कम कर दिया गया है। मैं इस तथ्य को वाणिज्य मन्त्री के नोट्स में लाना चाहता हूँ और उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उड़ीसा के वर्तमान खनन कार्य के बारे में वे क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं जिससे कम से कम वहां श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सके ?

श्री अरुण कुमार मेहता : मत्स्य पालन और लौह अयस्क बहुत ही मिनरल क्षेत्र हैं। लेकिन मुझे उनके प्रश्न का उत्तर देने में आपत्ति नहीं है। सबसे पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि जहां तक समुद्री उत्पादों के बारे में कुल विश्व बाजार का सम्बन्ध है, यह 50 बिलियन डालर है और 50 बिलियन डालर में से 40 बिलियन डालर मछली उत्पाद से सम्बन्धित है। हम यूरोप और अमरीका में विदेशी बाजारों में अन्य प्रकार की मछलियों के निर्यात को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम कटल मछली और अन्य प्रकार की मछलियों जैसी बहुत-सी अन्य चीजों का निर्यात कर रहे हैं। उड़ीसा में, हमने भारी निवेश किया है और हम शींगा मछली के उत्पादन और श्रोकिश शींगा मछली के उत्पादन के लिए और अधिक निवेश करना चाहते हैं। हम इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से बात कर रहे हैं। जहां तक उड़ीसा में लौह-अयस्क का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि हम पारादीप पत्तन को भी गहरा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि अतिरिक्त

बात्रा में निर्यात किया जा सके। उड़ीसा में लौह-अयस्क का निर्यात कम नहीं हुआ है। हम उड़ीसा में कुछ लौह-अयस्क को अपने मस्य के उत्पादन के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ लौह-अयस्क के निर्यात का कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और उड़ीसा में बेरोजगारी पैदा होने का भी कोई प्रश्न नहीं है।

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल

[हिन्दी]

*988, श्री हरि लंकर महाले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों का ब्योरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्थानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन स्थानों का और विकास करने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण लाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थानों का अभिनिर्धारण एवं विकास करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुणावगुणों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाएँ/स्कीमें स्वीकृत की थीं :—

1. बोबी-का-मकबरा, औरंगाबाद, पर प्रकाश-मुंज व्यवस्था
2. अर्बता, एलिफेन्टा और एल्होरा में टायलेट तथा पेय जल की व्यवस्था
3. गणपतिकुले में कुटीरें
4. बलनेश्वर में समुद्रतट विहाय-स्थल

5. शीमा में यात्री निवास
6. शीमा में मार्गस्थ सुविधाएं
7. महाराष्ट्र के लिए पैदल-भ्रमण उपकरण
8. जल क्रीड़ा उपकरण ।

(य) वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु अनुमानों सहित विस्तृत परिवी-
जना रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी प्रस्तुत करनी है ।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने पर्यटन स्थलों का व्योरा दिया है, उसमें तो कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम नहीं है, लेकिन दिल्ली में 8-10 होटल हैं—अशोक होटल है और उसके बगल में सम्राट होटल है, 26 करोड़ रुपए की धनराशि, उसके बनाने के लिये खर्च की गई है ।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे रहे हैं या सूचना पाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री हरि शंकर महाले : उसमें तीन मंजिल वाली हैं, इसमें बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं; यह उचित है या अनुचित है ?.....(व्यवधान).....अध्यक्ष महोदय, मुम्बई जैसे शहर में एक भी होटल नहीं है परन्तु आई टी०डी०सी० का पब्लिसिटी साहित्य कुछ और ही कहता है । आई० टी० डी० सी० ने महाराष्ट्र के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है, तो क्या जो पब्लिसिटी साहित्य बताया है, वह सही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप महाराष्ट्र के लिए पूछिये ।

श्री हरि शंकर महाले : मुम्बई शहर इतना बड़ा शहर है और वहां पर आई० टी० डी० सी० ने एक भी होटल नहीं खोला है, जो पब्लिसिटी साहित्य होता है, प्रचार करने के लिये, वह साहित्य भी उपलब्ध नहीं है, यह बात क्या सच है ?

श्री सत्यपाल बलिक : मैं तो पहले ही निवेदन कर रहा हूँ कि जो सदन के पटल पर अबाध रखा गया है, उसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो महाराष्ट्र में पर्यटन विकास के लिए कार्य किया गया है उस सबकी जानकारी दी गई है । जहां तक होटलों का ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से, महाराष्ट्र में जो होटल हैं, उनके बारे में बता देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : सारे महाराष्ट्र में होटल के नाम मत गिनवाईए, सिर्फ नम्बर बता दीजिए ।

श्री सत्यपाल बलिक : मैं नम्बर ही बता रहा हूँ । महाराष्ट्र में फाइव स्टार वीलक्स होटल सात हैं, फाइव स्टार होटल 11 हैं, फोर स्टार 10, थ्री स्टार 19, 2 स्टार 31 और वन स्टार 12 होटल हैं । वन होटल को क्लासिफाई करना है, उनकी संख्या 26 है ।

जी हरि संकर महासे : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जबाब नहीं मिला है। यह जो सम्राट होटल के बगल में, इस पर 26 करोड़ रुपए की धनराशि बिना वजह खर्च की गई है, इस पैसे का खर्च उचित नहीं है, गलत खर्च किया गया है और वह होटल खासी पड़ा हुआ है। वहां पर बड़े-बड़े आफिसर्स रहते हैं।....(व्यवधान)

जी सत्यपाल बलिक : माननीय सदस्य को जो चिंता है, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनकी जानकारी बिल्कुल उल्टी है। आई०टी०डी०सी० के जो होटल चल रहे हैं, उनमें काफी मुनाफा है, लेकिन फिर भी सरकार की नीति यह है कि अब कोई बड़ा होटल न बनाया जाए, महंगा होटल न बनाया जाए, बल्कि जगह जगह यात्री-निवास, जहां जहां राज्यों की मांग है, उनको बनाने में प्राथमिकता दे रहे हैं और पैसा उसमें लगा रहे हैं।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महासे जी, आप बैठ जाइए। आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं, अब सदन का समय गट मत करिए।

[अनुवाद]

जी ए० आर० अम्बुले : जैसा कि सुविदित है, महाराष्ट्र का कोंकण तट बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है जहां बहुत ही सुन्दर अच्छे समुद्र तट हैं और देश को यथार्थ में इन पर गर्व हो सकता है। यह केवल महाराष्ट्र का ही तट नहीं है, अपितु इसे राष्ट्रीय तट भी कहा जा सकता है जिनमें काफी प्राकृतिक बन है। सम्पूर्ण तट में बहुत ही सुन्दर संकरी खाड़ियां हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि इस मामले को केवल राज्य सरकार पर छोड़ने की बजाए, 'साउथ ऑफ फ्रांस' की तरह क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण कोंकण तट को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकास के लिए लिया जाएगा? कोंकण तट की तरह 'साउथ ऑफ फ्रांस' तट में कोई संकरी खाड़ियां नहीं हैं। चूंकि संकरी खाड़ियां, जो कि अच्छी हैं, तट पर समुद्री तटों के साथ-साथ बहुत ही सुन्दर और आकर्षक हॉलीडे स्पल और पर्यटक स्पल बन सकती हैं, वह न केवल रत्न-मिरी जिले के गणपतिकुले में बल्कि बहुत से अन्य स्थलों पर भी बनाए जा सकते हैं और यह 300 सप्ते कोंकण तट के साथ-साथ कम से कम तीस से चालीस तक बनाए जा सकते हैं, अतः क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि विदेशी मुद्रा आर्जन करने के लिए इस परियोजना को 'साउथ ऑफ फ्रांस' की तरह विकास के लिए विशेष राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाएगा?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (जी अरब कुमार नेहरू) : पर्यटन के उद्देश्य के लिए, जहां तक संभव होगा हम निश्चित रूप से अधिक से अधिक सुविधाएं और आभारमूलक सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। सम्पूर्ण देश में इस प्रकार की बहुत-सी योजनाएं हमारे पास आ रही हैं और हम निश्चित रूप से कोंकण क्षेत्र में समुद्री तट स्थल की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन जैसाकि आप जानते हैं, हमारे बजट में बहुत से दबाव हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, पर्यटन मंत्रालय प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर सुझाव, राज्य सरकारों से आने होते

हैं। और यदि राज्य सरकारों से अच्छे सुझाव आते हैं। तो धन की उपलब्धता को देखते हुए हम निश्चित रूप से उन पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, आज 25 मई है और 1990-91 के बजट को आए हुए 2 महीने के करीब पूरे हो रहे हैं। उत्तर के सी भाग में आपने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक प्रपोजल्स भी नहीं भेजे हैं, इस प्रकार की जानकारी इसमें दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को प्रपोजल्स कब भेजने चाहिए थे और प्रपोजल्स न भेजने के क्या कारण हैं और महाराष्ट्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है।

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, होता यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बताती है और प्रायोरिटी बताती है कि हमें इन-इन जगहों पर, फ्लां-फ्लां मदद चाहिए। उस सिलसिले में मई में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों और केन्द्र सरकार के आफिसरों के बीच में बातचीत हुई है। कुछ जगह कुछ काम आईडेंटिफाई किए गए हैं जिनको प्रायोरिटी देनी है। मेरे जबाब को माननीय सदस्य गौर से पढ़ें सो पता लगेगा कि एस्टीमेट हमें नहीं मिले। प्रायोरिटी किन-किन चीजों को देनी है, यह लिस्ट मिल गयी है, लेकिन जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट एस्टीमेट है वह हमको नहीं मिले है। इनके ही हम मिलते फौरन कार्यवाही करेंगे।

श्री ईश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के पर्यटन स्थलों का मंत्री जी ने ब्योरा दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका ध्यान बिहार की ओर गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बिहार का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चौधरी : महोदय, प्रश्न राष्ट्रीय महत्त्व का है। राजगिरि, पावापुरी, पारसनाथ, ब्रह्मयोनि, रामशिला, गया, विष्णुपद एवं सम्पूर्ण बौद्ध-गया क्षेत्रों में पर्यटन के महत्त्व से क्या विकास किया है? क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है? क्या इस दृष्टि से, आप अपनी योजनाओं में पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए बौद्ध गया और विष्णु पद को प्राथमिकता देंगे? अगर हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है?

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, हालांकि सामान्य तौर पर हमका सबाल से तात्सुक नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सबाल उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार में बुद्धिस्ट सर्कल, जहां महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके लिए हमने बड़े पैमाने पर योजना बनायी है। उस सिलेसिले में बढ़ा होने वाला है। जिसकी जानकारी, अक्सर से जब खबर पूछा जाएगा तो विश्व बावली 7

श्री गंगाधर लोधी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड ऐतिहासिक भूमि रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह बिहार या उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, वह तो जनरल सवाल है।

(व्यवधान)

श्री गंगाधर लोधी : मैं जनरल सवाल ही पूछ रहा हूँ। मैं मंत्री जी को दो महीने पहले लिख कर दे चुका हूँ, मंत्री महोदय को मालूम होगा। बुन्देलखण्ड में राम की कर्म-स्थली रही है। उसके बाद महाभारत में महाप्राणों के रचयिता की जन्म भूमि काल्पी रही है। उसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास की शुरुआत झांसी से हुई, महारानी लक्ष्मीबाई से हुई। महावीरों में गिने जाने वाले आला-उदल की जन्मभूमि महूआ रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन ऐतिहासिक स्थलों का विकास करने के लिए पर्यटन विभाग क्या कर रहा है? क्योंकि यहां पर बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन निराश होकर चले जाते हैं। उनके पास कोई साधन आन-जान का नहीं रहता है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यहां के विकास के लिए पर्यटन विभाग क्या कर रहा है?

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार से इन तमाम स्थानों के लिए जो हमें करने के लिए मिलेगा, हम उस पर पोजिटिवली विचार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए, हमने जो चीजें अभी कल-परमों ही तय की हैं, वह मैं बता देना चाहता हूँ। बिठूर जो नाना जी की कर्म-स्थली रही है, वहां पर बड़े मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां पर कैफेटेरिया भी बना रहे हैं। हमारा विभाग दो तरह से काम करता है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार से बुन्देलखण्ड के लिए जो भी मिलेगा हम उस पर कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्यों ने जो हमें चिट्ठियाँ लिखी हैं उनके सिलसिले में हम इसी महीने निर्णय करने वाले हैं कि कहां-कहां क्या हो सकता है। आपका पत्र मुझे मिला है, उस पर हम पोजिटिवली विचार कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जसबन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह किस सदस्य की कांस्टीच्यूएंसि है?

श्री अरुण कुमार मेहता : वह मेरी कांस्टीच्यूएंसि है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, समुद्र के किनारे पर्यटन स्थल के विकास की बात हो रही है। मैं कभी कोंकण गई थी वहां के लोगों में एक प्रकार का भय का वातावरण स्थापित है, वह ठीक है कि विकास होना चाहिए और लोगों को भी इससे सहायता मिलती है, लेकिन कुछ स्थान

ऐसे हैं जहां पर यह कुटीर बनाई गई हैं वहां पर ऐसी अवांछनीय बातें भी जुड़ जाती हैं जिससे वहां की मूल संस्कृति पर आघात होगा है। क्या इस तरफ भी सरकार का ध्यान है कि इस पर कंसे नियंत्रण रखा जाये ? गणपति कुटीर है वहां पर भी ऐसी बातें होती हैं, वह एक धार्मिक स्थान है, लेकिन कोंकण के लोगों में मय है कि अगर इस प्रकार की गलत संस्कृति पनपेगी तो उनकी मूल संस्कृति पर आघात होगा।

श्री सत्यपाल मलिक : अगर मैं सवाल को सही समझा हूं तो यह निवेदन करना चाहूंगा चाहे कोंकण के बीचों में या गोवा के हों, इस तरह की चीजें हमारे नोटिस में आती रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए असाधारण हैं, लेकिन उनके लिए साधारण हैं इसने हमें दिक्कत होती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम विदेशों से ऐसे पर्यटकों की पहचान करें और उनको लायें जो हमारी संस्कृति के विपरीत न हों। आपने जो कहा है उस तथ्य की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं और सम्मानत तथा सुरुचिपूर्ण पर्यटकों को विदेशों से लायें इसकी पहचान कर रहे हैं। वैसे यह मानकर चलना चाहिए कि जो बातें हैं उनके लिए तो साधारण-सी चीजें हैं लेकिन हमारे लिए वह असाधारण हैं।

श्री बोलसराब सोनूजी अहेर : मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में किन-किन जगहों को पर्यटन स्थल की दृष्टि से विकास करने की योजनाएँ केन्द्रीय सरकार को सातवीं योजना के अन्दर भेजी हैं और कितनी आपने बिलपर की है और यह भी बतायें कि आठवीं योजना में कितनी ऐसी योजनाएँ हैं ? क्या उसमें अजंजनेरी सापुतारा और त्रिबक भी है और इसका ब्योरा क्या है ?

श्री सत्यपाल मलिक : सातवीं योजना में केन्द्र की तरफ से जो योजनाएँ मंजूर की गई थीं उनका ब्योरा मैं दे देता हूं। यह सदन के पटल पर भी रखा गया है। अभी तक जो हमने आईडेंटिफाई की है वह मैं बता देता हूं। उसमें लाटूर में यात्री निवास की स्कीम है टेंटिड अचोमोडेशन की। टूरिस्ट काम्प्लेक्स कोडन नगर, वाटर एण्ड इक्विपमेंट्स विजिटर्स सेंटर औरंगाबाद, फरल क्राफ्ट सेंटर पुणे टूरिस्ट सेंटर पाथेलराम कंधामलन, एनिफैंटा और बम्बई के बीच हार्बर कृत्रिम के लिए भी इन्तजाम करना है। इनकी पहचान महाराष्ट्र सरकार ने हम लोगों के साथ बैठकर की है, लेकिन अभी इनका एस्टीमेट तैयार नहीं हुआ है।

कुमारी उमा भारती : छत्रपुर जिले में खजुराहो एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और वहां पर दिल्ली से बोईंग जाता है जो कि बनारस तक जाता है। वहां सरकार की तरफ से आपके विभाग का एक छोटा-सा कार्यालय था। कुछ दिनों पूर्व वह कार्यालय बन्द कर दिया गया है, पता नहीं किन कारणों से बन्द किया है। क्या आपको इसके सम्बन्ध में जानकारी है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान से पर्यटन कार्यालय बन्द किया गया और अभी वह बन्द है, क्या इसको खुलवाने का आपका विचार है ?

श्री सत्यपाल मलिक : यह बेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसकी जानकारी दी है। मैं एक सम्बन्ध में बात करूंगा।

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, पहले भी यहाँ टूरिज्म का मामला आया था। अण्डमान निकोबार आईलैंड और गुजरात की बात भी यहाँ आयी थी। हर वक्त सरकार यह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फण्डज नहीं है, बजट नहीं है, तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे रेलवे के पास पैसा नहीं था, तो उसने कम्पनी बनाकर लोगों से पैसा इकट्ठा किया, क्या वैसे कोई कम्पनी बनाकर सारे हिन्दुस्तान में जहाँ हो सके, वहाँ टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पैसा इकट्ठा करने के आईडिये पर सरकार विचार कर रही है या करेगी।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार नेह्रू : विभिन्न राज्यों के बहुत से सदस्य पर्यटक सुविधाओं के विकास के बारे में प्रश्न पूछते रहे हैं। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी कुछ थोड़ी सूचना देना चाहता हूँ।

कुल मिलाकर भारत में हमारे पास लगभग 30 मिलियन पर्यटक हैं, उसमें से 1.5 मिलियन पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं और 28.5 मिलियन पर्यटक घरेलू पर्यटक हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे हैं सभी राज्यों के लिये, घरेलू पर्यटन और विदेशी पर्यटन के लिये आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने का हमारा आशय है। बहुत से मामलों में, आधारभूत सुविधाएं एक जैसी हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ वह यह है केन्द्रीय सरकार के पास जो इसके लिये धनराशि है वह बहुत ही सीमित है।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामोर : मैंने प्रश्न हिन्दी में बोला है, उसका हिन्दी में जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी चाहें तो इंगलिश में बोल सकते हैं। ईयरफोन है उससे हिन्दी में सुन सकते हैं। आप भाषा का सवाल मत उठाएं।

श्री अरुण कुमार नेह्रू : आपको ईयरफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जवाब हिन्दी में देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हिन्दी में बोल रहे हैं।

श्री अरुण कुमार नेह्रू : तो प्रदेशों की जितनी सरकारें हैं, उनके अपने बजट होते हैं और उनकी टूरिज्म की जितनी भी योजनाएं यहाँ आएंगी उसकी सपोर्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मगर इस वक्त सातवाँ प्लान के पूरे प्लान में 70 करोड़ रुपये का एलोकेशन है जिसमें 16 करोड़ स्टेट्स को जाता है। तो जो भी योजनाएं बनती हैं, वे स्टेट लेवल से केन्द्रीय सरकार के पास आएंगी। तब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने फण्डज हैं, उसके मुताबिक ही संकशब्द होंगी। अण्डमान निकोबार के विषय में हम लोग एक जांच करा रहे हैं कि वहाँ एक टूरिस्ट स्कीम बनाएँ लेकिन वहाँ पर एम्पाउरमेंट की प्रॉब्लम है और थोड़ी अन्य समस्याएं भी हैं। कृपि अण्डमान निकोबार में टूरिज्म

ज्यादा बढ़ गया है और हम भी चाहते हैं कि एक दूरिज्म स्थान बने, उसके लिये मबिध्य में पूरी तरह से इसको डेवसेप करने के लिये पूरी कोशिश करेंगे।

सरकार: क्षेत्र के बैंकों में नई लेखा पद्धति

[अनुवाद]

+

*989 श्री प्रकाश कोको गहमहू } ! क्या बिल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।
श्री ए० जे० रावबा

(क) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आंतरिक पर्यवेक्षण और नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने और उनके वार्षिक लेखाओं को "अधिक सुस्पष्ट" बनाने के लिये एक नई पद्धति तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भारत के नियन्त्रक तथा महासेखा परीक्षक के नियन्त्रणाधीन लाने के प्रस्ताव की जांच करें,

(घ) खाते तैयार करने में वार्षिक लेखाओं की नई पद्धति कितनी सुहायक होगी, और

(ङ) नई पद्धति कब तक लागू की जाएगी।

बिल मन्त्री (प्रो० जमु बच्छवते) : (क) से (ङ) एक विवरण समा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने की सुपरिभाषित शक्तियां निहित हैं।

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मेटों में अपने तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेख तैयार करते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इन फार्मेटों में, विभिन्न खर्चों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के लेखों में अधिक सुस्पष्टता प्रदान करेगी। इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं तैयार की जा रही हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, उनके लेखों की सेवा-

परीक्षा कम्पनी अभिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी कम्पनी की लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के वास्ते अर्हताप्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जानी होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सान की बांछनीयता की भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको गृहमन्ट्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह वह प्रश्न उठाने के लिए इसलिये जरूरत पड़ी कि जा बैंक हैं, उनके एकाउंट्स से कभी मामूम नहीं होता कि जो बैंकों की ओट ऑफ प्राफिटिंग्स एंड लॉस एकाउंट्स हैं, उसमें कौन से कर्ज हैं जो बैंक डेट से नहीं आने वाले हैं, इसके लिये रिजर्व बैंक क्या करना चाहती है और सरकार न इन फार्मेट में विभिन्न चरणों में संशोधन करने का निर्णय लिया है तो वे विभिन्न चरण कौन से हैं और उनमें कौन से प्वाइंट्स आते हैं ?

प्रो० मधु बण्डवले : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बयान दिया है उसमें बताया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत जो तीसरा शेड्यूल है, उसके मुताबिक आज तक सारे बैंकों के एकाउंट्स के फार्मेट बनाये जाते हैं लेकिन एक बोच कमेटी बनाई थी जिसका माननीय सदस्य ने जिज्ञा किया है और बोच कमेटी ने भी उसका जिक्र किया था। उस कमेटी की राय रही कि जो लोग अपना डिपॉजिट बैंक में रखते हैं और आजाद हिन्दुस्तान में जनतांत्रिक हिन्दुस्तान में यह जरूरी है कि एकाउंट्स के सारे डिटेल्स लोगों के सामने आने चाहिये। बैंकों के एकाउंट्स के सिलसिले में चंद बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिनके बारे में सब जगह जानकारी फैलती है। इसलिये इन बातों में ज्यादा खुलापन होना चाहिये कि एकाउंट्स की पूरी आमदनी क्या है, बैंक डेट्स कितनी हुई हैं ? साथ ही साथ फार्मेट में यह जानकारी या मालूमता भी होना चाहिये कि कितन लोगों को कसेशन दिया गया है ? इस प्रकार के सुझाव बोच कमेटी की तरफ से रहे गये हैं। कर्नलमेंट रिजर्व बैंक के लोगों के साथ चर्चा करके उसके बारे में अंतिम फैसला करेगी।

श्री प्रकाश कोको गृहमन्ट्र : अध्यक्ष महोदय, पहले से बैंकों की कार्यक्षमता घट रही है और करप्शन बढ़ रहा है। इस करप्शन को घटाने के लिए रिजर्व बैंक क्या कार्रवाई करेगी और सरकार इस करप्शन को कब तक खत्म कर देगी ?

प्रो० मधु बण्डवले : अध्यक्ष जी, यह सवाल बैंकों के एकाउंट के फोरमेट के सिलसिले में है लेकिन चूंकि उन्होंने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि फोरमेट में जिस परिवर्तन की बात हम सोच रहे हैं, उसका तात्पर्य भी भ्रष्टाचार रोकने के साथ हो सकता है और हम सब प्रकार की कार्यवाही करेंगे जिसका वजह से भ्रष्टाचार कम हो जाये। भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले दिनों एक लेख आया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग धांधली करना चाहते हैं बैंकों के अन्दर, उन्हें पता सब क्या है कि रोबरी या बंकोप्टी करने से फंड करना ज्यादा फायदेमंद है। मैं समझता हूं कि इसे ध्यान में रखते हुए हम उचित कार्यवाही करेंगे। नियमों में आवश्यक तबदीली करेंगे, फोरमेट में उचित तबदीली करेंगे, जिसका हमें भ्रष्टाचार के ख़िलाफ कार्यवाही करने में फायदा मिलेगा।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर वेद की श्रुतियों का प्रसारण

* 90. रास्ता सिंह राखत : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले श्राव्य कालीन भक्ति संगीत कार्यक्रमों में वेदों की श्रुतियों को भी शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनसाधारण के लिए वेदों के महत्व के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री (श्री पी० उदयशर्मा) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कुछ आकाशवाणी केन्द्रों के भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में वेद पाठ होता है। दूरदर्शन के श्राव्य कालीन प्रसारण में उप-शास्त्रीय या शास्त्रीय शैली में भक्ति गीत भी प्रसारित किये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। और

(घ) जी नहीं।

श्री० रास्ता सिंह राखत : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की 86 प्रतिशत से अधिक जनता वेदों के प्रति असीम आस्था रखती है। वेदों के प्रथम उन्नावक और राष्ट्रीयता के प्रथम उद्घोषक महर्षि व्यासजी सरस्वती ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं। योगीराज अरुण ने भी इस बात को स्वीकार किया था। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परम्पराएं हमारी प्राचीनता, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा संगीत, सब वेदों से निकला है। उन वेदों की श्रुतियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर यदि महत्व न दिया जाये तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्रालय को अवगत है कि वेद का शब्दार्थ ज्ञान ही की पुस्तक है ? क्या यह तथ्य नहीं कि वेद के महत्व को एक धार्मिक ग्रन्थ के अतिरिक्त ज्ञान के एक स्रोत के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी है ? इसी मान्यता के आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री० रास्ता सिंह राखत : इस मान्यता के फलस्वरूप क्या मन्त्रालय का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वेदों में 'महति ज्ञान की लोको तक पहुँचावे ? क्या ऐसा करना इस कारण भी आवश्यक नहीं होता कि वेद हमारे देश की कई सांस्कृतिक धारों का उद्गम है ?

[अनुवाद]

श्री पी० उदयशर्मा : नीति सम्बन्धी मामलों के अनुसार, आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने केन्द्रों

से कर्मकाण्डी धार्मिक प्रसारणों को प्रोत्साहन नहीं देते। तथापि, अपनी नीति के अनुसार में, इन कार्यक्रमों से लोगों के नैतिक चरित्र को मजबूत करने में सहायता मिलती है इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन लोगों और भारत के सभी वर्गों के अनुयायियों के अनुमंड एकर करते हैं और पवित्र साहित्यों के उद्देश्यों का उपयोग करते हैं। इस प्रयास को संगीत और गाने जाने वाले कार्यक्रमों में दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : वेदों का प्रसारण जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए क्या वैदिक कालीन सौन्दर्य, वैदिक संगीत, वैदिक गणित, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक स्वापस्य कला और वैदिक विज्ञान के बारे में जनता को जानकारी दिलाये जाने की दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से व्यवस्था नहीं की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इन सबको प्रसारित नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से कार्यक्रमों में, उप-शास्त्रीय और शास्त्रीय कार्यक्रमों में भक्ति संगीत दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण बडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो जवाब आया है, उसमें माननीय मंत्री जी ने इसके प्रति अपनी इच्छा तो प्रकट की है और यह जानकर प्रसन्नता भी होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से बेबपाठ के कार्यक्रमों के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उत्तर में आये यह भी कहा गया है कि दूरदर्शन के प्रसारणों में शास्त्रीय संगीत भी प्रसारित किया जाता है, शास्त्रीय शैली में भक्ति गीत प्रसारित होते हैं, परन्तु वेदों में जो ज्ञान की बातें हैं, वेदों में शिक्षा भरी है, वह सबमाम्य है और उससे किसी का विरोध नहीं हो सकता।

“ओं विश्वानिदेवः सवितुर्दरितानि परासुव। यद् मद्रं तन्नमासुव।”

हे सर्वशान्तिमान परमेश्वर सब लोगों के दुःख दूर करके सबको सुखी और समृद्ध कर। इस बात से किसी का विरोध नहीं हो सकता। ऐसी बातें जो हैं जो ज्ञान की, विज्ञान की, उनको यदि प्रकट करने के लिये सूक्तियों के रूप में प्रकट करने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाने में क्या हर्ज है। इससे तो वेद के ज्ञान और शिक्षा को प्रसारित करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि ऐसी सूक्ती और छोटी-छोटी पंक्तियों को उद्धृत करने और ऐसी शिक्षा को प्रसारित करने में आप दूरदर्शन का उपयोग करेंगे क्या ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : आकाशवाणी के कुछ केन्द्र प्रतिदिन नियमित रूप से नहीं बरिफ कमी-कमी

वेदों से श्लोक देते हैं। मेरा पहले का उत्तर भी केवल दैनिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। लेकिन जब कभी ऐसे अवसर आते हैं तो कभी-कभी ये कार्यक्रम भी दिये जाते हैं।

श्रीमती गीता मुक्कर्जी : स्वभाविक है यदि वेदों के सूत्रों को भी लोकप्रिय बनाया जाता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये ऐसे सूत्र होना चाहिए जो कि हमारे संविधान और नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाते हों। यहां और भी धर्म हैं। उनकी भी ऐसी ही अपीलें हैं। जब सरकार धार्मिक बातों को लेगी, क्या वे इन दोनों पहलुओं पर विचार करेगी और अकेले तुम पर विचार करने के बाद क्या वे कोई बात निश्चित करेगे ?

श्री पी० ज्येष्ठ : जैसा कि मैंने बताया है मथुरा, पांडिचेरी, धारवाड़ जैसे कुछ केन्द्र कभी-कभी वेदों के श्लोक प्रसारित करते हैं। इसी प्रकार आकाशवाणी के हैदराबाद और ब्रिजगर केन्द्र कुरान शरीफ में पाठ प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी का जालंधर केन्द्र और दूरदर्शन गुरुवाणी में उद्धारण रेडियो और दूरदर्शन में प्रसारित करते हैं। और जब कभी ईसाइयों के त्यौहार आते हैं, धार्मिक व्रन्दावन भी रेडियो और दूरदर्शन में प्रसारित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री कपिलदेव शास्त्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वेद सारे संसार का आदिम ज्ञान है। सारा संसार इस बात को मानता है कि वेद के पहले कोई पुस्तक, ऋचा इस दुनिया में नहीं आई। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जब वेद दुनिया का आदिम ज्ञान है और सारे धर्म उससे ज्ञान अधि-गृहीत करते हैं, तो वेद की ऋचाओं को बोलने में, इस दूरदर्शन को और आकाशवाणी को परहेज क्यों है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ज्येष्ठ : हमारी ओर से कोई हिचक नहीं है। इन्हें कभी-कभी अवसर के अनुसार रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस वेद को विश्व के अन्य देश मानते हैं और जिसमें से कम्प्यूटर साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं, वेद की ऋचाओं के आधार पर जर्मनी और अन्य देशों में शोध हो रहे हैं और उसी वेद को यह देश छोड़ दे, यह तो मुझे उचित नहीं लगता है। वेद जैसा ग्रन्थ जो ज्ञान का भण्डार है, उस ज्ञान को क्या मन्त्री जी देश के 80 करोड़ लोगों को नहीं देना चाहते हैं ? इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वेद की ऋचाओं के अनुवाद और ऋचाएं सबको सुनाई जाएं, जिससे देश के लोगों का ज्ञान बढ़े, इस बारे में देश क्या कर रहे हैं और क्या विचार है ?

[अनुक्रम]

श्री पी० उपेन्द्र : मैं उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। इसमें कोई हिचक अथवा अनिच्छा नहीं है। लेकिन नीति के अनुसार हम इसे प्रतिदिन प्रसारित नहीं कर रहे हैं।

श्री ए० के० राय : वेदों में दो प्रकार के श्लोक हैं—एक में किसी देवता की प्रशंसा की गई है और दूसरे में प्रकृति की प्रशंसा की गई है। वास्तविकता का तत्त्व भी वहाँ है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सभी बमों और इन सभी बातों को प्रसारित करते समय क्या वह वास्तविकता के तत्त्वों का भी प्रसारण करेंगे जो कि उनमें है।

श्री पी० उपेन्द्र : यह कार्यवाही किए जाने के लिए एक सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट

*991. श्री मित्रसेन यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा कुछ समय पूर्व प्रस्तुत की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार की सिफारिश-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ये सिफारिशें कितनी लाभ-दायक होंगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल बलिक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन समिति की प्रमुख सिफारिशों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया नीचे दी गई :—

क्रम सं०	सिफारिशें	सरकार की प्रतिक्रिया
(1)	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों में सरकार की पूर्ण निवेश को आकर्षित करने के लिए एकमुस्त नीति	सामान्य रूप में स्वीकृत और कार्य-म्वित

- (2) पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन कर दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम का राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम में पुनर्गठित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। पर्यटन विभाग को पुनर्गठित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- (3) वायु और मृ-परिवहन क्षमता में तेजी से वृद्धि करने हेतु नीति इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का आंशिक निजीकरण करने की सिफारिश को छोड़ कर सामान्य रूप में स्वीकार किया गया।

(ग) ये सिफारिशें पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए उपयोगी हैं और इनके द्वारा स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी।

अनिवासी भारतीय

*992. श्री बमेश प्रसाद वर्मा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्रीमती वसुंधरा राजे }

(क) विश्व भर में देश-वार कितने अनिवासी भारतीय हैं और उनके द्वारा भारतीय बैंकों में जमा कराई गई विदेशी मुद्रा सहित अन्य क्षेत्रों में अब तक कितना-कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना में अनिवासी भारतीयों से अधिकाधिक पूंजी निवेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बण्डवते) : (क) अनिवासी भारतीयों के संबंध में कोई विशिष्ट जन-गणना उपलब्ध नहीं है। 31.1.1990 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए कुल निवेशों की राशि संक्षेप रूप से लगभग 19,000 करोड़ रुपए थी जिसमें बैंक जमा राशियां शामिल हैं।

(ख) अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और प्रोत्साहन देना सरकार की नीति रही है।

इंडो इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड का प्रस्ताव

*993. श्री प्रकाश कोको कल्लुकरु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्स्ट इंडो-इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड के माध्यम से इक्विटी और अनिवासी भारतीयों की जमा राशि देश में आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसमें से कितनी छनराशि गैर-प्रत्यावर्तनीय होगी;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में इंडो-एन०आर०आई० नैम्बर आफ कामर्स एण्ड कल्चर के अध्यक्ष द्वारा किए प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो फर्स्ट इंडो-इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड के प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बण्डवले) : (क) से (च) नवम्बर, 1988 में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम इंडो-इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड नसाऊ, बाहामास, ने अनिवासी भारतीय निवेशों निक्षेपों को आकर्षित करने के लिए बम्बई में एक शाखा खोलने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से जुलाई, 1989 में सम्पर्क किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक के प्रार्थना-पत्र पर अनुकूल रुख नहीं अपनाया। अब बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने की प्रार्थना की है।

कन्याकुमारी में पर्यटन केन्द्र की स्थापना

*994. श्री एन. डेनिस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जापान के सहयोग से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पर्यटन केन्द्र की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल बलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

‘स्मरणिम ज्ञान व राहुज’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार

995. श्री कन्यारी ज्ञान पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तस्करी के विरुद्ध कार्यरत विभिन्न संगठनों के अनुसार पिछले एक दशक से तस्करी की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है जैसा कि 28 और 29 अप्रैल, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या गुप्तचर विभाग द्वारा तस्करी के विरुद्ध कार्यरत विभिन्न संगठनों के सहयोग से सितम्बर, 1989 में तैयार की गई रिपोर्ट की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का व्यौरा क्या है; और सरकार का तस्करी के विरुद्ध कार्यरत संगठनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है।

बिस्म मंत्री (प्रो० जगु बंडवले) : (क) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पिछले दशक के दौरान तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं तथा यदि हुई है, तो किस सीमा तक। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किए गए अभियानों के मूल्य से, जिन्हें नीचे सारणी में दर्शाया गया है, बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह जरूरी नहीं है कि इससे तस्करी में वृद्धि होने का पता चलता हो, परन्तु ऐसा तस्करी रोधी प्रयासों को तेज करने से भी हो सकता है।

सारणी

वर्ष	अभियानों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1	2
1985	195.63
1986	217.52
1987	251.47
1988	443.14
1989	554.59
1990 (अप्रैल तक)	223.38 (अनन्तिम)

(ख) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन किसी भी आसूचना एजेंसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों, दस्तकारों और बुनकरों के ऋण माफ़ करवा :

*996. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से उन किसानों, दस्तकारों और बुनकरों को, जिन्होंने विभिन्न बैंकों से 10,000 रुपये तक के ऋण लिये हैं, ऋण माफ़ करने हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस योजना को कब तक तैयार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बंडोपत) : (क) से (ग) सरकार ने उन किसानों, कारीगरों और बुनकरों को ऋण राहत देने के निर्णय की घोषणा की है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से 10,000 रुपये तक का ऋण लिया था। सरकार ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 तैयार की है। योजना की मुख्य बातें अनुबंध में दी गई हैं।

केन्द्रीय सरकार की कृषि तथा ऋण राहत योजना 1990, की मुख्य-मुख्य बातें

1. यह राहत 2 अक्टूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों सहित सहकारी समितियों द्वारा दिए गए सभी अल्पावधि और सावधि अतिदेय राशियों पर लागू होगी।

2. यह राहत उन सभी उधारकर्ताओं को प्राप्त होगी, जिनके द्वारा एक या अधिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या सहकारी समितियों से लिए गए मूलधन की रकम 10,000 रुपये से अधिक नहीं है।

3. मूलधन और ब्याज की रकम की माफ़ी केवल 10,000 रुपये की सीमा तक ही प्राप्त होगी।

4. ऋण राहत का लाभ निम्नलिखित उधारकर्ताओं के वर्गों को प्राप्त होगा :—

(क) जानबूझकर ऋण न करने वाला वह किसान जो गांव के आबार पर लागू आनावरी प्रणाली के अंतर्गत आता है—

(ख) जानबूझकर ऋण न करने वाला वह कारीगर/बुनकर जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने ऋण की वापसी अदायगी करने में ऋण की है।

(ग) ऋण करने वाले उन किसानों, कारीगरों और बुनकरों की "पुरानी अतिदेय राशियां"

जो अन्तिम (कर आक) तारीख अर्कित 1-10-1989 को पिछले तीन वर्षों से अदा न की गई हो।

(ब) मृत उधारकर्ता के परिवार के उत्तरजीवी सदस्य, जिन पर ऋण का दायित्व आता हो।

(ङ) वे किसान जिन्होंने दिवालियापन की याचिका दायर कर दी थी या जिसे पहले ही दिवालिया घोषित कर दिया गया हो और जो ऊपर लिखी शर्तें पूरी करता हो।

5. उधारकर्ताओं की पहचान और पात्र ऋणों का निर्णय सरकारी क्षेत्र के बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रत्येक शाखा के प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। उसे इस स्कीम के अंतर्गत पहचान किए गए और माने गए उधारकर्ता को राहत मंजूर करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. प्रत्येक खण्ड में अग्रणी बैंक का प्रबंधक योजना के कार्यान्वयन के लिये समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और वह प्रत्येक उधारकर्ता द्वारा किए गए ऋण के कुल मूलधन की रकम का निर्धारण करने तथा योजना से सम्बद्ध अन्य शर्तों की जाँच करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कन्द्रीय सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों की सम्बन्धित शाखाओं के प्रबन्धकों और खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार की बैठकें बुलाएगा।

7. शाखा प्रबंधक उधारकर्ता को दी गई राहत की रकम और यदि उसके खाते का पूर्ण रूप से निपटारा हो गया हो तो खाते के बन्द किए जाने की सूचना लिखित रूप में भेजेगा और जहाँ कहीं लागू हो वहाँ बकाया रकम का मुग्तान भी करेगा।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर में महिला कर्मचारियों

*997. श्री ए.बी. थोरड : क्या इत्याद और ज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विच्छेद की गई शिकायतों की जानकारी है जिसमें उन पर महिला कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन शिकायतों की जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम प्राप्त हुए और इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

इत्याद और ज्ञान मंत्री तथा बिबि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सरकार को इस प्रकार की शिकायतों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

998. श्री कुसुम कुण्डन मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक अपनी-अपनी राय दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इनके बारे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या विचार व्यक्त किये हैं और सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें कार्यान्वित करने के बारे में कार्य योजना क्या है; और

(ग) समिति की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बंधनते) : (क) से (ग) कृषि ऋण संवीक्षा समिति (अध्यक्ष, प्रो० ए०एम० जामरो) ने देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की है और हाल में उसे प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों का मूल्यांकन किया है। समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं :—

- (1) कृषि अधिमों से सम्बन्धित व्याज दर ढांचा जटिल नहीं होना चाहिए और ऐसे ऋणों के रियायत की सीमा कम की जानी चाहिए।
- (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों में विलय कर दिया जाना चाहिए;
- (3) पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए;
- (4) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक का गठन किया जाना चाहिए; और
- (5) फसल बीमा निगम की स्थापना की जानी चाहिए।

ये सिफारिशें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विचाराधीन हैं।

एकल यूरोपीय बाजार का भारतीय व्यापार पर प्रभाव

*999. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय व्यापार पर एक यूरोपीय बाजार के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) एकल यूरोपीय बाजार की चुनौती से निपटने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीधरन) : (क) और (ख) जी, हाँ। भिन्न-भिन्न सरकारी और औद्योगिक संगठनों द्वारा विभिन्न अध्ययन करने के अतिरिक्त 5 राज्यों की एक समिति ने वर्ष 1992 तक भारतीय व्यापार पर यूरोपीय बाजार के एकीकरण के प्रभाव के आकलन का विस्तृत अध्ययन किया है।

(ग) यूरोप में उमरती हुई स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित उपायों का विस्तृत आकलन और अनुवर्तन, यूरोप में विकसित हो रहे नये मापदंडों का अनुवर्तन उद्योग और व्यापार मंचों के साथ अन्योन्यक्रिया, यूरोप में मण्डारण संवर्धन इत्यादि के प्रयास शामिल हैं।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

* 1000. श्री समरेन्द्र कुचडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा का बजट-घाटा पूरा करने और विशेष रूप से इस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे भारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो सस्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु बच्छावते) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि 1990-91 की वार्षिक योजना को पूर्णतः वित्त पोषित करने हेतु संसाधनों के अन्तराल को भरने के लिए विशेष ऋणों, अग्रिम योजना महायता इत्यादि के रूप में उड़ीसा सरकार के लिए अतिरिक्त ऋण व्यवस्था की जाए। उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के पास लंबित पड़े मृत्यु-दावे

* 1001. श्री लाल कुण्डू झाड़बाणी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री कल्पनाच सोनकर }

(क) जीवन बीमा निगम के पास लंबित पड़े मृत्यु दावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने दावे पांच वर्ष तथा उससे अधिक समय से लंबित पड़े हैं; और

(ग) जिन विद्यवाओं के बच्चे बड़े नहीं हैं, उनके घर पर ही इन दावों की राशि के मुसतान की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, ताकि उनको इस दुःख की दृष्टि में हजर-खजर माप-बौद न करनी पड़े ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु वण्डवते) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1989 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के पास बकाया रहते मृत्यु सम्बन्धी दावों की संख्या 14456 थी, जिनमें से 826 मृत्यु सम्बन्धी दावे 2 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थे जो 28 फरवरी, 1990 को और कम होकर 412 रह गए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम उन मृत्यु सम्बन्धी दावों के पृथक आंकड़े नहीं रखता है जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से बकाया हैं। निगम मृत्यु सम्बन्धी दावों के राज्यवार आंकड़े भी नहीं रखता है। तथापि, क्षेत्रवार आंकड़े पृथक रूप से रखे जाते हैं जिनमें सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जो 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार निम्ना-नुसार हैं :—

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.89 को बकाया मृत्यु संबंधी दावे	31.3.89 को 2 वर्ष से अधिक बकाया मृत्यु सम्बन्धी दावे
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली, राजस्थान, चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश	1957	83
केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	1701	61
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, मिझोरम, अण्डमान और निकोबार, नागालैण्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर	1639	42
दक्षिणी क्षेत्र	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश पांडिचेरी और लक्षद्वीप	4635	248
पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ, दादरा और नगर हवेली तथा अडमान और दीव	4624	392
निगम का जोड़ :—		14456	826

(ग) कठिन मामलों अर्थात् हक या अन्य कानूनी विवाद वाले मामलों की छोड़कर सामान्यतः सभी मृत्यु सम्बन्धी दावों का 2 वर्ष की अवधि के अंदर निपटारा हो जाता है। निगम, मृत्यु की सूचना के 75 दिन के अंदर मृत्यु सम्बन्धी अधिकतम दावों का निपटारा करने का प्रयत्न करता है।

परन्तु, जल्दी मृत्यु सम्बन्धी दावों के सम्बन्ध में जहाँ पर जांच-पड़ताल और अधिक अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक हो वहाँ दावों का निपटान मृत्यु की सूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर करने के प्रयत्न किए जाते हैं। दावों के शीघ्र निपटान के लिए एजेंटों, विकास अधिकारियों और सेवा (सर्विसिंग) शाखा के कर्मचारियों द्वारा, सभी अपेक्षाएँ पूरी कराने में दावेदारों की हर सम्भव सहायता की जाती है। इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा नियम के पास दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक उचित पद्धति है।

एशियाई विकास बैंक की ऋण सम्बन्धी रिपोर्टें

*1002. श्री एम. बी. चण्डेश्वर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशियाई विकास बैंक से भारत के विदेशी ऋण के बारे में विस्तृत रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक से कतिपय आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करने का सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अपेक्षित आंकड़े एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में खनिजों का बिबोहण

*1003. बसन्त साठे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने महाराष्ट्र में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में विभिन्न खनिज भण्डारों में खनिजों की अलग-अलग कितनी मात्रा होने का अनुमान है और 31 मार्च 1990 तक ग.१ तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में खनिज निकाले गए और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय और राज्य/भार सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग वर्ष 1990-91 के दौरान खनिजों के लिए क्या कन्वेंशन-सौकर किया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में खनिज कार्य के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता मांगी/प्राप्त की गई है; और

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिजि और म्याप मंत्री (बी विनेश मोस्वाजी) : (क) महाराष्ट्र में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, महाराष्ट्र राज्य भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय तथा अन्य केन्द्रीय/सरकारी एजेंसियों ने सर्वे किया है।

(ख) मण्डार इस प्रकार हैं :—

(मिलियन टनों में)

बाक्साइट	—	87.721
चीना मिट्टी	—	3.258
कोयला	—	5,075.40
तांबे का अयस्क	—	0.141
डोलोमाइट	—	217.102
फायर क्ले	—	5.437
लौह अयस्क (हेमेटाइट)	—	181.550
मैंगनीज अयस्क	—	5.161
इल्मेनाइट (बालू)	—	4.129
काइनाइट और सिलिमिनाइट	—	0.960
बूना पत्थर	—	3,455.572
टंगस्टन अयस्क	—	6.606

वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान खनिज खनिजों की मात्रा उनके मूल्य इस प्रकार हैं :—

(उत्पादन लाख टनों में एवं मूल्य लाख रुपये में)

खनिज	वर्ष 1987		वर्ष 1988		वर्ष 1989	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
कोयला	108.88	23277.85	118.76	25275.86	117.19	31676.02
बूनापत्थर	31.62	921.25	44.99	1349.22	36.47	1303.96
मैंगनीज अयस्क	2.35	1064.90	2.51	946.67	1.71	796.41

1	2	3	4	5	6	7
लौह अयस्क	9.33	313.73	5.24	305.55	11.17	642 85
बाक्साइट	4.01	168.54	5.59	275.44	5.27	271.69
सिलिका रेत	1.67	70.44	1.76	73.72	1.67	100.93
डोलोमाइट	0.30	15.37	0.25	16.59	0.19	11.21
काइनाइट	0.11	31.07	0.15	42.32	0.20	63 98
सिलिमैनाइट	0.08	76.22	0.06	60.20	0.10	89.55
मरई रेत	12.03	39.37	9.18	78.41	12.43	189 88
कोरंडम	00.02	1.25	0.006	3.91	0.0009	0.54
फाइरो-फिलाइट	0.02	1.29	0.009	0.60	0.009	0.58
क्रोमाइट	0.0009	0.60	0.002	1.35	शून्य	शून्य
मिट्टी	0.14	5.02	0.13	5.39	0.14	5.02
क्वार्ट्ज	0.07	3.66	0.20	11.51	0.16	9.99
सेटेराइट	0.57	34.64	0.64	33.60	0.67	46.31
शेल	0.15	1.17	0.20	1.54	0.06	0.47
कुल जोड़	171.33	36026.55	189.67	28486.88	187.43	35209.39

*वर्ष 1989 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सेंटर राज्य/प्राइवेट सेंटर में क्षमताओं के समन का कार्यक्रम इस प्रकार है:—

सेक्टर	क्षमता	संगठन	उत्पादन लक्ष्य (टन में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
केन्द्रीय	मैंगनीज अयस्क	मैंगनीज ओर (इ०) लि०	2,56,000	
	कोयला	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि०	1,70,00,000	

1	2	3	4
राज्य	काइनाइट सिलिमिनाइट	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,000
	कोरंडम आदि		
	डोलोमाइट	—वही—	25,000
	चूनापत्थर	—वही—	20,000
	फसोराइट	—वही—	5,000
	सिलिका बालू	—वही—	15,000
प्राइवेट	बाक्स:इट	इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी	6,00,000
	लौह अयस्क	—वही—	5,00,000
			लौह अयस्क के निर्यात के अनुसार आंकड़े घट-बढ़ सकते हैं
	चूनापत्थर	—वही—	35,00,000

(ख) 12 मई, 1988 को खनिज गवेषण निगम और फ्रांस की खनिज गवेषण एजेंसी बी०आर०जी०एस०एम० के बीच एक करार हुआ है, जिसके अन्तर्गत खनिज गवेषण प्रौद्योगिकी के अन्तरण द्वारा भारत में टिन व टंगस्टन निक्षेपों के गवेषण और विकास हेतु एक संयुक्त परियोजना का क्रियान्वयन होना है। इस परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में नागपुर जिले के खोबना टंगस्टन निक्षेप शामिल हैं।

(ङ) टंगस्टन अयस्क पिंड के आन्वेषीकृत जोन के मूल्यांकन हेतु, संयुक्त कार्यदल की यथा-समर्थन गवेषणी द्रिस्तिक का काम चल रहा है।

नई आयात-निर्यात नीति के विषय केरल से अभ्यावेदन

•1004. प्रो० पी.जे. कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति के विषय केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीवरन) : (क) जी, हाँ।

(ख) अमिवेदन के मुख्य मुद्दे यह थे कि नारियल-तेल, गरी, प्राकृतिक रबड़, कयर यार्न, कोका और मसाले जैसे कृषि और बागान उत्पादों के सन्वर्धन में नई आयात-निर्यात नीति का केरल के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) जायफल और जावित्री को छोड़कर उपयुक्त मदों के लिए आयात-निर्यात नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी व्यक्तियों के लिए इन दोनों मदों के स्टॉक और बिज्जी के लिए आयात की अनुमति पहले खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दी गई थी, नई आयात-निर्यात नीति में इन्हें लाइसेंस श्रेणी में इन मदों के आयात को और कड़ा कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान ज्विक लिमिटेड, उदयपुर के अवालती मामले

*1005. श्री केशव मेघवाल : क्या इस्पात और लौह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ज्विक लिमिटेड, उदयपुर और इसके विभिन्न एककों द्वारा दायर किये गये और उनके विरुद्ध दायर किए गए, श्रमिक कानूनों से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर अन्य कितने मुकदमे निम्न, उच्च और उच्चतम न्यायालयों में अनिश्चित पड़े हैं और इन मुकदमों में पक्षकार कौन-कौन हैं तथा सम्बद्ध कारण क्या हैं;

(ख) ये मुकदमे कब से लम्बित हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विवादों को सम्बन्धित पक्षों के साथ आपसी समझौते से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और लौह मंत्री तथा बिधि और न्याय मन्त्री (श्री विमल गोस्वामी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1150/90]

(ग) न्यायालयों के बाहर मामलों के निपटाने के बारे में प्राप्त अनुरोधों पर कम्पनी के हितों को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है।

मंत्रालयों, विभागों में पदोन्नति में गतिरोध

*1006. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में समूह "ग" और "घ" के पदों में पदोन्नति में भारी गतिरोध है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक विशिष्ट अवधि के पश्चात् समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में स्वतः पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी म्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक लागू किया जाएगा ?

बिला मंत्री (प्रो. मधु बण्णवते) : (क) सरकार इस बात को जानती है कि समूह "ग" और "ब" पदों में कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनमें पदोन्नति के अवसर नहीं हैं या पदोन्नति के आधार अपर्याप्त हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार में विभिन्न स्तरों पर पदों का सृजन आवश्यकता के आधार पर विचार करके किया जाता है। यदि पदोन्नति के स्तरों में पद कार्यात्मक रूप से औचित्यपूर्ण/आवश्यक नहीं हैं तो ऐसे पद पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने तथा गतिरोध को दूर करने मात्र के लिए सृजित नहीं किए जा सकते। तथापि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष की मांग के आधार पर सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या समूह "ग" और "ब" के सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में कम से कम एक पदोन्नति दी जा सकती है।

मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड द्वारा बिज्जी

[हिन्दी]

*1007. प्रो. महाबेश शिबनकर : क्या इस्पात और ज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड ने गत वर्ष एक कम्पनी को विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी कम मूल्य पर मैंगनीज अवस्क बेचा था,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) क्या "मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड" के कर्मचारी-कल्याण संघ से कोई ऐसा आपन प्राप्त हुआ था, जिसमें उभ्र सौदे में कदाचार होने का आरोप लगाया गया था,

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त आरोपों की जांच की गई है, और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या सुधारार्थक कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और ज्ञान मंत्री तथा बिज्जी और न्याय मंत्री (श्री बिनेस गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) आरोपों की जाँच की गई तथा इनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ।

भारत को जापानी सहायता

[अनुचाब]

10401. श्री प्रकाश बी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल में भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमन्त्री ने भारत के लिए द्विपक्षीय सहायता में थोड़ी वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) भारत के लिए आर्थिक सहायता के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) से (ग) जापान के प्रधानमन्त्री ने अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान यह संकेत दिया था कि जापान सरकार चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 160 अरब येन तक का ऋण प्रदान करने वाली है। यह पिछले वर्ष की गई 96.7 अरब येन की बचनबद्धता की तुलना में 3.29 अरब येन की वृद्धि प्रकट करती है।

बिहार में बंद रोलिंग मिल

10402. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में कौन-कौन सी रोलिंग मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी पूँजी अवरोध पड़ी है और कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिजि और ग्याय मंत्री (श्री विनोद गोस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही और समा पटल पर रख दी जाएगी।

रांची दूरदर्शन केन्द्र में अस्थायी कर्मचारी

[हिन्दी]

10403. श्री दीवानलाल प्रसाद वर्मा : क्या दूरदर्शन और प्रसारण मंत्री यह बतावेगी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र रांची में कुछ अस्थायी कर्मचारी इस केन्द्र के आरम्भ होने के समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन स्थायी नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थायी करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब और उन्हें मूलतम वेतन का सुवृत्तान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (जी. वी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां। जिन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा गया है, उनके स्थान पर नैमित्तिक आधार पर, कुछ कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है।

(स) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं। नियमों में नैमित्तिक कर्मचारियों को कब तक नियमित करने की व्यवस्था नहीं है जब तक वे नियमित नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता में नहीं बैठते।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में पोस्त की खेती

10404. श्री गुलाबबन्ध कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में पोस्ट की खेती करने वाले किसानों को "पट्टे" देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या पोस्ट की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक है और इससे बिबेसी मृदा की आय भी होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का पोस्ट का उत्पादन बढ़ाने का विचार है;

(क) क्या सरकार का राजस्थान में पोस्ट पर आधारित फैक्ट्री की स्थापना करने का विचार है; और

(ब) यदि हाँ, तो कब तक ?

विस्तार के साथ ही विस्तार में (विस्तार के साथ ही) : (क) से (ख) के लिए के लिए

उन किसानों को लाइसेंस अक्टूबर/नवम्बर में जारी किए जाते हैं जो सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। अफीम-पोस्त की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक साधन है और विदेशों को अफीम के निर्यात द्वारा भारत सरकार विदेशी मुद्रा भी अर्जित करती है। भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यतः निर्यातोन्मुखी है। भारतीय अफीम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी विकल्प कच्ची सामग्री, नामशः पोस्त के तिनकों के सांठण से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ अफीम के निर्यात में कमी आई है और इसको स्टॉक में वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार का अफीम के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कलकत्ता से बम्बई कार्य अन्तरित करना

[अनुवाद]

10405. श्री बसुदेब आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अंतर्जाली समन्वय कार्य, यात्री बैंक जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को कलकत्ता से बम्बई अन्तरित कर दिया है, जिनके परिणामस्वरूप रोजगार की सम्भावनाओं में कमी हुई है और पश्चिम बंगाल की आर्थिक महत्ता कम हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने उस समय की परिस्थितियों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में किये जा रहे कुछ कार्यों को काफी समय पहले कारोबार और प्रबन्धकीय कारणों से वहाँ से अन्तरित कर दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बताया है कि किसी और अनुभाग/काम के मद्द को कलकत्ता से अन्तरित करने का बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अनुभागों/कार्य की मदों को कलकत्ता से स्थानान्तरित/अन्तरित किए जाने के कारण बैंक के पश्चिम बंगाल में उपलब्ध रोजगार अवसरों में कोई कमी नहीं आई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का पुनर्गठन

10406. श्री ए. बिजय राघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों के पुनर्गठन की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो इन मंडलों का पुनर्गठन कब किया जायेगा ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अभिल साहनी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक मण्डलों का काम एक निरन्तर प्रक्रिया है और निदेशकों की होने वाली रिक्तियों को समय समय पर भरा जाता है। इस समय सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की कुछ रिक्तियाँ हैं। सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि पिछली नियुक्तियों की समीक्षा के बाद यथाशीघ्र इन रिक्तियों को भर लिया जाए।

अवाइंट विजेता निर्यात फनों को प्रोत्साहन

10407. श्री परसराम मारहाज : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेटेड बैंम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री आफ इंडिया ने अवाइंट विजेता निर्यात फनों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करने का सुझाव दिया है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जन करने में उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के कुल प्रसारण समय में विज्ञापनों के प्रसारण समय की प्रतिशतता

10408. डा० बेंकटेश काबड़े : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कुल प्रसारण समय में विज्ञापनों के प्रसारण समय की प्रतिशतता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन विज्ञापनों के प्रसारण से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार का दिवार दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) इन विज्ञापनों के प्रसारण का बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रारम्भ की गई योजना का ग्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उषेन्द्र) : (क) इस समय दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण की अवधि कुल प्रसारण समय का लगभग 3 प्रतिशत है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दूरदर्शन का कुल विज्ञापन राजस्व 507.69 करोड़ रुपए था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गत कुछ वर्षों में, दूरदर्शन-विज्ञापनों के सामाजिक प्रभाव पर, किए गए अध्ययन से यह पता चला कि ये विज्ञापन प्रायः रुचिकर, मनोरंजक तथा सूचनापरक हैं और इनका समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

केरल से सस्त्रियों का निर्यात

१०४०९. श्री सुस्तापल्ली रामचन्द्रन : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९८७/१९८८ और १९८९ के दौरान केरल से खाड़ी के देशों को कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की सस्त्रियां निर्यात की गई;

(ख) खाड़ी के देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए केरल के निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन/सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को एअर इन्डिया द्वारा केरल के निर्यातकों को त्रिवेन्द्रम, कीचीन कालीकट में आवंटित एअर मार्गों-क्षेत्र को कम किए जाने से विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुणिल श्रीधरन) (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल से खाड़ी देशों को निर्यात की गई सस्त्रियों की कुल मात्रा और कीमत नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा (एम टी) (अनुमानित)	मूल्य रु०/लाख (अनुमानित)
१९८७-८८	५२४२	३१०
१९८८-८९	५९६८	३५०
१९८९-९०	७१२०	४७७

स्रोत : केरल राज्य औद्योगिक इण्टरप्राइजेज लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम।

(ख) सभी निर्यातकों को, जिनमें केरल के निर्यातक भी शामिल हैं, ताजी सस्त्रियों का निर्यात बढ़ाने के लिए एकदम मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति आदि जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(घ) और (घ) कृषि उत्पाद और संसाधित खाद्य निर्यातक एसोसिएशन, त्रिवेन्द्रम ने एयर

इंडिया द्वारा निवेन्द्रम को आर्बिट्रि कारगो स्पेस को कम करने के विरुद्ध अभिवेदन दिया था। यह मामला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ उठाया गया था जिसने जानकारी दी है कि एयर इंडिया ने 15 अप्रैल, 1990 से इस कटौती को वापस ले लिया है।

विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए आप्रवासन औपचारिकताओं में रियायत

10410. श्री एम० एच० परल्लम राजू : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए लागू की गई आप्रवासन औपचारिकताओं में छूट के संवर्धन में मुख्य परिवर्तनों का ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए औपचारिकताएं कम करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल ललित) : (क) विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए आप्रवासन औपचारिकताओं में और ढील दिए जाने की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती क्योंकि सामान्यतया आप्रवासन काउंटर पर यात्रियों को बाहर निकालने में 2 मिनट से अधिक नहीं लगते। बिना बीजा आने वाले विदेशी पर्यटकों के समूह को आप्रवासन अधिकारियों द्वारा 30 दिनों की अधिकतम अवधि की लैंडिंग परमिट सुविधाएं स्वीकृत की जा सकती हैं बशर्ते कि यात्रा मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रेवल एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई हो।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चार महानगरों के क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्टर्ड विदेशी पर्यटकों के लिए "निर्गमन अनुमति" प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। अब विदेशियों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्टर्ड विदेशी पर्यटक प्रस्थान के समय हवाई अड्डे से निर्गमन अनुमति प्राप्त करते हैं।

केरल को पर्यटन हेतु सहायता

10411. श्री टी० बशीर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1989-90 के दौरान पर्यटन विकास हेतु कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) इस क्षेत्र पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और इस वर्ष के दौरान क्या उपलब्धि रही;

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए पर्यटन विकास हेतु कितनी धनराशि का आबंधन किया गया है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना अथवा परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) :
(क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1989-90 के दौरान 85.02 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं/स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है, जबकि वर्ष के दौरान नई तथा बाधू परियोजनाओं को रिसीज की गई कुल सहायता राशि 170.13 लाख रुपये थी।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उनके विशिष्ट प्रस्तावों पर दी जाती है। केरल राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार करके प्रस्तुत नहीं की है।

बिहार को बाढ़ राहत सहायता

[हिन्दी]

10412. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार बिहार में विनाशकारी बाढ़ों को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है;

(ख) बिहार को बाढ़ राहत कोष से गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई; और

(ग) क्या उपर्युक्त राज्य को बाढ़ सहायता प्रदान करने हेतु कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) बिहार के सभी गरीब तन्त्रों के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा बाढ़ प्रबन्ध हेतु व्यापक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ख) बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि नीचे दिए गए अनुसार है:—

वर्ष	आपदा	सीमान्त धन सहित दी गई केन्द्रीय सहायता
		(करोड़ रुपये में)
1987-88	बाढ़	54.329
1988-89	भूकम्प, स्थानिक बाढ़ आदि	16.875
1989-90	बाढ़ तथा सूखा एवं आम मगना इत्यादि स्थानिक आपदा	0.560

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष स्थापित करने के बारे में नवें वित्त आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा कोष की अभिरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार राज्य के लिए कोष में नवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा 26.25 करोड़ रुपए तथा राज्य द्वारा 8.75 करोड़ रुपए का अंशदान होगा।

कर सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण

[अनुषाच:]

10413. श्री श्रीकांत बल नरसिंहराज बाडियर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर मंसूर चेंबर आफ कामर्स ने उनके मंत्रालय को कर सम्बन्धी कानूनों के सरलीकरण और उत्पादन कराधान बोध वस्तुओं के वर्गीकरण तथा अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के मामले में समानता लाने हेतु तेजी से सुधार करने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों को कहां तक लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) कर सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण करना तथा शुल्क नाल के वर्गीकरण में तथा अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के सम्बन्ध में एक-छप्ता लाने में तेजी से सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की विभिन्न संस्थाएं और संघ इस सम्बन्ध में समय-समय पर सुझाव देते हैं। सरकार अपनी नीतियां तैयार करते समय नीतियों की समीक्षा करते समय ऐसे सभी सुझावों को ध्यान में रखती है।

आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उद्यम

10414. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उद्यमों की स्थापना करने के लिए कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार-विस्तार के लिए वर्ष 1989-90 में कोई समझौता ज्ञापन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान भारत-आस्ट्रेलिया के व्यापार के विस्तार की क्या योजना बनाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री-अरविन्द-जीवरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की जुलाई, 1989 में हुई प्रथम बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश एक दूसरे से वर्ष 1992 तक व्यापार कारोबार दोगुना कर 1.2 बिलियन डालर करने का प्रयास करेंगे।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार संबंधों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं :—

1. भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद का नियमित बैठकों की माहौल भारतीय तथा आस्ट्रेलियाई व्यापारियों के बीच सम्पर्क बढ़ाना।
2. संयुक्त व्यापार समिति (जे० टी० सी०) की स्थापित प्रक्रिया द्वारा वार्षिक व्यापार वार्ताओं का आयोजन करना।
3. आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक आयोजित करना।
4. आस्ट्रेलिया में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अधिक सहभागिता।
5. आस्ट्रेलियाई सरकार की बाजार मलाहकार सेवा की सहायता से आस्ट्रेलिया में भारतीय उत्पादों की अनन्य प्रदर्शनी लगाना।
6. आस्ट्रेलिया में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।
7. दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान करना।

प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले संवाददाताओं के चयन के लिए मानदंड

10415. श्री धर्मपाल सिंह गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और देश के बाहर प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले संवाददाताओं के चयन के लिये क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले संवाददाताओं का चयन राज्यवार करने के बारे में ध्यान दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्री. उषेन्द्र) : (क) और (ख) चयन का मुख्य मानदण्ड यथासंभव अधिक से अधिक कवरेज है। विदेशी टीवी के लिए चयन का मार्गदर्शी आचार भारत की विदेश नीति तथा प्रधान मंत्री की यात्रा की यथासंभव अधिक से अधिक कवरेज

सुनिश्चित करना है। ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की कबरेज में अनुभव प्राप्त होता है। क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों को यथासंभव प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती

10416. श्री जे० चोक्काराब : क्या बिस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उसी स्थान पर तैनात करने के सम्बन्ध में कोई नीति है जहां उनके पति/पत्नी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

बिस्त मंत्रालय में जय मंत्री (श्री अनिल झास्त्री) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों पर लागू अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बैंकिंग उद्योग से सम्बन्धित विशिष्ट कारकों, बैंकों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्थानान्तरण के मानदण्डों आदि को देखते हुए बैंकों से उन मामलों में पति एवं पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने के वास्ते नीति तैयार करने के लिए कहा गया है, जहां वे दोनों एक ही बैंक में अथवा अलग-अलग बैंकों में काम करते हैं। जब पति-पत्नी बैंकों से सम्बन्धित नहीं होते, वे मामले उपयुक्त मार्गनिर्देशों के अंतर्गत नहीं आते। बैंक कर्मचारियों पर लागू अधिकारी सेवा विनियमों के अंतर्गत, उनका स्थानान्तरण पूरे भारत में किया जा सकता है और प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानान्तरण अपरिहार्य भी हो सकता है और इसलिए इस आधार पर कि पति या पत्नी राज्य/केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, बैंकों के अधिकारियों को स्थानान्तरण से कोई छुली छूट प्रदान करना सम्भव नहीं हुआ है।

अवाइड स्टाफ कर्मचारियों पर लागू शास्त्री अवाइड के अनुसार, सामान्यतया उनका स्थानान्तरण उन भाषाई क्षेत्रों से बाहर नहीं किया जाता है जिनमें वे कार्य कर रहे होते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम

10417. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या बिस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने 17 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 1985 तक नाबेली में "दक्षिण अरकाट" के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम चलाया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कुछ प्रशिक्षणार्थियों को ऋण प्राप्त करने हेतु परिवोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो इन उद्यमियों की संख्या कितनी थी और उनमें से कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है; और

(ङ) जिन प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है उन्हें ऋण मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने 19.11.85 से 17.12.85 तक नाबेली में दक्षिण अरकाट जिले के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम चलाया था। 24 उद्यमियों को उद्यम-भूति के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया था।

(घ) से (ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सारे व्यक्तियों से अपनी परियोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। परन्तु उनमें से केवल 4 लोगों ने ही ऋण की मजूरी के लिए, अपनी परियोजना प्रस्तुत की थी। इनमें से, दो को उनकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। एक को व्यवहार्य नहीं पाया गया तथा चौथे आवेदनकर्ता को प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले उसकी ऋण्यस्तता के कारण वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी।

मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जिले में पर्यटन केन्द्र

[हिन्दी]

10418. श्री रेशम लाल झांगड़े : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे स्थानों का ग्योरा क्या है जहां, भारतीय पर्यटन विकास निगम या राज्य सरकार द्वारा खान तथा आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या मोरामदेव रतनपुर, सीरपुर दांतेवाड़ा, राजम, सियोरिनारायन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किए जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ग्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर भारत पर्यटन विकास निगम और अथवा राज्य सरकार द्वारा खान-पान और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं —

बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क
भेडाबाट
भोपाल
बिचकूट

ओरछा
पञ्चमढ़ी
पिपरिया
कण्डा

ग्वालियर	सागर
इन्दौर	साँची
जबलपुर	सतना
कान्हा राष्ट्रीय पार्क	शिवपुरी
खजुराहो	उज्जैन
मांडू	

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभागोंने गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ जिले में निम्नलिखित स्कीमों को मंजूरी दी है :—

स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)

(I) दांतेवाड़ा में कैफेटेरिया एवं टायलेट सुविधाएं	12.54
(II) बवारड़ा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	18.36
(III) भोरमदेव में मार्गस्थ सुविधाएं	3.67
(ग) जी, नहीं।	
(घ) प्रश्न नहीं उठता।	

विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करना

10419. श्री फूलचन्द बर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत विदेशी बैंक किसी खाते में न्यूनतम जमा राशि कार्य घंटे कम मूल्य वाले नोटों को लेने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये बैंक पांच लाख से कम राशि के ऋण आवेदनों पर विचार करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों को जमा खातों में एक न्यूनतम जमा राशि के बनाए रखने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारतीय बैंक संघ ने इस संबन्ध में सदस्य बैंकों द्वारा अनुमरण करने के लिए मूल नियम तथा आचार संहिता नियम जारी किए हैं। तथापि, सदस्य बैंक न्यूनतम जमा राशि आदि के बारे में स्वयं अपने लिए नियम बना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंक द्वारा निर्धारित कार्य के न्यूनतम चर्यों का पालन कर

रहे हैं। तथा उन्हें विदेशी बैंकों द्वारा जनता से कम मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार न करने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी बैंक पांच लाख रुपए से कम ऋणों के आवेदन पत्रों पर विचार करते हैं।

स्वर्ण आभूषण

[अनुवाद]

10420. श्रीमती अय्यवल्ली नवीनचन्द्र मेहता : क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महाराष्ट्र में वर्ष 1988 से स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कितने नमूने एकत्र किए गए;

(ख) अब तक इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का स्वर्णकारों द्वारा की जाने वाली बेईमानी पर रोक लगाने के लिए सभी स्वर्ण आभूषणों पर "हाल मार्क" लगाने की व्यवस्था करने का विचार है ?

बिस्व मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) बानवे (92)।

(ख) इनमें से उनहत्तर नमूने नियमित तोर अभिग्रहणों से संबन्धित हैं, जैसे—प्रारम्भिक सोना, विदेशी मार्क का सोना आदि। बाकी मामलों में नमून इसलिए लिए गए थे ताकि भारत सरकार टंकसाल, बम्बई में स्वर्ण-आभूषणों को अंकित शुद्धता का सही-सही रूप में पता लगाया जा सके। इनमें से 3 नमूने घोषित शुद्धता के थे। नौ मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा 3 मामलों में न्याय-निर्णय हो गया है तथा दण्ड आयद किया गया है। छः मामलों में न्याय निर्णय को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है तथा 10 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना बाकी है।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की धारा 30 में ऐसा प्रावधान है कि डीलर आभूषणों पर शुद्धता को अंकित करें।

कुवि उत्पादों का निर्यात

10421. श्री लेख नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुवि मंत्रालय के माध्यम से कुवि उत्पादों के निर्यात का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कृषि संज्ञान के माध्यम से निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित कृषि उत्पादों का ब्योरा क्या है; और

(ब) इस प्रस्तावित परिवर्तन से किसानों को क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद जीधरन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

आकाशवाणी केन्द्र त्रिवेन्द्रम से मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

10422. श्री सुरेश कोडीककुम्मील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी केन्द्र त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के लिये मलयालम कार्यक्रम प्रसारित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो मलयालम कार्यक्रम का प्रसारण कब तक आरंभ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता और तकनीकी दृष्टि से खाड़ी देशों को कोई कार्यक्रम प्रसारित करना सम्भव भी नहीं है । आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए मलयालम में कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सातवीं योजना के एक अंग के रूप में, आकाशवाणी के प्रस्तावों में खाड़ी के देशों को हिन्दी, मलयालम और अरबी में एक पूर्ण सेवा शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है । प्रारम्भ में यह सेवा मुख्य रूप से सऊदी अरब ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तरा और दक्षिणी यमन, कुवैत, ओडन और ईरान तथा इराक के कुछ भागों में रहने वाले भारतीयों के लिए प्रसारित की जाएगी । यह सेवा इस प्रयोजन के लिए पणजी में लगाये जा रहे 250-250 कि० वा० के दो शाट्रवेव ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर यह आरम्भ हो जायेगी ।

आकाशवाणी भवन, मुम्बई में सिनेमा थियेटर

10423. श्री राम नाईक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में आकाशवाणी के भवन में स्थित सिनेमा थियेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है जबकि यह चर्च गेट स्टेशन के निकट एक उत्कृष्ट क्षेत्र में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान इसका कितने दिन उपयोग किया गया; और

(ब) इस थियेटर का नाटकों, सार्वजनिक समारोहों सहित अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : (क) और (ख) बम्बई में आकाशवाणी की इमारत में कोई सिनेमाघर नहीं है। चर्चबेट, बम्बई के आकाशवाणी प्रसारण भवन ५.५५.५५ में एक सभागार है। आकाशवाणी ने यह सभागार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्म प्रदर्शन के लिए सौंप दिया था। किन्तु आकाशवाणी के माल्टी-ट्रेक रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु इस सभागार को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से वापिस ले लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से 1988 में सभागार वापिस ले लेने के बाद इसका उपयोग आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख कार्यक्रमों की रिकार्डिंग के लिए किया जा रहा है। सभागार को माल्टी ट्रेक रिकार्डिंग स्टूडियो के लिए उपयुक्त बनाने हेतु नवीकरण कार्य तथा सिविल सुधार कार्य पहले से ही शुरू किये जा चुके हैं।

स्वर्णकारों की समस्या

10424 श्री आर० जीवरत्नम }
 श्री आर० एन० राकेश } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
 श्री फूल चन्द वर्मा }
 श्री ए० आर० अम्बुले }

(क) क्या सरकार ने देश में लाइसेंसधारा स्वर्णकारों की संख्या और उनकी वार्षिक सोने की मांग का कोई आकलन किया है;

(ख) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, के कारण प्रभावित हुए स्वर्णकारों के पुनर्वास हेतु उन्हें ऋण देने अथवा कुछ राहत देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी व्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में सोने की मांग को पूरा करने हेतु कोई उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1989 में देश में प्रभावित स्वर्णकारों की संख्या 3,78,416 थी। तथापि, स्वर्णकारों द्वारा अपेक्षित सोने की वार्षिक मांग का कोई मूल्यांकन संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सोना एक आवश्यक वस्तु नहीं है, इसलिए देश में सोने की मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भारतीय कम्पनियों के पूंजी निर्गम में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

10425. श्री विलीप सिंह जू देव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री शान्ताराम पोद्दुके }

(क) क्या भारतीय कम्पनियों के पूंजी निर्गमों में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश में अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निवेशक देश के पूंजी बाजार में भी कम्पनियों के डिबेन्चर करने के अनुचित तरीकों से असमंजस में हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने और अनिवासी भारतीयों और निवासी भारतीयों द्वारा पूंजी बाजार में निवेश में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) किसी कम्पनी के निर्गम के प्रति निवेशकों का प्रतिक्रिया, पूंजी बाजार की सामान्य स्थिति, कम्पनी द्वारा किए गए विपणन प्रयास उसका पिछला रिकार्ड, निवेशकों की प्रत्याशाएं की प्रत्याशाएं और प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उन्हें उपलब्ध विकल्प सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। पूंजी बाजार के विकास तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और जारी रहेगी।

श्रीकाकुलम के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन ट्रांसमीटर यूनिट
की स्थापना

10426. डा० बिश्वनाथम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान श्रीकाकुलम के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण टेलीविजन ट्रांसमीटर यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) जबकि श्रीकाकुलम में एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है, फिर भी विशाखा-पत्तनम का उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर भी ग्रामीण इलाकों सहित श्रीकाकुलम जिले के कुछ भागों को सेवा प्रदान करता है। तथापि, इस समय श्रीकाकुलम जिले में दूसरा दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धनराशि के अनुसार सरकार का यह प्रयास है कि श्रीकाकुलम जिले सहित देश के कवर न हुए बाकी भागों में दूरदर्शन का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार किया जाए।

पर्यटक परिवहन से भारत पर्यटन विकास निगम को घाटा

10427. श्री काशीराम राणा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विचार के आधार पर कि भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन परिवहन कारोबार को चला रखना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है, भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन बेड़े/कारोबार को बंद करने/घटाने के प्रयास पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी झ्योरा क्या है; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन कारोबार में घाटा होने के कारण क्या हैं और घाटे को कम करने/घटाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) पर्यटक गंतव्यों पर परिवहन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की उत्प्रेरक भूमिका रही है। अतः भारत पर्यटन विकास निगम की यह नीति रही है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर्यटकों की परिवहन सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट अथवा अन्य परिवहन प्रचालक आगे आते हैं वहाँ से निगम हट जाए। तदनुसार, 1983 से भारत पर्यटन विकास निगम ने नौ परिवहन एकक बन्द किए हैं तथा आने वाले वर्षों में अपने बेड़े में और कमी करने की इसकी योजनाएँ हैं ताकि अन्ततोगत्वा वाणिज्यिक रूप से उगादेय स्थानों पर लगभग 50 वाहनों की एक सुदृढ़ व्यवस्था हाई कोर) रखी जा सके। हानि का मुख्य कारण छोटे निजी प्रचालकों/राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना था जिनकी मजबूरी संबंधी लागत एवं ऊपरी व्यय कम थे।

दौरों एवं यात्राओं सम्बन्धी कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने के अलावा, मिश्रित उत्पादों में परिवर्तन तथा वृद्धि करके हानि में कमी करने और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1989-90 के लिए, अशोक ट्रैवल्स एवं टूरर्स को 53 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

10428. श्री कल्पनाचंद राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया था;

(ख) क्या जिन परियोजनाओं के लिए यह ऋण लिया गया था उनमें इसका पूरा उपयोग किया गया था; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी धनराशि का ऋण प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी ऋण का अनुरोध नहीं किया गया था ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लोहा और इस्पात बर्तों का वितरण

10429. श्री केशरी लाल : क्या इस्पात और लौह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित शाला बिक्री कार्यालय द्वारा जनवरी मार्च/अप्रैल-जून 1990 के दौरान टी०वी०एस०/एल०टी०सी० के अंतर्गत, वितरण सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए, विशेष/सामान्य किस्म में राऊण्ड्स/जी० पी० शीट (63/5 मि० मी०) जैसी दुर्लभ इस्पात मदे जारी की गई हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दोनों किस्मों में राऊण्ड्स/जी० पी० शीटों का प्रतिशत-वार कितना आवंटन किया गया;

(ग) क्या आवंटन सम्बन्धी ये प्रतिशतता सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू की गई थी;

(घ) क्या जी०पी० शीटों, एल०एफ०यू० की पूर्व-पेशकश/अतिरिक्त पूर्व पेशकश मात्राओं को बाद में सामान्य किस्म में बदला गया, जबकि सामान्य किस्म की स्टेट्स "ए" की मांग सम्बन्धित पड़ी थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो पार्टियों के भूरे सहित मात्रा में इस प्रकार कितना परिवर्तन किया गया और ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

इस्पात और लौह मंत्री तथा बिजि और ग्याय मंत्री (श्री विवेक जोशवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राऊण्ड्स/जी०पी० शीटों का प्रतिशत-वार आवंटन नहीं होता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जनवरी-मार्च, 1989 की टी०बी०एस० के लिए जब अन्य गुणवत्ता सामग्री की पैकका की गयी, तब इस सामग्री के लिए स्टेट्स "ए" की कोई बुकिंग लम्बित नहीं थी ।

(ङ) सेल द्वारा पांच पार्टियों को एल० एफ० ब्यू० शीटों के स्थान पर सामान्य किस्म की ओ०पी० शीटों की लगभग 166 मीटरी टन की सप्लाई की गई जिससे टी०बी०एस० बुकिंग के लिए जुमाना देने की सम्भावनाओं से बचा जा सके ।

शीतल पेयों का विज्ञापन व्यय और उत्पाद-मूल्य

10430. श्री सिकिहो सेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीतल पेयों के निर्यात अपने उत्पादों के विज्ञापन/प्रचार पर अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं जिसके फलस्वरूप इनके उत्पादों का मूल्य अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बोतल पर प्रचार सम्बन्धी औसत व्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इनके मूल्यों में कमी करने के लिए इनके विज्ञापन व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

बिला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सेबन सी एल्स को भरणघाट क्षेत्र के बाहर अप्रभरण की अनुमति

10431. प्रो० के० बी० चामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेबन सी एल्स" को भरणघाट क्षेत्र के बाहर शिपर्स कन्साइनीज परिमर में अप्रभरण की अनुमति दिए जाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत तथा विदेशों में अन्य प्रमुख पत्तनों पर यह प्रणाली अपनाई जाती है ?

बिला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न एफ० सी० एल्स० (पूरे आबान लोड) को अप्रभरण किये जाने से सम्बन्धित है न कि "सेबन सी एल्स" को ।

सामान्यतः सम्पूर्ण आधान लोड की सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क क्षेत्र में निकासी की जाती है जो सामान्यतः भरण घाट (वार्क) क्षेत्र में होते हैं और तब इन्हें या तो भरण घाट क्षेत्र अथवा शिपर्स/कन्साइनीज/आयातक के परिसरों में अप्रभरण (डिस्टीफिंग) और सुपुर्वगी डिलीवरी के लिये सौंप दिया जाता है। बुनिन्दा मामलों में पूरे आधान लोड की भरण घाट/सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर सीमा शुल्क के कर्मचारियों को कन्साइनीज के परिसरों में भेजकर पूर्ण आधान लोड की सीमा शुल्क जांच एवं निकासी करने के लिए विशेष अनुमति दी गई है। कर्मचारियों की कमी होने के कारण सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर सीमा शुल्क सम्बन्धी जांच और निकासी कार्य सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं किया जाता है।

यह पद्धति भारत में कोचीन को छोड़ कर बड़े पत्तनों पर अपनायी जाती है जहां आधान लोड के अप्रभरण तथा डिलीवरी सम्बन्धी कार्य केवल भरण घाट क्षेत्र पर ही किये जाते हैं। बाहर के देशों में इस सम्बन्ध में अपनायी जा रही पद्धति के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि कुछ विकसित पश्चिमी देशों में सीमा शुल्क से पूर्व निकासित पूर्ण आधान लोड अप्रभरण के लिये आयातक के परिसरों में डिलीवर किये जाते हैं तथा केवल ऐसे ही पूर्ण आधान लोड को ही ऐसी जांच के लिये पत्तनों पर अप्रभरण करने के लिये रोका जा जाता है जिन्हें सीमा शुल्क जांच हेतु चुना गया हो।

लाख के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट

10432. श्री राधा मोहन सिंह } क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री अनादित्त यादव }

(क) क्या एम० आर० शिवरमन समिति की रिपोर्ट, राज्य सभा की वाचिका समिति की रिपोर्ट और लाख के व्यवसाय में लगे किसानों तथा कामगारों को न्यूनतम पारिश्रमिक देने तथा लाख दाने के भण्डार को बढ़ाने सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को ये रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को यथा सम्भव कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उत्तरा।

न्यायिक प्रणाली के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन

10433. श्री सैकट कुल्ल रेड्डी कासु
श्री० विजय कुमार मल्होत्रा
श्री बाई० एस० राजेश्वरी रेड्डी
श्री टी० बशीर } : क्या बिचि और न्याय मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन सामान्य को समय पर न्याय प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान न्यायिक प्रणाली के ढांचे में परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों से सम्बन्धित झीरा क्या है और उसके विचारार्थ विषय क्या-क्या होंगे।

इस्पात और खान मंत्री तथा बिचि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिये एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इसके गठन के सम्बन्ध में उपबन्ध, संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक में दिया गया है जो लोक सभा में तारीख 18-5-1990 को पुरः-स्थापित किया गया है।

इस समय किसी अन्य आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा वसूल किया गया ब्याज

10434. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक ने, इस बैंक के कुछ खाना धारियों से वसूल किए गए ब्याज के सम्बन्ध में कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से बातचीत प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी झीरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) किसी भी खाते में ब्याज रियायत के सम्बन्ध में इंडियन ओवरसीज बैंक ने सरकारी क्षेत्र में किसी भी उपक्रम के साथ विचार विमर्श शुरू नहीं किया है।

रि-रोलिंग उद्योग के मजदूर

10435. श्री० विजय कुमार मल्होत्रा क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऑल इंडिया रि-रोलर्स एसोसिएशन से देश में रि-रोलिंग उद्योग के मजदूरों की समस्याओं/कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इन मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा इन मजदूरों की कठिनाइयों की जाँच करने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो कब ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा बिबि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) मुख्य उत्पादकों द्वारा कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कुछ पुनर्गठन मिलों को बन्द किये जाने की ओर एसोसिएशन द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख)से (घ) मुख्य उत्पादकों से अर्द्ध तैयार इस्पात/बिलेटों की उपलब्धता कुल देशी उपलब्धता के 20% से कम है अर्थात् इसमें गौण क्षेत्र भी शामिल हैं। गौण क्षेत्र में वृद्धित उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रेपलेनिशमेंट/अतिरिक्त लाइसेंसों पर भी अर्द्ध तैयार इस्पात/बिलेटों का आयात एम.एम.टी.सी. के माध्यम से करने की भी अनुमति दी गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्राइम कोकिंग कोयले का आयात

[हिन्दी]

10436. श्री बृज भूषण तिवारी क्या : इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में प्राइम कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ख) देश में प्राइम कोकिंग कोयले का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) इसका आयात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा बिबि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान समन्वित इस्पात कारखानों द्वारा आयातित वर्ष कोकिंग कोयले की

अनुमानित मात्रा तथा चालू वर्ष के लिये योजनाबद्ध मात्रा नीचे दी गई है :—

(लाख टन)

1988-89	1989-90	1990-91
44.4	53.5	56

उत्कृष्ट क्वालिटी के कम राख वाले धातुकर्मीय कोककर कोयले की मांग तथा घरेलू उप-सम्पत्ता के बीच मात्रात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से अन्तरों को पाटने के सम्बन्ध में समन्वित इस्पात कारखानों के आयात का सहारा लेना पड़ता है। आयातित कोयले को उस स्वदेशी कोयले के साथ मिलाया जाता है जिसमें राख की उच्च प्रतिशतता होती है ताकि अश्वेजित राख के स्तर सहित संतोषजनक प्रौद्योगिकीय प्राचलों की प्राप्ति हो सके।

(ख) वर्ष 1888-89 के दौरान देश में उत्कृष्ट कोककर कोयले का उत्पादन 125 लाख मी० टन रहा और वर्ष 1989-90 के दौरान इसके 113.4 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया था।

भारत-पाकिस्तान महिला उद्यमी व्यापार

[अनुवाद]

10437. श्री आर० एन० राकेश
श्री मन्जिराज होडल्या मामीत } : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान महिला उद्यमी व्यापार परिषद की 30 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस बैठक में हुई चर्चा की मुख्य बातें तथा परिषद द्वारा सरकार को दिए गये सुझावों का ब्योरा क्या है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द जीधरन) : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान की संयुक्त व्यापार महिला परिषद की दूसरी बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में हुई थी। भागीदारों ने प्रशासन एवं व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने में दोनों देशों के बीच सहयोग देन, पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र अभिज्ञात करने के लिए तथा दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये और पाकिस्तान में अध्ययन दौरे

आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। परिषद ने सरकार को कोई सुझाव नहीं दिए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

बुमेन्स बिग आफ नेशनल एसायम्स आफ थिंग एंटरप्राइजर्स (नाए)

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1. श्रीमती नीना मल्होत्रा | — | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती रजनी अग्रवाल | — | अध्यक्ष |

अन्तर्राष्ट्रीय समिति

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 3. श्रीमती प्रिया खन्ना, | उपाध्यक्ष |
| 4. श्रीमती शोभा अरोड़ा, | उपाध्यक्ष |

दिल्ली-सभा

- | | |
|----------------------------|------|
| 5. श्रीमती नरिन्दर पाल कौर | सचिव |
|----------------------------|------|

पाकिस्तान एसोसिएशन आफ बुमेन्स एंटरप्राइजर्स (पाबे)

1. बेगम सलमा अहमद, अध्यक्ष
2. नुशरा अजमल, संयुक्त सचिव
3. फरजाना रहमान, सचिव—सूचना
4. बसरा सुल्ताना
5. शामिना सुल्ताना

अमरीका को किए जाने वाले वस्त्र निर्यात पर सुपर 301 का प्रभाव

10438. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को सुपर 301 के अधीन सूची में लाने के बारे में अमरीका के निर्णय का वस्त्र निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) वस्त्र निर्यात के हित में किन-किन उपायों पर विचार लिया जा रहा है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) संयुक्त राज्य भारत के निर्यात के खिलाफ संयुक्त राज्य न सुपर 301 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इन परिस्थितियों में भारत को सूचीबद्ध किये जाने से भारत से संयुक्त राज्य को किये जाने वाले वस्त्र निर्यात के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लेखन सामग्री की तस्करी

10439. श्रीमती वासुध राजेश्वरी }
श्री श्री० एस० वासुदेवाय } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, हावकाँक और भिस्मपुर से लेखन-सामग्री की बड़े पैमाने पर तस्करी के कारण भारतीय लेखन सामग्री उद्योग को भारी क्षति पड़ा हो गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस तस्करी को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

बिस्म मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे ए०३ किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

रग्ग चाय बागान

10440. श्री बिल बलु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रग्ग चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उन बागानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्टाक मार्केट

10441. श्री पी० एम० सईब : क्या बिल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने विशेषकर राज्यों की राजधानियों में और अधिक स्टॉक मार्केट स्थापित किए जान की बकालत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दिये गये तर्कों सहित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

बिस्म मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने 31 अक्टूबर, 1949 को दिये गये एक ज्ञापन में अन्य बानों के साथ साथ, नये स्टॉक एक्सचेंजों के विकास का मुद्दा दिया था, क्योंकि शाताब्दी के अंत तक पंजीकृत कम्पनियों की संख्या तथा निवेशकों और लेन देन के आकार में संभावित वृद्धि होने के कारण वर्तमान स्टॉक एक्सचेंजों पर भारी दबाव पड़ेगा।

(ग) सरकार ने उपर्युक्त मुद्दा को नोट कर लिया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के नवीनीकरण पर व्यय

10442. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारागत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अपने होटल-भवनों के विकास परिवर्तन और नवीनीकरण पर होटल-वार निर्धारित की गई और व्यय की गई धनराशि का झोरा क्या है;

(ख) इस लेखे पर वर्ष 1989-90 के दौरान महीने-वार व्यय की गई धनराशि का झोरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के अन्तिम महीने में व्यय की गई धनराशि असमानुपातिक रूप से बहुत अधिक थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सत्यपाल बलिक) : (क) अपेक्षित सूचना सलग्न—1 में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण—2 में दी गई है।

(ग) और (घ) 1989-90 के अन्तिम महीने में खाते में दर्ज किया गया व्यय 365.72 लाख रुपए रहा है जबकि समूचे वर्ष में कुल व्यय 1164 00 लाख रु० हुआ है। मार्च 90 में खाते में दर्ज 365 72 लाख रु० में ये शामिल हैं :—

(1) विभिन्न एककों द्वारा पूरे वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शुरू किये गए/पूरे किए गए कार्यों हेतु 156 लाख रु० (जिनके लिए मार्च 90 में सूचना प्राप्त हुई थी);

(2) प्रत्यक्ष पत्र को खोलने/सीमा शुल्क का मुगतान करने हेतु 50 लाख रुपए; और

(3) भावी कार्यों के लिये 50 लाख रु० मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में अदा किए जिसके सम्बन्ध में लगभग 100 लाख रु० की राशि बकाया रही जो मार्च 90 के दौरान परिवर्द्धन/परिवर्तन/नवीनीकरण कार्यों पर खर्च की गई है जो पूर्ववर्ती महीने के दौरान किए गए व्यय के साथ अनुकूल दृष्टि से तुलनीय है।

विवरण-1

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	होटल का नाम	वर्षवार बजट/व्यय		
		1987-88 बजट व्यय	1988-89 बजट व्यय	1989-90 बजट व्यय
	वर्तमान होटलों/एककों का परिवर्द्धन/परिवर्तन/सुधार	425.00	782.00	1240.75
1	2	3	4	5
1.	अशोक होटल नई दिल्ली	122.50	225.45	359.75
2.	सफाट होटल, नई दिल्ली	31.60	13.69	109.50

1	2	3	4	5
3.	कुतब होटल नई दिल्ली	22.84	30.61	47.84
4.	कनिष्क होटल नई दिल्ली	84.12	250.16	47.95
5.	जनपथ होटल नई दिल्ली	25.33	26.33	76.67
6.	सोदी होटल नई दिल्ली	5.16	0.97	48.28
7.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	25.99	31.31	45.22
8.	होटल अशोक बगलौर	30.05	24.95	90.74
9.	होटल बाराणसी अशोक बाराणसी	19.98	35.94	83.66
10.	होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना	1.49	23.62	71.32
11.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	13.70	20.32	72.85
12.	होटल एयर पोर्ट, कलकत्ता	45.45	66.43	44.34
13.	होटल जम्मू अशोक जम्मू	10.56	1.22	17.52
14.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर	0.38	—	7.92
15.	होटल जयपुर अशोक जयपुर	12.32	4.41	0.39
16.	होटल आगरा अशोक	—	2.92	—
17.	होटल मधुरै अशोक मधुरै	0.82	2.85	1.94
18.	होटल कलिंग अशोक मुवनेश्वर	—	13.63	8.00
19.	होटल बोधगया अशोक बोधगया	—	—	7.67
20.	ललितामहल पैलेस होटल मैसूर	7.20	13.56	7.52
21.	भरतपुर फोरेस्ट लाज भरतपुर	—	—	0.03
22.	होटल हसन अशोक हसन	2.83	5.44	1.26
23.	रणजीत होटल नई दिल्ली	24.20	7.55	8.29
24.	होटल खजुराहो अशोक	0.40	—	0.74
25.	होटल महाबलीपुरम अशोक	1.23	—	—
26.	होटल औरंगाबाद अशोक औरंगाबाद	3.26	2.40	0.75
27.	विविध कार्य	—	26.15*	—
		425.00	422.55	772.00
			829.89	1164.04

1240.45

कहें

493.00

830.00

*कहें

1164.00 लाख

*दस्तावेज और सेवा वरीलाबीन ।

विवरण-2

(सालों रुपये में)

1989-90 के दौरान साहवार व्यय

क्र.सं.	होटल का नाम	बजट	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
	विस्तार/फिरवटल/ सुधार/नवीकरण	1240.45						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अशोक होटल नई दिल्ली		16.63	4.10	6.35	53.28	21.49	41.06
2.	सम्राट होटल नई दिल्ली		7.17	1.59	1.51	0.12	11.03	19.55
3.	कुतब होटल, नई दिल्ली		1.59	1.96	5.92	3.59	3.63	13.00
4.	कनिष्ठ होटल नई दिल्ली		0.01	3.00	0.47	0.60	9.76	3.93
5.	जनपथ होटल नई दिल्ली		0.25	.87	3.56	6.82	3.51	7.32
6.	लॉदी होटल नई दिल्ली		—	—	—	0.11	—	—
7.	अशोक यात्री निवास नई दिल्ली		—	—	3.93	—	—	2.44
8.	होटल अशोक बंगलौर		—	—	0.12	—	7.80	6.84
9.	होटल बाराणसी अशोक बाराणसी		1.79	2.09	6.57	0.45	12.76	13.10
10.	होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना		—	—	1.01	4.03	7.59	6.80

1989-90 के दौरान माहवार व्यय

क्र.सं.	होटल का नाम	बजट	अप्रैल	मई	जून	जुलै	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16						
	विस्तार/फिरबदल/ सुधार/नवीकरण	1240.45													
1.	असोक होटल नई दिल्ली		2.50	16.71	34.86	23.39	16.28	103.13	359.75						
2.	सम्राट होटल नई दिल्ली		8.03	4.94	11.73	11.86	4.70	27.27	109.50						
3.	कुतब होटल, नई दिल्ली		5.31	0.01	4.12	4.73	1.34	2.64	47.84						
4.	कनिष्ठ होटल नई दिल्ली		1.69	4.07	7.29	4.27	0.22	12.64	47.95						
5.	जनपथ होटल नई दिल्ली		5.87	0.53	6.19	11.96	—	25.39	76.67						
6.	सोनी होटल नई दिल्ली		—	—	0.01	—	28.72	19.43	48.28						
7.	असोक यात्री निवास नई दिल्ली		3.86	—	9.24	6.09	—	19.66	45.22						
8.	होटल असोक बंगलौर		25.65	1.26	10.79	9.36	0.11	28.81	90.74						
9.	होटल बाराबंसी असोक बाराबंसी		23.25	1.54	4.10	1.80	4.58	11.44	83.66						
10.	होटल पाटलीपुत्र पटना		12.45	2.83	7.44	4.76	6.78	16.83	71.32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	कोबलम अडोफ बीच रिपोर्ट कोबलम		4.99	3.39	2.63	—	—	—
12.	होटल एयरपोर्ट, कलकत्ता		—	2.94	3.16	1.74	2.72	3.40
13.	होटल जम्मू अडोफ, जम्मू		—	—	—	—	—	—
14.	बकसी विलास पैलेड होटल, जयपुर		—	—	—	—	0.21	0.02
15.	होटल जयपुर अडोफ जयपुर		—	2.02	—	—	—	—
16.	होटल जानरा अडोफ जानरा		—	—	—	—	—	—
17.	होटल मयूर अडोफ मयूर		—	—	—	—	—	—
18.	होटल फनिव अडोफ पुष्पेश्वर		—	1.30	0.20	0.19	—	—
19.	होटल बोधगया अडोफ बोधगया		1.66	1.20	0.54	0.43	—	0.01

1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
11.	कोबलन अशोक बीच रिपोर्ट कोबलन		—	—	9.76	—	2.41	49.67	72.85
12.	होटल एयरपोर्ट कलकत्ता		1.88	0.23	2.76	4.99	0.83	19.69	44.34
13.	होटल जम् अशोक, जम्		11.42	0.43	1.09	—	—	4.58	7.12
14.	लक्ष्मी विनास वैस होटल, जयपुर		0.01	0.22	2.31	0.22	1.46	3.47	7.92
15.	होटल जयपुर अशोक जयपुर		—	—	—	—	0.35	0.02	0.39
16.	होटल आगरा अशोक आगरा								
17.	होटल महरं अशोक महरं		—	0.46	0.01	—	—	1.49	1.94
18.	होटल कलिय अशोक मुक्तेश्वर		3.80	—	0.37	1.34	0.05	0.75	8.00
19.	होटल बोधगया अशोक बोधगया		0.34	—	0.09	0.05	0.05	3.30	7.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	सखिता महल पब्लिस होटल मैन्नूर		—	—	—	1.30	—	0.11
21.	भरतपुर बल-गृह भरतपुर		—	—	—	—	—	—
22.	होटल हसन अशोक हसन		—	—	—	—	—	—
23.	रणजीत होटल नई दिल्ली		—	—	—	—	—	2.36
24.	होटल लजुगहो अशोक लजुगहो		—	0.63	0.10	—	—	—
25.	होटल महाबलीपुरम अशोक							
26.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद		0.03	0.39	0.07	0.05	—	—
27.	विविधा कार्य		1.58	—	0.25	0.91	—	—
जोड़ :-			36.02	28.48	36.84	73.62	79.45	19.94

1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
20.	सविता महल पैलेस होटल मैसूर		—	—	0.01	—	—	6.10	7.52
21.	बलपुर वन-गृह बलपुर		—	—	—	0.03	—	—	0.03
22.	होटल हमन अशोक हसन		—	—	—	—	—	1.28	1.28
23.	रजनीत होटल नई दिल्ली		—	—	0.08	—	1.09	4.76	8.29
24.	होटल सपुराहो अशोक सपुराहो		—	—	0.01	—	—	—	0.74
25.	होटल महाबलीपुरम अशोक		—	—	—	—	—	—	—
26.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद		—	—	0.01	—	—	0.20	0.75
27.	निविदा कार्य		—	—	0.02	—	2.76	—	—
जोड़ :-			26 27	34 23	112.29	84.91	66.27	365.72	11.64

लघु उद्योगों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की योजना

10443. श्री सुधीर गिरि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने लघु उद्योगों के समझ आने वाली विशिष्ट समस्याओं के समाधान में योगदान देने के लिये "रिहैबिलिटेशन क्लीनिकस" नामक एक नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के लिये अपने यहां खोले गए कक्ष (सैल) के जरिए कितनी महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण लघु उद्योगों के लिये पुनर्स्थापना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप में तेजी से निपटाने के वास्ते उमने अपने अंचल कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी (पुनर्स्थापना) के अधीन पुनर्स्थापना कक्षों का गठन किया है। बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों वाला स्थानीय दल रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना से सम्बद्ध समस्याओं पर चर्चा करने के लिये एक निश्चित समयवधि में बैठकें करते हैं।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि छोटे पैमाने पर छोटे कारबार वित्त के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अलावा, जिनके अन्तर्गत महिला उद्यमी ऋण सुविधाएं प्राप्त करती हैं, बैंक ने "स्त्री शक्ति पैकेज" नामक एक योजना प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत व्याज दर तथा माजिन में रियायत दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 1.5 लाख महिला उद्यमियों को अग्रिम मंजूर किये गये हैं और दिसम्बर 1989 की स्थिति के अनुसार 86 करोड़ ६० के कुल बकाया ऋण थे।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंग्रेजी में छपे फार्म

[हिन्दी]

10444. कुमारी उमा भारती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ ही फार्म अंग्रेजी में हैं या अधिकांशतः अंग्रेजी में हैं; यदि हाँ, तो ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है जो केवल अंग्रेजी में ही भरे जाने अपेक्षित हैं; और

(ग) विभिन्न योजनाओं के लिये फार्म हिन्दी में न भरने दिए जाने के कारण क्या है और और ऐसी समस्या कब तक की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट से

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिमहाल प्रचालन सम्बन्धी कार्यों से उनके अधिकांश फार्म बंधोबी में हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यूनिट धारकों से सम्बन्धित आंकड़े तथा सामांशों का समय पर भुगतान आदि सम्बन्धी आंकड़े कम्प्यूटरों की सहायता से रखे जाते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट से जहाँ तक सम्भव हो, अधिकाधिक फार्म हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

राजस्व अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किया जाना

[अनुवाद]

10445. श्री बालासाहिब बिसे पाटिल : क्या बिसे बंधी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किये जाने सम्बन्धी मामलों का व्यौरा क्या है, जैसा कि 19 मार्च 1990 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपा है;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की गई है जैसा कि रिपोर्ट में आरोप है;

(ग) यदि हां, तो परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) परेशान करने के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करने के लिये क्या कोई एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

बिसे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) यह आरोप लगाया गया है कि एक अधिकारी का बम्बई से मुबनेश्वर को तथा बाद में मद्रास स्टाय प्रशिक्षण कालेज को स्थानांतरण किया गया था और उसकी पदोन्नति छः वर्ष से अधिक अवधि के लिये रोक दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि एक अन्य अधिकारी को बिना किसी जांच पड़ताल के सराहनीय आरोप पर उसके खिलाफ अनुशासनारम्भ कार्रवाई शुरू करके पदोन्नति नहीं की गई थी तथा उसके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को "सील बन्द लिफाफे" में रखा गया था।

(ख) यह सच नहीं है कि सम्बन्धित दो अधिकारियों को परेशान किया गया था। एक अधिकारी को सामान्य तौर पर 4 वर्ष की सेवा-अवधि के पूरा होने पर बम्बई से मुबनेश्वर को स्थानांतरित किया था। मुबनेश्वर से, सामान्य तौर पर लगभग 4 वर्ष की अवधि को पूरा करने पर उन्हें मद्रास स्टाय प्रशिक्षण कालेज को स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में उन्हें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समार्वहों के तौर पर पदोन्नत किया गया था और बम्बई में सेनात कर दिया गया।

दूसरे अधिकारी के मामले में, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को अनुशासनारम्भ कार्यवाही के कारण सीलबन्द लिफाफे में रखा गया था जो कि एक सामान्य पद्धति है।

(ग) और (घ) के उत्तर नहीं सकते हैं।

मध्य प्रदेश में रतलाम में "स्टील स्क्रैप यार्ड" की स्थापना

[हिन्दी]

10446. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या इस्पात और ज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में एक "स्टील स्क्रैप यार्ड" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

इस्पात और ज्ञान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में यात्री निवासों की स्थापना

[अंगुबाव]

10447. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार हरियाणा में यात्री निवास की स्थापना के लिए किसी स्थान के बारे में भी विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लख्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रयोगशाला बुकिंग

10448. श्री एम० सेल्वाराम् : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में खाद्य पदार्थों की आकस्मिक जाँच करने हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1987-88 और 1989-90 के दौरान इसके कार्य निष्पादन का व्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी जनशक्ति-व्यय की गई है; और

(ग) इस कार्य हेतु कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें सौंपे गये कार्यों का व्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) मुख्यतः गौरवगाली चोगम सम्मेलन के लिए, 1983 में अशोक होटल नई दिल्ली में एक छोटी-सी रसायन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी जिसमें 4 कर्मचारी थे और इसने केवल 1986-87 तक कार्य किया। 4 कर्मचारियों में से 2 ने 1984 में नौकरी छोड़ दी थी और शेष 2 कर्मचारियों की सेवाओं का (अर्थात् एक विश्लेषक एवं एक प्रयोगशाला सहायक) खाद्य तथा अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली स्थित होटल एक्को की सहायता पर निगम द्वारा अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य विंग में उपयोग किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोगशाला के लिए उपकरणों/मशीनों पर कोई खर्चा नहीं किया है।

मसालों का निर्यात

10449. श्री डी० एम० पुट्टे गौडा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिये मसालों के निर्यात का लक्ष्य कितना था और वास्तव में कितनी मात्रा में मसालों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों के निर्यात का लक्ष्य पूरा किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीचरन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों के निर्यात मात्रावार लक्ष्य से अधिक हुए, परन्तु मूल्य की दृष्टि से इनमें गिरावट आई, इसका मुख्य कारण यह था कि इकाई मूल्य बसुनी अपेक्षाकृत कम थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहज आपूर्ति के कारण कालीमिर्च का निर्यात कम हुआ था।

(घ) किए जा रहे निर्यात संवर्धन उपायों में शामिल हैं : प्रचार अभियान, व्यापार मेलों में भाग लेना, क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करना आदि, नकद मुआवजा सहायता और आयात प्रतिपूर्ति जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के अलावा क्वालिटी सुधार कार्यक्रम आदि।

मद	विवरण मसालों का निर्यात		वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों के निर्यात में उपलब्धि	
	वर्ष 1989-90 के लिए लक्ष्य			
	मात्रा एम टी	मूल्य लाख रु०	मात्रा एम टी	मूल्य लाख रु०
1	2	3	4	5
काली मिर्च	42000	21000	36601	15987.74
इलायची (छोटी)	750	1125	171	319.41
इलायची (बड़ी)	300	140	598	255.62
मिर्च	8000	1495	10713	2098.76
अदरक	5200	1040	7315	1271.53
हल्दी	13000	1300	16468	1572.42
कढ़ी पाउडर	3000	500	3107	602.47
बीज और अन्य मसाले	14000	1400	24312	3074.36
मसालों का तेल तथा तेल राल	450	2000	601	2253.77
कुल	86700	30000	99886	27436.08

बीकड़े अनन्तिम है।

सोहे और इस्पात की सामग्री का वितरण

10450. श्री नकुल नायक } क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री केसरी लाल }

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा ऐसी पार्टियों को बोहे और इस्पात की सामग्री जारी की गई है जिनके बारे में चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन के लिये कुछ तकनीकी विकास महानिदेशालय एककों की क्षमता प्रमाण पत्रों की विषय सूचियों के प्रति जाली क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर और कुछ यूनिटों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के सम्बन्ध में तकनीकी विकास महानिदेशालय से स्वीकृति प्राप्त न करने के आधार पर विभागीय समिति/सरकारी लेख परीक्षा रिपोर्ट संख्या 10 और 11, दिनांक 21 अक्टूबर, 1989/1 जनवरी, 1990 और 26 दिसम्बर, 1989 में क्रमशः विपरीत टिप्पणी दी गई थी,

(ख) क्या इन पार्टियों को डी० आर०एस० शाहकों की पुष्टि हुई बुकिंग के आधार पर प्राप्त टी० बी० एस० बुकिंग की एवम में भी सामग्री जारी की गई है और इस प्रकार के गैर-सरकारी पार्टियों को टी० बी० एड० में कन्वर्शन एवलों के लाइट सेक्शन का वाबंटन करते हुये ई०ई०पी०सी०

आर०ओ० कारकों को उसकी सप्लाई से इन्कार किया गया है और रखा प्राथमिकताओं के कार्यों में भी विलम्ब हुआ है, और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का उन ग्राहकों के हित की रक्षा के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है जिन्हें इन अधिकारियों द्वारा घमकी दी गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और म्याथ मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) बी० एस० ओ०, "सेल" नई दिल्ली में जे० पी० सी० के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर लोहे और इस्पात की सामग्री सप्लाई की थी।

दिल्ली शाखाओं से सम्बद्ध एक पार्टी से शिकायत मिलने पर "सेल" की आन्तरिक समिति से इसकी जांच करने को कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.1989 को पेश कर दी थी। रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई। पार्टी द्वारा प्रकाशित मुद्दे दिसम्बर, 89 और जनवरी, 90 में लेखा परीक्षा में भी विषय वस्तु थी। वितरण नीति से सम्बन्धित लेखा—परीक्षा में का "सेल" द्वारा उधार दे दिया गया है, और बंकों को अस्वीकार किए जाने से सम्बन्धित अन्य मामले के बारे में उत्तर भेजा रहा है। चूंकि सेल विपन्न संगठन मुख्यालय को इस मामले के बारे में जानकारी मिली है, अतः इन मुद्दों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए "सेल" ने दो बरिष्ठ स्तरीय समितियाँ भी नियुक्त की थीं। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि :—

(i) न तो जे०पी०सी० और न ही "सेल" के आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया।

(ii) शाखा ने अनेक वर्षों से प्रचलित पद्धतियों का अनुसरण किया है।

(iii) सभी बुकिंग सामान रूप से की गई हैं।

दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच करना "सेल" के लिए सम्भव नहीं है। जब कभी भी शिकायतों में दस्तावेज की प्रमाणिकता के बारे में संदेह किया जाता है, तो उनको जारी करने वाले प्राधिकारियों को उन्हें सत्यापित करने के लिये भेजा जाता है।

(ख) सामग्री की सप्लाई मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया के अनुसार की गई है। उठाए गए उल्लिखित मदों की पेशकश किये जाने के समय ई० ई० पी० सी०, रक्षा की कोई भी मांग सम्भव नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में "सेल" टाईगर सफारी की स्थापना

10451. श्री बी० कुल्ल राव : क्या सर्वदल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में "सैकंड टाईगर सफारी" को स्थापलत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यलद हाँ, तो वह किस जगह में स्थापलत की जाएगी और वहाँ रहे जाने वाले वलमलन कलस्म के पशुओं की संख्या कलतनी है;

(ग) क्या "सफारी समूह" को प्रसलद पर्यटन केन्द्र बनाने के ललये वलषेय केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) यलद हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मल्लिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रशन नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रशन नहीं उठता ।

आयकर के छापे

[हलन्दी]

10452. श्री राजबौर सलह : क्या वलस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कल :

(क) गत दो वषों के दौरान आयकर वलभाग ने कलतने बड़ी और सुवलख्यात कम्पनलयों पर छापा मारा;

(ख) छापों में जलन कम्पनलयों में अनलयमतताएं पाई गयीं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छापों के क्या परलणाम निकले हैं ?

वलस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अमलल शास्त्री) : (क) से (ग) आयकर वलभाग ने वलस वष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान कम्पनलयों के परलसरों सहलत वलवलध परलसरों की 11,489 तलाशलयां सी थीं । इन तलाशलियों के परलणामस्वरूप प्रथम दृष्ट्या 280.73 करोड़ रुपये के अनुमानलत मूल्य की लेखा—बाह्य परलसम्पतलयां अभलनूहीत की गई थीं । जलन ब्यक्तलयों की तलाशी गई थी, उन ब्यक्तलयों ने तलाशलियों के दौरान दर्ज कराए अपने बयानों में 442.80 करोड़ रुपये की लेखा—बाह्य आय की घोषणा की है ।

जलन मामलों में तलाशलियों के परलणामस्वरूप प्रथम दृष्ट्या 1 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की राशल की लेखा—बाह्य परलसम्पतलयां अभलनूहीत की गई थी, उनका ब्यौरा संलग्न वलवरण में दलया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	अभिग्रहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)	तलाशियों के दौरान सुपुर्ब की गई छिपाई गई वस्तु की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	श्री गुणवंत सी० गोपानी तथा अन्य, बम्बई।	588.46	368.81
2.	खेतान ग्रुप, कलकत्ता।	446.36	—
3.	डालमिया तथा उसके सम्बन्धित मामले दिल्ली।	381.91	56.40
4.	श्री कान्ति लाल ए० शाह तथा अन्य, बम्बई।	284.82	—
5.	मैसर्स गणेश प्रसाद गोदी लाल एण्ड एसोसिएट्स, कानपुर।	245.16	220.07
6.	डा० एस० पी० श्रीवास्तव तथा श्रीमती लता श्रीवास्तव, नई दिल्ली।	217.45	—
7.	श्री सोमाभाई कंचन लाल पटेल तथा अन्य, बम्बई	206.90	2.00
8.	मैसर्स रेडीफूड्स (प्रा०) लि०, बंगलौर	200.00	—
9.	मैसर्स मल्होत्रा स्टील इण्डस्ट्रीज ग्रुप, अहमदाबाद	200.00	615.00
10.	श्री बल्ली बिलास एम०वी० पावड़े सेंट्रियार सन्स तथा अन्य कुड्डलौर तमिलनाडु	187.12	206.67
11.	मैसर्स बालकृष्ण वेल्स (प्रा०) लि०, बम्बई।	176.30	357.05

1	2	3	4
12. मैसर्स अरुण पोद्दार तथा अन्य, कलकत्ता	173.60		1—
13. श्री लक्ष्मण दास एस० फेरवानी तथा अन्य बम्बई ।	164.09		197.98
14. मैसर्स रंजीत गुप आफ इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद ।	154.91		43.06
15. एम० मुवालका ग्रुप, कलकत्ता ।	153.87		4.30
16. डा० पी० आर० मुखर्जी तथा यू० उपाध्याय ग्रुप, आसनसोल (५० बंगाल)	132.14		205.65
17. श्री गुणवंत राय एच० देसाई, बम्बई ।	124.85		200.00
18. श्री ए०के० अग्रवाल, नई दिल्ली ।	123.98		—
19. हीरा लाल अग्रवाल तथा अन्य, कानपुर	121.34		—
20. हरिपेदा खट्टा, कलकत्ता ।	120.04		100.00
21. मैसर्स सत्य नारायण रस्तोगी तथा अन्य, हरदोई ।	119.60		3.00
22. बागला एण्ड सेमका ग्रुप, नई दिल्ली	119.27		5.14
23. श्री आर० कोटेश्वर राव, हैदराबाद ।	118.69		24.30
24. श्री कांतिलाल डी० शाह तथा अन्य, अहमदाबाद ।	117.43		200.16
25. मैसर्स टेट्रान कमर्शियल लि०, कलकत्ता	117.27		—
26. मैसर्स भावना कंस्ट्रक्शन कम्पनी तथा अन्य, अहमदाबाद ।	111.83		101.95
27. महेश्वरी ग्रुप तथा अन्य, कानपुर	108.02		54.00
28. मैसर्स फोगला ग्रुप मैसर्स तुलसायन ग्रुप } कलकत्ता । मैसर्स गायनका ग्रुप }	106.53		—
29. मैसर्स डी०पी० जैलस तथा मैसर्स विष्णुबाकिता स्वर्ण, अहमदाबाद ।	106.47		55.80

1	2	3	4
30. जे०सी० बुढराजा ब०प, नई दिल्ली ।	105.61	—	
31. मीसर्स बनवारी लाल मोहन लाल ब०प तथा मीसर्स एम० एस० सराफ ब०प, कानपुर ।	103.11	44.31	
32. मीसर्स एम० आर० बंसाली एण्ड कम्पनी, बम्बई ।	101.49	182.40	

केरल में नए होटल खोलना

[अनुवाद]

10453. श्री ए० चार्ल्स : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विदेशों के कुछ प्रमुख होटल उद्योगों ने केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये यहां होटल खोलने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केरल में पर्याप्त होटल सुविधाएं सुलभ कराने के लिए जाने क्या कदम उठाए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने केरल सहित देश में और अधिक होटल स्थापित करने को प्रोत्साहित कर के लिए होटलों को विभिन्न प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाये हैं ।

कुत्रेमुळ लीह अवस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा श्रीह अवस्क का निर्वात

10454. श्री मनोरंजन भक्त : क्या इन्फांट और जवान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 के लिये उक्त कम्पनी द्वारा लौह अयस्क के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और लौह तन्त्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० (के०आई०ओ०सी०एल०) ने लौह अयस्क का निर्यात निम्नानुसार किया : -

भद	निर्यातित मात्रा (लाख मी० टन)	
	1988-89	1989-90
(1) लौह अयस्क सांद्रण	30.0	34.0
(2) लौह अयस्क पैलेट	16.8	19.5
कुल :	46.8	53.5

(ख) वर्ष 1990-91 में कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० की 40 लाख मी० टन लौह अयस्क सान्द्रण तथा 25 लाख मीटरी टन लौह-सा अयस्क पैलेटों का निर्यात करने की योजना है।

(ग) कम्पनी को भारी मात्रा में सप्लाय के आर्डर पहले ही मिल चुके हैं तथा लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है।

बैंक उद्योग सम्बन्धों में नीति

[हिन्दी]

10455. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या बिना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में निश्चित नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे बैंक कर्मचारी किस तरह से लाभान्वित होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

वास्तविक अयस्क का उत्पादन और मूल्य

[अनुवाद]

10456. श्री सत्यनारायण खटिया : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)गत तीन वर्षों के दौरान देश में किन-किन धातु अयस्कों का खनन किया गया;

(ख) उसमें से कितना धातु अयस्क देश में इस्तेमाल किया गया और कितना निर्यात किया गया और कितने मूल्य का प्रत्येक अयस्क निर्यात किया गया; और

(ग) प्रत्येक स्वदेशी धातु अयस्क का और आयातित धातुओं का पृथक्-पृथक् मानक बाजार मूल्य क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा बिधि और म्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक में केम्पना गुडी में केबल कार सुविधा

10457. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक स्थित केम्पना गुडी एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है;

(ख) यदि हाँ, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केम्पना गुडी में "केबल-कार" सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचारार्थान है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी उद्यमियों की योजनाओं को भी मंजूरी देगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ब) यह राज्य सरकार का काम है कि जब भी कनी वैर-सदकारी उद्यमकर्ता ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें, वह उनकी जांच करें।

पूँजीगत वस्तुओं का आयात

10458. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1988-89 के तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं का आयात किया गया; और

(ख) यदि इसमें कोई वृद्धि हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरंगिल श्रीधरम) : (क) 1989-90* तथा 1988-89* के दौरान पूँजीगत माल का आयात निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	1989-90 (जनवरी, 90 तक)	1988-90 (जनवरी, 89 तक)
6905.78	7081.70	5525.32

* अन्तिम

(ख) बढ़ोतरी में योगदान करने वाले अनेक कारक हैं जैसे—प्रौद्योगिकी उन्नयन/निर्यात उत्पादन के लिये आयात मृदा, स्फीति, विदेशी मृदा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव इत्यादि।

नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं खोलना

[विश्वी]

10459. श्री हरीश रावत : क्या बिहार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल/अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कुछ स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बैंक की शाखाएं किन-किन स्थानों पर और कब तक खोलने का विचार है ?

बिहार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं खोलने के लिये अतिरिक्त केन्द्रों के आर्बंटन हेतु नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अल्मोड़ा जिले में मोला तथा लोहारखेत केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिये नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहले जारी किये गये दो लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया है और अभी सम्बन्धित है। चूंकि अपर्याप्त साधारणतः सुविधाओं के कारण बैंक 31 मार्च, 1990 तक

इन केन्द्रों पर अपनी कालाएं नहीं जोत सका था, अतः मास्तीव रिजर्व बैंक ने इन साइसेंटों की वैधता अवधि को सितम्बर 1920 तक बढ़ा दिया है।

चीनी का निर्यात

10460. श्री हरिकेश्वर प्रसाद : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्ती वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीवरन) : चालू वित्तीय वर्ष में चीनी का निर्यात संभवतः निम्नानुसार होगा।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय	10,000 मी० टन
संयुक्त राज्य अमरीका	12,000 मी० टन (औसतन)

उपयुक्त निर्यात, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत के लिए आवंटित अधिमाम्यता कोटों पर होंगे। इसके अलावा, निर्यात पड़ोसी देशों को भी कुछ मात्रा में किए जाने की संभावना है।

मूल औषधों और तैयार दवाइयों का निर्यात

[अनुवाद]

1461. श्री के० मालवेन्द्र सिंह : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल औषधों तथा तैयार दवाइयों के निर्यात के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का तैयार दवाइयों के निर्यात के लिए और प्रोत्साहन देने का विचार है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीवरन) : (क) बल्क औषधियों तथा विनिर्मितियों के निर्यात के लिए प्रदान की गई सुविधाओं में नकद मुआवजा सहायता सी०सी०एस० और आयात प्रतिपूर्ति भी है। नकारात्मक सूची में शामिल 27 मदों को छोड़कर औषधियों के निर्यात पर एफ०ओ०बी० मूल्य के 5% के हिसाब से नकद मुआवजा सहायता स्वीकार्य है। नकारात्मक सूची में शामिल बल्क औषधियों से विनिर्मित औषधियों सहित सभी औषधि विनिर्मितियों पर भी 15% के हिसाब से नकद मुआवजा सहायता स्वीकार्य है।

निर्यात पर बल्क औषधियों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 15% की दर से तथा विनिर्मितियों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 20% की दर आयात प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है।

(ख) सी०सी०एस० प्रदान किए जाने का उद्देश्य गैर छूट प्राप्त अप्रत्यक्ष कर बटकों भाड़ा अलावों तथा निर्यात उत्पाद पर बाजार विकास लागत की उचित ढंग से क्षतिपूर्ति करना है। आयात प्रतिपूर्ति में निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्निविष्टियों का प्रावधान है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्वीकृति हेतु संबित पड़े दूरदर्शन धारावाहिक फीचर फिल्मों

10462. श्री प्रतापराव बी० मोसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में दूरदर्शन धारावाहिक और फीचर फिल्मों की स्वीकृति के लिए संबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन धारावाहिकों और फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक के संबित पड़े रहने के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का संबित पड़े दूरदर्शन धारावाहिकों और फीचर फिल्मों को स्वीकृति देने हेतु अपने वर्तमान मानदंडों में संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन धारावाहिक निर्माताओं द्वारा यदि कोई शुल्क दिया जाता है, तो उसका व्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिकों के अन्तर्गत नए प्रस्ताव स्वीकार करने की स्कीम 7 मई, 1986 से निलंबित कर दी गई थी। इस तारीख तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है और इनको अन्तिम रूप दे दिया गया है। जहां तक बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाली फीचर फिल्मों के प्रसारण के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इनकी जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय फीचर फिल्मों के प्रसारण के प्रस्तावों की छानबीन चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार किसी भी आवेदक को उसके प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए किसी प्रकार का प्रक्रिया शुल्क नहीं देना पड़ता है।

बचत दर

10463. श्री एस० सी० चर्मा : क्या बिस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जापान और दूसरे विकसित देशों की तुलना में वर्ष 1980 के बाद से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में बचत दर कितनी है; और

(ख) सरकार रहन-सहन पर व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, योजनाओं के बास्ते अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बचत दर बढ़ाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है ?

बिस्म मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) अपेक्षित आंकड़े, यथा उपलब्ध, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अर्थव्यवस्था में बचत की दर अनेक उत्पादनों से प्रभावित होती है जैसे व्याज की दर, वास्तविक उत्पादन में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में आय का वितरण। सरकार, बचत के लिए प्रोत्साहन देकर और अनावश्यक उपभोग को हतोत्साहित करके बचतों की दर बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न कर रही है और इस प्रकार योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा रही है।

विवरण

सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सकल घरेलू बचतें

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
भारत*	21	21	19	20	19	20	20	20	21
भाषात	31	32	31	30	31	32	32	34	उ.न.
हिन्दु राज्य बंरमिज	17	18	15	15	16	16	15	13	उ.न.
दू.के.०	19	20	20	18	17	18	18	18	उ.न.
पश्चिम बर्मेनी	25	23	24	23	23	24	24	25	उ.न.
कीर	21	17	17	20	19	19	20	20	उ.न.
एटवी	22	19	20	18	18	18	23	21	उ.न.

*स्रोत : राष्ट्रीय सेवा आंकड़े, 1990 अनुमान पहली अप्रैल से शुरू होने वाले राबकोवीय वर्षों से सम्बन्धित हैं।

स्रोत : विश्व बैंक की वर्ष 1982 से 1989 तक के विभिन्न वर्षों के सम्बन्ध में विश्व विकास रिपोर्टें।

**भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा अन्य शहरों में भी प्रगति
मंदान जैसी सुविधाएं**

10464. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का अन्य शहरों में भी प्रगति मंदान, नई दिल्ली में उपलब्ध सुविधाओं जैसी व्यापार मेला सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो ये सुविधाएं और किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएंगी और हमके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल धीधरन) : (क) और (ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का उद्देश्य न केवल दिल्ली में, बरन अन्य प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों में मेले आयोजित करना है। हालांकि, देश में बम्बई जैसे महानगरों में प्रदर्शनी सम्बन्धी कुछ अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को कुछ प्रस्ताव हैं लेकिन कोई निश्चित परियोजना तैयार नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1987 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक प्रदर्शनी कॉम्प्लेक्स बनाने की सम्भावना पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए टी०एफ०ए०आई० से अनुरोध किया था। टी०एफ०ए०आई० ने ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की शर्तों से उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया। लेकिन, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जवाब न मिलने की वजह से उस प्रस्ताव पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यालयों में विशेष कार्य मत्ता

10465. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या बिस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सभी अंगियों के कर्मचारियों को विशेष कार्य मत्ते का भुगतान करने के लिए 14 दिसम्बर, 1983 के भारत सरकार के आदेश के उपबन्धों के अनुसार, आवश्यक पूर्व प्रमाणी सरकारी आदेश इस बीच जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कौन-कौन से कार्यालय हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है ?

बिस्म मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कमल झात्री) : (क) से (ग) भारत सरकार के 14.12.83 के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों को बिशेष (इपूटी) भत्ता, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों को वहाँ सेवा करने हेतु आकर्षित करने तथा वहाँ पर उनकी सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आदेश उन सभी केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व है तथा जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनात हैं। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे तथा अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से कोई आदेश जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपवादिक किस्म के बहुत ही कम मामलों में अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व की शर्त से लोक हित में छूट प्रदान की गई थी।

यूनাইटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा किराये पर लिये गये रिहायशी फ्लैट

10466. श्री बी० एन० रेडडी : क्या बिस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनাইटेड बैंक आफ इण्डिया ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी फ्लैट पट्टे पर लिए हैं और यदि हाँ, तो आज तक कितने फ्लैट पट्टे पर लिये गये हैं;

(ख) क्या बैंक ने पुराने पट्टानामे समाप्त होने पर नए पट्टानामे करा लिए हैं;

(ग) वर्ष 1989 में और 1990 में (अब तक) कितने मकानमालिकों ने नये पट्टानामों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या मकानमालिकों द्वारा नए पट्टानामों को स्वीकार न किये जाने की स्थिति में तथा उनके द्वारा फ्लैटों को खाली करने का अनुरोध किये जाने पर बैंक ने उनके फ्लैटों को खाली कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस बारे में यदि कोई कार्रवाई की जानी है तो उसका व्यौरा क्या है ?

बिस्म मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अरंगिल जीवरन) : (क) यूननाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उन्होंने अब तक अपने कर्मचारियों के लिये दिल्ली में पट्टे पर 115 फ्लैट लिए हैं।

(ग) बैंक के पट्टा बिल्लों को उनकी समाप्ति पर नवीकरण कराने का प्रयास रहा है।

(ग) बैंक के अनुसार 1989 और 1990 के दौरान (अब तक) 33 मामलों में मालिकों ने पट्टा अनुबन्धों के नवीकरण मंजूर करने से मना कर दिया है।

(च) से (च) बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने मालिकों की वास्तविक दिक्कतों को देखते

हुए अब तक 30 पर्जेंटों को खाली कर दिया है। शेष मामलों में बैंक कोई अन्य व्यवस्था नहीं कर सका है तथा खाली करने के वास्ते मालिकों की मांग की सच्चाई के बारे में भी सदेह नहीं है।

पट्टे/किराये आधार पर भवनों का अधिग्रहण, पट्टा विलेखों का नवीकरण तथा भवनों को खाली करना बैंकों के रोजमर्रा के कार्य हैं और बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय वाणिज्यिक महत्वों को देखते हुए स्वयं लिये जाते हैं। बैंकों के ऐसे रोजाना के कार्यों में सरकार दखल नहीं देती है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को सीमा शुल्क में रियायत

10467. श्री पी०जी० नारायणन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, परिवर्तन लागत और सरकार द्वारा इस कम्पनी में किये गये निवेश को ध्यान में रखने के बाद ही सभी फोटो सुग्राहित वस्तुओं के सम्बन्धित निर्माण हेतु विस्तार कार्यक्रम के लिए लगभग वर्ष 1982 के बाद सीमा शुल्क में रियायत दी गई थी;

(ख) क्या गैर-सरकारी एककों को भी सीमा-शुल्क में रियायत देने में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) संभवतः इस प्रश्न में पूछे गये विषय का सम्बन्ध फोटो-सुग्राहित-माल के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दरों से है। प्रारम्भ में आयात शुल्क में रियायत वर्ष 1976 के आस-पास रंगीन जम्बों फिल्मों को रंगीन चल चित्र फिल्मों हेतु उपयोगी बनाने के लिए आयात करने के लिए दी गई थी। अन्य फोटो-सुग्राहित माल के जम्बो रोलों के आयात के लिए आयात शुल्क की रियायतों को बाद में विभिन्न रियायती दरों पर भी लागू किया गया था। संगत अधिसूचनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध शुल्क सम्बन्धी ये रियायतें हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तक ही सीमित नहीं हैं तथा इनका लाभ कोई भी आयातक उठा सकता है बशर्ते कि वह संगत अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

(ख) और (ग) उपयुक्त (क) में दिये गये उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

10468. श्री एम०एस० पाण्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वित्त निगम ने वर्ष 1989-90 के दौरान ऋण संकट करार तथा वितरित अनेक का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान नए उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी योजनाएँ मंजूर की गईं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और खोबी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) से (ग) दिल्ली वित्त निगम द्वारा सूचित किया गया है कि उसने वर्ष 1989-90 के दौरान ऋण मंजूरी के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथा नए उद्योग लगाने के लिए कुल 561 स्कीमों को मंजूरी दी गई। परन्तु, उक्त अवधि के दौरान संवितरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि पहले छः महीनों की अवधि के दौरान के ऋण आवेदनों की मंजूरी में देरी हुई जिसने ऋण संवितरण पर विपरीत प्रभाव डाला। इसके अलावा कुछ मामलों में ऋण के संवितरण में संवितरण विभाग में भी देरी हुई। निगम ने एक अधिकारी के विरुद्ध पहले ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा बताया गया है कि वह कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए भी विचार कर रहा है।

दूरदर्शन द्वारा 1990 में आयोजित "इन्टरनेशनल टी०वी० प्रोड्यूसर्स मार्केट" में भाग लेना

19469. श्री प्रकाश बी पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने 20 से 25 अप्रैल तक के बीच केनस में आयोजित "इन्टरनेशनल टी०वी० प्रोड्यूसर्स मार्केट, 1990" में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ किन-किन भारतीय फिल्मों को दर्शाया गया;

(ग) इससे दूरदर्शन को क्या लाभ हुआ; और

(घ) क्या वहाँ हमारी फिल्मों की खरीद के लिए कोई पेशकश की गई थी, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी. ज्येष्ठ) : (क) जी हाँ।

(ख) यह समारोह, टी०वी० कार्यक्रमों के खरीददारों तथा बिक्रेताओं का मिलन स्थल है। तदनुसार, दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस समारोह में भाग लिया। कुल मिलाकर, दूरदर्शन द्वारा स्वयं बनाई गई तथा बाहरी निर्देशकों से बनवाई गई 22 टेली-मूवियों तथा पूरी लम्बाई की फीचर फिल्मों समारोह स्थल पर "दूरदर्शन भारत" स्टाल पर प्रदर्शित की गई थी।

(ग) और (घ) "दासी" तथा "मारात्म" नामक दो फिल्मों सहित दूरदर्शन कार्यक्रम सप्लाय करने के लिए, दूरदर्शन द्वारा कान में ही 26,000 अमरीकी डालर के मूल्य के उचितियों पर हस्ताक्षर किए गए। 25,000 अमरीकी डालर मूल्य के कार्यक्रम सप्लाय करने के अतिरिक्त

आर्बर प्राप्त हुए हैं। समारोह में दूरदर्शन दल के विपणन प्रयासों का कई विदेशी खरीददारों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक पूछताछ बराबर होती रहती है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी की पत्रिकाओं की विषयी

[हिन्दी]

10470. श्री आर० एस्० प्रसाद : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं, आदि में से प्रत्येक की इस समय कितनी बिक्री होती है और इनमें से प्रत्येक को कब से प्रकाशित किया जा रहा है;

(ख) उन पत्र-पत्रिकाओं आदि के नाम क्या-क्या हैं जिनका प्रकाशन पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका पुनः प्रकाशन और बिक्री करने के लिए यदि कोई प्रबंध किये जाने हैं तो वे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा सहायक कार्यमन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) "इण्डियन एण्ड फारिन रिव्यू" पत्रिका पहले विदेश मन्त्रालय की ओर से प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती थी। जून, 88 से यह पत्रिका "इण्डिया पर्सपेक्टिव" के नए नाम से, विदेश मन्त्रालय द्वारा निकाली जा रही है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	पत्रिका का नाम	भाषा	अवधि	बिक्री (लगभग)	शुरू होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	बाल भारती	हिन्दी	मासिक	23,300 प्रतियां	19-8
2.	आजकल	हिन्दी	मासिक	7,300 प्रतियां	1945
3.	योजना	हिन्दी	पाक्षिक	16,450 प्रतियां	1957

1	2	3	4	5	6
4.	कुरुक्षेत्र	हिन्दी	मासिक	6,900 प्रतिमा	1955
5.	रोजगार समाचार	हिन्दी	साप्ताहिक	71,600 प्रतिमा	1976
6.	योजना	अंग्रेजी	पाक्षिक	24,750 प्रतिमा	1957
7.	कुरुक्षेत्र	अंग्रेजी	मासिक	9,425 प्रतिमा	1952
8.	एम्प्लायमेन्ट न्यूज	अंग्रेजी	साप्ताहिक	3,16,400—तबैब—	1976

निर्वाचन प्रणाली में सुधार सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

*10471. श्री शिवशरण वर्मा : क्या बिबि और ग्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

हस्तात और खान मंत्री तथा बिबि और ग्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें, संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस समय सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

विवरण

निर्वाचन सुधार विषयक समिति की मुख्य सिफारिशें

1. निर्वाचन आयोग, तीन सदस्यीय निकाय होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विपक्ष के नेता के परामर्श से की जायेगी। अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से की जायेगी।
2. 1981 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों का चकानुक्रमण।
3. बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र की प्रयोग प्रारम्भ करना।
4. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने की अनुमति न दी जाए।

5. गैर संजीदा अम्प्रायियों को हतोत्साहित किया जाए। निर्दोष अम्प्रायियों के प्रतिभूति निक्षेप की रकम बढ़ा दी जाए। डामे गए मतों में से 1/4 से कम मत प्राप्त करने पर प्रतिभूति निक्षेप जप्त कर लिया जाए।
6. आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण उपबन्धों को कानूनी आधार प्रदान किया जाए।
7. सभी भावी निर्वाचनों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाए।
8. वृथ पर कब्जा करने, गड़बड़ी करने और मतदाताओं को अभिभूत करने की कुराई को समाप्त करने के लिए अनेक विधायी उपाय किए जाएं।
9. प्रारम्भ में, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सरकार द्वारा वस्तु रूप में एक सीमा तक सहायता उपलब्ध की जाये।
10. मतदान के दिन मोटरयान चलाने, अम्प्रायुष लेकर चलने, घराब बेचने और उसके वितरण को निर्वाचन अपराध माना जाए।
11. दल परिवर्तन विरोधी विधि के अधीन निरहंता को, स्वच्छता त्यागपत्र देने और विश्वास प्रस्ताव, घन विधेयक या राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव के मामले में दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने या उससे प्रविरत रहने तक ही, सीमित रखा जाए। निर्वाचन आयोग से राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति या राज्यपाल निरहंता के बारे में विनिश्चय करें।
12. वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रश्न पर और अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये।
13. निर्वाचन के सभी विषयों का अध्ययन करने के लिये संसद की एक स्थायी समिति हो।

अमरीका के सहयोग वाली कम्पनियाँ

[अनुवाद]

10472. श्री ई.एस.एम. पाकीर मोहम्मद : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में अमरीका के सहयोग के कार्यरत कम्पनियों का ग्योरा क्या है;

(ख) अमरीकी कम्पनियों की उनमें कुल कितनी भागीदारी है;

(ग) क्या सरकार को व्यापार सीमा में वृद्धि करने के लिए इन कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन आवेदन पत्रों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) 1981 से 1989 के दौरान भारतवाय तथा अमरीकी कम्पनियों के बीच 1376 विदेशी सहयोग अनुमोदित किए गए थे जिनमें कुल 28,202.48 लाख रुपये का निवेश शामिल है।

(ग) और (घ) केवल 40 प्रतिशत से अधिक अतिव्यापी हितवासी कम्पनियों पर ही व्यापार सीमा लागू की गई है। सरकार को इस प्रकार की कम्पनियों से उच्च व्यापार सीमाओं की अनुमति हेतु समय-समय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहे हैं। सुसंगत कारणों, उदाहरण के लिए, अनुसंधान, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन, और निर्यात आदि, को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामलों के आधार पर उच्च व्यापार सीमा की अनुमति दी जाती है।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

10473. श्री इरा अम्बारसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये;

(ख) क्या सरकार का विचार : 1990-91 के दौरान इस राज्य में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान तमिलनाडु में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचमहल जिले में पावागढ़ पर्वत पर एक उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना

10474. श्री शंकर सिंह बघेला }
श्री हरिन पाठक } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
श्री एन. के. रावबा } कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पंचमहल जिले में पावागढ़ पर्वत पर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था क्योंकि विद्यमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर का प्रसारण निकटवर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है जिससे इस क्षेत्र के वाणिज्यिक क्षेत्र लाभान्वित हो सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) हाल में गुजरात सरकार से पंचमहल जिले सहित गुजरात राज्य में अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जिले में गोधरा तथा दोहाद में पहले से कार्यरत दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के अलावा, पंचमहल जिले के कुछ भागों को अहमदाबाद के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर से भी दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। यद्यपि, सरकार का यह प्रयास है कि पंचमहल जिले सहित देश के शेष कवर न हुए भागों में यथार्थांघ दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जाए परन्तु यह काम इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा सकता है।

लोगों को कानून संबंधी जानकारी देने के लिए किए गए प्रयास

10475. **श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान जनसाधारण को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देने और लोगों को मुकदमेबाजी न करने और विवादों का निपटारा आपसी सुलह से करने की उपयोगिता समझाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विमेश गोस्वामी) : विधिक साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा अंगीकृत पद्धतिआत्मक विधिक सहायता कार्यक्रमों में से एक है। समिति, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग एक त्रैमासिक विधिक सहायता समाचार पत्र प्रकाशित कर रही है और समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने संबंधी अपने विचारों और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध करा रही है। विधिक साक्षरता कार्यक्रम के अधीन समिति, निधनों से सम्बन्धित विभिन्न विधियों पर, पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करने के लिए, कुछ शर्तों पर राज्य विधिक सेवा और सलाह बोर्डों, स्वयंसेवा सामाजिक कार्य समूहों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे जन प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है; विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में वृत्त चित्रों और विडियो फिल्मों का निर्माण और निनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन भी विधिक साक्षरता कार्यक्रम का ही एक अंग है।

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, विधिक सहायता शिबिर और विधिक साक्षरता शिबिर/कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। दिल्ली में विवाह परामर्श केन्द्र, गुजरात में शिकायत सेल और चार स्थायी सुलह समितियाँ और तमिलनाडु राज्य में ऐसी ही अनेक समितियाँ कार्य कर रही हैं। जनता में विधिक साक्षरता का प्रसार करने और निवारक मुकदमेबाजी तथा सुलह द्वारा निपटारे के विषय में जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, व्याख्यान, गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, प्रदर्शनियाँ और परा-विधिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष में 40 विधिक साक्षरता शिबिर आयोजित किए गए। आयोजित 248 विधिक

सहायता शिबिरों से, 13,772 लोगों को लाभ हुआ। 487 लोक अदालतों में, 1,15,066 मामले निपटाए गए और 21,24, 50, 086 रु० का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया।

उड़ीसा सरकार की दूसरे सेशन की मांग

10476. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु टेलीविजन के दूसरे चैनल की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : (क) जी, हाँ।

(ख) आठवीं योजना के अंतर्गत, धनराशि उपलब्ध होने पर मुम्बई (कटक) सहित 16 और शहरों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के दूसरे चैनल पर कार्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव

10477. श्री ए० आर० अन्तुले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन और आकाशवाणी के दूसरे चैनल पर कुछ कार्यक्रमों को पूर्णतः गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह पदन ही नहीं उठता।

सीमा-शुल्क मगन की फुटकर दुकान में बिजली के लिए रजे गये गवों का प्रारम्भिक लेख

10478. श्री राज सागर (संबपुर) : क्या बिजली मंत्री उक्त की गई साक्षियों की बिजली के बारे में 30 मार्च, 1990 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2947 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमा-शुल्क मगन की फुटकर दुकान में बिजली के लिए रजे गये गवों

का प्रारम्भिक शेष प्रतिदिन दर्शाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

बिस्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सीमा शुल्क गृहों की सभी फुटकर दुकानों में बिक्री के लिए रखी गयी मशों का प्रतिदिन आदि शेष दर्शाने जाने को संभावना पर विचार किया जा रहा है।

बच्चों के लिए हिन्दी में कार्यक्रम

[हिन्दी]

10479. श्री मोहन लाल सिकराम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर भिकि माउस जैसे बच्चों के कार्यक्रम को हिन्दी में भी प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा सप्तमीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) दूरदर्शन द्वारा इस समय ऐसे कार्यक्रम मुख्यतः अन्तरराष्ट्रीय स्रोतों से खरीदे जाते हैं क्योंकि देश में इनके निर्माण के लिए अपेक्षित सुविधाएँ तथा आवश्यक विशिष्ट विशेषता की कमी है। फिर भी दूरदर्शन का देश में ही इन कार्यक्रमों के निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास है।

पर्यटन विकास के लिये राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाई गई योजना

[अनुवाद]

10480. श्री गुमान मल लोडा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ऐतिहासिक स्मारकों को सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य पर्यटन विकास निगमों के केन्द्रांय सरकार को वित्तीय सहायता और स्वीकृति के लिये ऐसी योजनाएँ भेजी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ख) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन महत्त्व के स्थानों पर प्रकाश पुंज व्यवस्था करने सहित देश में पर्यटन आधारीक-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता देने पर विचार करते समय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुणवत्तियों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

इलेक्ट्रानिकी प्रचार माध्यम की स्वायत्तता देने संबंधी विचार-गोष्ठी

[हिन्दी]

10481. श्री माधवराव तिथिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम की स्वायत्तता देने के संबंध में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य टिप्पणियाँ और सुझाव क्या थे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : (क) दिनांक 16 जनवरी, 1990 को हैदराबाद में प्रकाशन इन्स्टीट्यूट डेवलपमेंट स्टडीज और इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कामर्स द्वारा प्रसार भारती विधेयक पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) इस विचार गोष्ठी के निष्कर्ष और सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती विधेयक में, जो इस सदन में विचारार्थ रखा गया है, संस्थानों अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों पर विचार किया गया है।

विवरण

दिनांक 16 जनवरी, 1990 को हैदराबाद में प्रकाशन इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कामर्स द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों का सार

विचार गोष्ठी में इलेक्ट्रानिक माध्यमों की स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की पहल का स्वागत किया गया और जनता के सम्मुख आम बहस के लिए जिस प्रकार विधेयक को प्राक्य को रखा गया, उसी सराहना की गई ताकि उसमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए जा सकें। विचार गोष्ठी में निगम की स्थापना किए जाने के पीछे निहित भावना और विधेयक से संबद्ध कारणों पर सतोष व्यक्त किया गया। विचार गोष्ठी में विभिन्न सुझाव दिए गए जैसे :—उच्च नीति निर्माण

और निश्चित परिचासन प्रबन्ध कार्यों के बीच में करना आवश्यक है; नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर शासक बोर्ड के स्थान पर न्यासी बोर्ड होना चाहिए; और नियमित परिचासन प्रबन्ध के लिए अलग प्रबन्ध बोर्ड होना चाहिए; अध्यक्ष और अन्य शासकों के नामों की अनुमति करने के लिए गठित समिति में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, विपक्ष का नेता और लोकपाल हों, जब कि प्रेस परिषद के अध्यक्ष को समिति का संयोजक मनोनीत किया जाए; अध्यक्ष और अन्य न्यालयों को देय परिशिष्टियों/मसौं का कानून में उल्लेख किया जाए; दिवालियापन, नियम के अलावा साथ-साथ अदालत नियुक्ति शारीरिक और मानसिक अशक्तता के आधार पर अध्यक्ष और शासकों को हटाने पर विचार किया जाना चाहिए; उद्देश्यों की मौजूदा समीचीन सूची के बजाय यह व्यवस्था करना पर्याप्त होगा कि जनता को सूचना देने उन्हें शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में निगम भारत के संविधान में निहित मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना; गतिविधियों का मौजूदा स्तर पर बनाए रखने और विविध भाषाओं और संस्कृतियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्त व्यवस्था की गारंटी दी जानी चाहिए। अंश्रीय न्यासी बोर्ड भी स्थापित किए जाए।

पंजाब में ऋण-जमा अनुपात

[अनुवाद]

10482. बाबा सुखसा सिंह } : क्या बिल संघी यह बताने की कृपा करेंगे कि :
स० अतिश्वर पास सिंह }

(क) पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कुल कितनी राशि जमा थी;

(ख) इस अवधि के दौरान इन शाखाओं द्वारा कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किये गये;

(ग) क्या पंजाब में ऋण-जमा अनुपात तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय औसत से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार का इस राज्य में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

बिल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल क्षात्री) : पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सदस्यों में पंजाब में कुल बैंक जमा राशियाँ और कुल बैंक ऋण निम्नानुसार हैं :—

(रुपए करोड़ में)

	जमा राशि	ऋण
दिसम्बर 1987	6238	2695
दिसम्बर 1988	7540	3094
दिसम्बर 1989	8226	3660

(ग) से (ङ) पंजाब में ऋण जमा अनुपात 44.5 प्रतिशत है और यह अखिल भारत के 62.84 प्रतिशत औसत ऋण जमा अनुपात से कम है। तथापि, किसी खास क्षेत्र के आर्थिक विकास का अनुमान लगाने के लिए ऋण जमा अनुपात ही एकमात्र संकेतक नहीं है। पंजाब में अपेक्षाकृत कम ऋण जमा अनुपात का कारण कृषि क्षेत्र का बाहुल्य, राज्य में सुदृढ़ सहकारी समितियाँ और उच्च बैंक जमा राशियाँ हैं। पंजाब में व्यापार तथा उद्योग को उनकी दिशक्तियों से बचाने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से, उन्हें ऋण सुविधाओं में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की रियायतें/छूट देने के निर्देश बैंकों को दिये गये हैं।

अनिवासी भारतीयों के निर्यातान्मुख एकक

10483. श्री बामनराव महाडिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने समान भागीदारी के साथ विभिन्न निर्यातान्मुख आयात विकल्प औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये आवेदन किया था ?

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिये क्या मानवण्ड रखे गये अथवा क्या सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) जी, हाँ।

(ख) विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाहुल्य योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तियों को बैंक जमा राशियों में अनिवासी भारतीय निवेश की सुली छूट है। अधिकांश मामलों में अप्रत्याशतनीय आधार पर शत-प्रतिशत निवेश करने की अनुमति है। प्रत्याशतनीय आधार पर निवेश के स्तरों की अनुमति सामान्यतः कार्यकलापों की प्राथमिकता और मामले क गुणाङ्कणों पर निर्भर करता है।

पोर्टफोलियों निवेश के लिए 5 प्रतिशत तक की सीमा है। औद्योगिक उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेश 74 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत योजनाओं सहित, अनेक योजनाओं में अनुमत्य है।

(ग) 31-1-90 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए कुल निवेशों की राशि संघीय रूप से लगभग 19,000 करोड़ रुपये थी जिसमें बैंक जमा-राशियाँ भी शामिल हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

[हिन्दी]

10484. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में रिक्त पड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की वगैरह संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अमिल शास्त्री) : 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987, 1988 और 1989 के अंत तक के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की घर्ती का विछला वकाया बँकन वितरण में दिया गया है।

(आंकड़े अनन्तिस)

क्र० सं०	बैंक का नाम	1989					निपिक	अधीनस्थ कर्मचारी		
		अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.		अ. ज. जा.		
1	2	15	16	17	18	19	20			
Not available										
1.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया									
2.	बैंक आफ इंडिया	10	10	77	98	34	88			
3.	पंजाब नेशनल बैंक	6	6	144	65	58	34			
4.	बैंक आफ बड़ोदा	138	22	59	69	12	9			
5.	सूरी बैंक	—	—	76	88	20	43			
6.	कैपल बैंक	24	10	98	62	17	11			
7.	मार्गस्टेड बैंक आफ इंडिया	14	10	56	37	11	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. सैना बैंक	47	31	12	202	12	37	32	15	16	20	23	28	
9. लिबिटे बैंक	2	5	62	111	24	38	3	5	66	63	31	43	
10. इन्डियन बैंक आफ इरिया	—	—	1	6	—	1	—	4	6	7	—	6	
11. इलाहाबाद बैंक	40	41	107	98	37	67	26	45	110	80	24	60	
12. इंडियन बैंक	9	15	141	95	15	31	12	15	34	65	17	26	
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	3	1	11	15	—	10	—	—	—	8	—	21	
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	1	2	78	40	20	27	2	6	61	25	23	20	
15. वंदाव एंड सिध बैंक	2	—	15	31	60	37	2	—	19	28	52	33	
16. कारपोरेशन बैंक	24	16	52	58	1	14	10	5	56	39	4	16	
17. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6	6	6	28	7	5	6	4	12	12	1	1	
18. सिविल बैंक	6	3	55	46	21	21	—	1	36	31	20	15	
19. न्यू बैंक आफ इरिया	10	5	47	30	27	24	7	1	40	18	26	18	
20. बांध बैंक	8	2	17	13	—	—	6	2	2	3	—	1	

1	2	15	16	17	18	19	20
8. देना बैंक		22	9	8	11	1	4
9. सिडिकेट बैंक		2	1	33	24	7	18
10. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया		5	9	34	21	17	27
11. इलाहाबाद बैंक		17	7	37	39	8	11
12. इंडियन बैंक		6	4	—	—	1	4
13. बैंक आफ महाराष्ट्र		1	—	7	22	2	21
14. इंडियन ओरिएण्टल बैंक		—	—	21	8	9	4
15. पंजाब एण्ड सिख बैंक		1	—	12	14	—	—
16. कारपोरेशन बैंक		6	4	25	17	3	6
17. जोरिण्टल बैंक आफ कामसे		2	—	9	8	2	2
18. बिजस बैंक		—	2	13	12	2	6
19. न्यू बैंक आफ इंडिया		1	—	10	10	1	—
20. बॉम्बे बैंक		—	1	15	8	2	4

उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

10485. डा० महावीर सिंह शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदत्त धनराशि का 30 प्रतिशत भाग अनुदान और 60 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये ऋण राशियाँ विकास कार्यों पर खर्च नहीं की जाती हैं बल्कि इनका उपयोग ऋण और ब्याज की अदायगी हेतु किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उच्च मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 30% अनुदान के रूप में और 70% ऋण के रूप में दी जाती है और पंचतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता 90% अनुदान के रूप में तथा 10% ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश को राज्य योजना के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता राज्य योजना स्कीमों के लिए उपयोग में लाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अलौह धातुओं के मामले में आत्मनिर्भरता

[अनुवाद]

10486. श्री सी० एम० नेगी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलौह धातुओं का वर्षवार कितना आयात किया गया और यह आयात इनकी कुल मांग का कितने प्रतिशत था;

(ख) अलौह धातुओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अलौह धातुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के प्रयोजन से एक नई नीति तैयार करने का और देश को इन धातुओं के अग्रणी निर्यातकों की श्रेणी में शामिल करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य अलौह धातुओं की कुल मांग और आयात मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग (टन)	एमएमटीसी की मार्फत आयात (टनों में)	मांग पर आयात का प्रतिशत(%)
एल्यूमिनियम			
1987-88	3,45,000	57,254	17%
1988-89	3,70,000	शून्य	—
1989-90	4,00,000	शून्य	—

1	2	3	4
तांबा			
1987-88	1,28,000	88,083	69%
1988-89	1,35,000	60,506	45%
1989-90	1,35,000	60,292	45%
जस्ता			
1987-88	1,49,100	71, 57	48%
1988-89	1,53,000	62,883	41%
1989-90	1,53,000	53,395	34%
सीसा			
1987-88	71,900	23,871	33%
1988-89	67,000	21,474	32%
1989-90	65,000	27,768	43%

(ख) और (ग) एस्पूमिनियम के प्रयोग में नेशनल एस्पूमिनियम कम्पनी द्वारा उत्पादन शुरू होने से, देश आत्मनिर्भर हो गया है। हिन्दुस्तान कापर लि., तलोजा (महाराष्ट्र) में 80,000 टन वार्षिक क्षमता का एक सतत तांबा छड़ डलाई सयन लयाया है, जिनसे देश में इस तरह की तांबा छड़ों की मांग काफी हद तक पूरी हो जायेगी। मलजलण्ड ताम्र प्रोजेक्ट (म०प्र०) के समेकित विकास हेतु विस्तृत गवेषण और साध्यता अध्ययन शुरू हो गया है। ऐसा ही अध्ययन सिंहभूम तांबा पट्टी (बिहार) में पूरा हो गया है। देश में जस्ता और सीसा की मांग को काफी हद तक देशी उत्पादन से पूरा करने के लिये, हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा हर साल 70,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीसा उत्पादन हेतु चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के निकट एक बड़ी समेकित परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

सैनिटरी-वेयर और नहाने के साबुनों के निर्माताओं द्वारा

उत्पाद शुल्क का अपवर्धन

[हिम्मी]

10487. श्री रामदास सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सैनिटरी-वेयर और नहाने के साबुनों के निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क अपवर्धन के अनेक मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन निर्माताओं का ब्योरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

बिला बन्नालय में उप मंत्री (श्री अमिल सास्त्री) : (क) जी, हाँ।

(ख) संलग्न विवरण में जिन निर्माताओं के नाम दिए गए हैं उनके विरुद्ध 307.75 लाख रु० के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करते हुए 25 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 14 मामलों में 55.85 लाख रु० की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पुष्टि कर दी गई है और 4.21 लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	कारण बलाबो नोटिस की तारीख
1	2	3
1.	स्वास्तिक सैनिटरी वेयर, कादी	10.5.1989
2.	मधुसूदन सैरामिक्स, कादी	29.3.1989
3.	वही—	19.6.1987
4.	विपूरो लिमिटेड, अमलनेर, जिला जलगांव	16.2.1990
5.	रविन्द्रा इन्डस्ट्रीज, बम्बई	12.2.1990
6.	मोदरेज सोप्स लिमिटेड, बम्बई	28.10.1988
7.	रॉबसन इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	22.12.1988
8.	माडल सोप कं० कलकत्ता	24.5.1989
9.	हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, बहादुरगढ़	18.8.1988
10.	—वही—	29.8.1988
11.	—वही—	29.11.1988
12.	—वही—	30.1.1989
13.	—वही—	22.2.1989
14.	—वही—	31.8.1988
		(अब समाप्त कर दिया गया है)
15.	—वही—	10.4.1989
16.	—वही—	20.8.1989
17.	—वही—	27.9.1989
18.	—वही—	24.1.1989
19.	यूनिवर्सल सैरामिक्स लि०, नालगोण्डा	3.1.1990
20.	गारनेट ग्लास फाइबरी, मद्रास	28.2.1990
21.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, खामगांव	11.8.1989
22.	परशुराम पोटरी वर्क्स लिमिटेड धानगढ़	8.8.1987
23.	सोडियार पोटरी वर्क्स लि० सिहोर	30.11.1987
24.	परशुराम पोटरी वर्क्स लि०, मोरबी	29.7.1987
25.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	29.12.1987

फोटो कार्पिंग मशीनों का उपयोग

[अनुवाद]

10488. श्री बल्लभ सारन कुराना : क्या बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कार्यालयों में फोटो कार्पिंग मशीनों की व्यवस्था हो जाने से भारी संख्या में व्यक्तियों में परिचालित की जाने वाली बहुत अधिक पुष्ठों वाली, बड़ी-बड़ी टिप्पणियां; संक्षिप्त विवरण और रिपोर्टों तक स्टेबिलिज काटकर साइक्लोस्टाइल करने की बजाय भारी संख्या में फोटो कापी करके परिचालित की जा रही हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सर्वे में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी कार्यालयों को इस प्रकार के निदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है कि अधिक पुष्ठों वाले दस्तावेजों की फोटो कापी करने के लिए फोटो कार्पिंग मशीनों का इस्तेमाल न किया जाए; और

(घ) यदि इस प्रकार के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं; तो उनका पालन न करने के क्या कारण हैं और उनका पालन कराने के लिए की गई कार्यवाही का ज्वारा क्या है ?

बिला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल छास्त्री) : (क) भारत सरकार के ब्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है जहां अधिक संख्या में व्यक्तियों में परिचालित करने के लिए बहुत अधिक पुष्ठों वाले दस्तावेजों की फोटोकापी की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार में फिजूलखर्ची से बचने के लिए पहले से ही हिदायतें दी हुई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लिखित है कि लेखन सामग्री में यथा संभव किरायत धरती जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई नई हिदायत जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

फोटोग्राफिक फिल्मों के लिए सीमा शुल्क की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र

10489. श्री शांतिलाल पुष्योत्तम दास पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोटोग्राफिक फिल्मों को सीमा शुल्क की स्वीकृति हेतु पिछले छह महीनों के दौरान (31 मार्च, 1990 तक) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा स्वीकृति प्रदान किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या का राज्यवार ज्वारा क्या है; और

(ख) जेब आवेदन-पत्रों को स्वीकृति-प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जूनिटों का पुनर्वास

10490. श्री के० प्रभासी : क्या बिस् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले उन यूनिटों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1 जनवरी, 1990 के बाद पुनर्वास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या इस वर्ष के शुरू में उद्योगियों के साथ हुई बातचीत में "शिपिंग क्रेडिट इनवेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड" के प्रतिनिधि उपस्थित थे; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के मामले में सरकार की पुनर्वास नीति को शिपिंग क्रेडिट इनवेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड" द्वारा ठीक से लागू किए जाने हेतु यदि कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

बिस् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम को 28 मस्स्यन कम्पनियों के संबन्ध में पुनरुद्धार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो कम्पनियों के सम्बन्ध में पुनरुद्धार पैसेज कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा 8 कम्पनियां अर्धक्षम नहीं पाई गई हैं। 14 कम्पनियों के मामले विचाराधीन हैं। 4 कम्पनियों के मामले में मस्स्यन कम्पनियों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले पर भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। अलबत्ता, कतिपय कम्पनियों ने, जिन्हें पहले अर्धक्षम नहीं पाया गया था, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम/सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव पुन. भेजे हैं।

(ख) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम ने सूचित किया है कि इस वर्ष के आरंभ में उद्योगियों के साथ बातचीत के दौरान उसके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(ग) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम पुनरुद्धार पैसेजों पर प्रत्येक एक की तकनीकी जांच सक्षमता और भारत के सामान्य नीतिगत पैरामीटरों के आधार पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के अनुसार विचार करता है।

तीस हजारों न्यायालय के वकीलों द्वारा हड़ताल

10491. श्री मानिकराव होडल्या गांधी } : क्या बिधि और न्याय मंत्री यह बताने की
श्री आर० एन० राकेश }

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान तीस हजारों न्यायालय के वकीलों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आकषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तब इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने अथवा कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विजय गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली बार एसोसिएशन, तीस हजारों-न्यायालय, दिल्ली के सदस्यों ने दिल्ली न्याया-

सर्वों के द्विमात्रन के मुद्दे पर तारीख 9-4-1990 को अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी।

(ग) सरकार क, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक प्रशासन में कोई परिवर्तन करने का आशय नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लिए एक नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

कच्चे माल का आयात

10492. श्री सन्त कुमार मंडल : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई स्थित अनेक कम्पनियाँ मिथ्या घोषणा और गलत वर्गीकरण करके अपेक्षाकृत कम आयात शुल्क देने के लिए मन्त्रालय और कोषिन पत्तनों के माध्यम से कच्चे माल का आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, उपर्युक्त पत्तनों पर ऐसे गलत वर्गीकरण के मामलों का पता न चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे चोरी-छिपे आयात जिससे राजकोष को भी राजस्व की हानि हो रही है, की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

बिस्स मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल झांसी) : (क) मुम्बई स्थित कम्पनियों द्वारा कच्ची सामग्रियों का आयात मन्त्रालय और कोषिन पत्तनों में भी किया जाता है। मन्त्रालय में एक मामले में तथा कोषिन में सात मामलों में माल के मूल्य/विवरण की गलत घोषणा अथवा गलत वर्गीकरण किये जाने का पता चला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे आयातों के सम्बन्ध में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

पंजाब में व्यापारियों और उद्यमियों की रियायतें

10493. श्री कुसुम कृष्ण शर्मा : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पंजाब में व्यापारियों और उद्यमियों को दी गई रियायतों तथा सुविधाओं का व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन रियायतों की अवधि 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो जाती थी;

(ग) क्या पंजाब में व्यापारियों और उद्यमियों को रियायतें देने की अवधि और जाने बढ़ा दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

बिस्स मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल झांसी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब में असाधारण स्थिति के कारण, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में लाभान्वित करने वाली

कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से, बैंकों से समय-समय पर यह कहा गया है—कि वे पंजाब में ऋणकर्ताओं को निम्नलिखित रियायतें छूटें प्रदान करें :—

- (I) आवा/नियंत्रक अधिकारी स्तर पर ऋण सीमा में 50 प्रतिशत तक त्वर्य वृद्धि वसुलें कि अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये हो। 20 लाख रुपये से अधिक ऋण-सीमाएं उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जावेंगी।
- (II) मार्जिन में कमी ताकि यह 15 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (III) बिलों की उगाही की अवधि में एक महीने की वृद्धि।
- (IV) पात्र मामलों में सावधि ऋणों की किस्तों की अदायगी के पुनर्निर्धारण की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाना।
- (V) डिमांड ड्राफ्ट, अदायगी आदेशों, बैंकर्स चेकों और अन्य प्रेषणों के सेवा प्रसारों में 50 प्रतिशत तक कमी।
- (VI) समय अनुज्ञेय बैंक वित्त के अन्दर-अन्दर ऋणकर्ताओं को उच्चतर-बिल पुनर्मुनाई ऋण सीमाएं प्रदान करना, और बिलों पर निर्धारित किया गया मार्जिन साधारणतया 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी पंजाब में नये उद्योगों को तरजीह दी है और उदार शर्तों पर ऋण दिया है। दी गयी रियायतों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

- (1) पुनर्वित्त योजना के तहत, पंजाब में नये औद्योगिक एककों को।
- (2) 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिया जायेगा और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से संस्थाओं को 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जायेगी।
- (3) जहाँ तक प्रवर्तकों के अंशदान और डी० ई० आर० का संबंध है, संस्थाएं प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर लचीला दृष्टिकोण अपना सकती हैं।

(ख) से (घ) बैंकों द्वारा पंजाब में व्यापार तथा उद्योग को दी गयी रियायतें, जो 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गयी हैं अब 31 मार्च, 1991 तक बढ़ा दी गयी हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन समय पत्राब में उद्योगों के लिये दी गयी रियायतें जो 31 मार्च, 1992 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

ब्राह्म टिनप्लेट का उत्पादन

10494. श्री सनल कुमार मंडल : क्या इस्पात और लाल बंगरी यह बढ़ाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान ब्राह्म टिनप्लेट के कुल स्वदेशी उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और यह कुल बाजार की क्षमता में कितना कम है;

(ग) देश में प्रतिवर्ष भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग तथा गैर-भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए लगभग कितनी मात्रा में टिनप्लेट का प्रयोग किया जाता है;

(घ) क्या टिन निर्माता, विशेषकर लघु औद्योगिक क्षेत्र में रही और घटिया किसम की टिनप्लेट का निर्माण कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का प्राइम टिनप्लेट के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने और भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए घटिया टिनप्लेट के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और लाल मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (हिनेस गोस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न कारकों से टिन प्लेट के स्वदेशी उत्पादन में कमी आई । इनमें टिन मिल ब्लैक प्लेट (टी० एम० बी० पी०) की उच्च आबक लागत, प्राइम टिन प्लेट तथा टिनप्लेट के छिजन के सीधे आयात में वृद्धि और प्लास्टिक पेपर, कार्ड बोर्ड इत्यादि जैसे पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सामग्रियों से स्पर्धा शामिल हैं वर्ष 1989-90 में स्वदेशी उत्पादन कुल अनुमानित मांग के बीच लगभग 1.9 लाख मी० टन का अन्तर है ।

(ग) भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग तथा गैर-भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए देश में इस्तेमाल में लायी जाने वाली टिन प्लेट की मात्रा के सम्बन्ध में अधिप्रमाणित प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) लघु क्षेत्र में टिन प्लेट का निर्माण नहीं किया जाता है । टिन प्लेट के छिजन तथा गीन ग्रेड के टिन प्लेट का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि ये टिन प्लेट के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं ।

(ङ) टिन प्लेटों का उत्पादन करने के लिए और अधिक इकाइयों को अनुमति दी जा रही है । भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए टिन प्लेट बेस्ट बेस्ट के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं है जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं होता ।

भारतीय मत्स्य उद्योग का विकास

10495. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या बालिष्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय मत्स्य उद्योग के विकास हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या "प्रयोजन स्टोरेज रेफ्रिजरेटिड ट्रको" के निर्माण की योजनाएं रद्द कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार को इससे कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

बालिष्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद जीबरेन) : (क) भारतीय मत्स्य उद्योग के विकास हेतु मैरीन प्राइमेट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी एम्पीडा) द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- (1) प्रौद्योगिकीय उन्नयन और मूल्यवर्धन योजना;
- (2) उत्पाद विकास योजना;
- (3) मूल्यवर्धित उत्पादों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का संवर्धन करने संबंधी परियोजनाओं में एम्पीडा द्वारा इक्विटी सहभागिता की योजना;
- (4) समुद्री खाद्य प्रसंस्करण एककों के उन्नयन तथा क्वालिटी नियंत्रण की योजना;
- (5) अण्डजों की सप्लाई के लिए झोंगा मछली पालन के संवर्धन और झोंगा मछली हैचरियां स्थापित करने संबंधी योजना; और
- (6) विदेशों में विशेष कृत वस्तु मेलों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन।

(ख) जी, हाँ।

(ग) ये योजनाएं आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को प्रदान करके समुद्री निर्यात क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरक होने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थीं। इस सीमित प्रयोजन के पूरा हो जाने पर इन्हें बन्द कर दिया गया। इसलिए इन योजनाओं का लाभ अथवा हानि की दृष्टि से यथोचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

सिधिया स्टीम नवौगेशन कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन

10496. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिधिया स्टीम नवौगेशन कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कंपनी में सरकार का कितना हिस्सा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल साहू) : (क) और (ख) कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनर्वास, प्रस्ताव भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लिमिटेड के पास विचारार्थ है।

(ग) भारत सरकार की ऋणों और गारंटियों के रूप में कुल बकाया राशि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार लगभग 178 करोड़ रुपए है।

सिलिका-मैंगनीज का जापान को निर्यात

10497. श्री एस. बी. थोरट : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड द्वारा जापान को सिक्कापाननम से कच्चाई किए गए सिलिका-मैंगनीज भाल की थटिया किसिम के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच-कारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और ज्ञान मंत्री तथा विधि और ग्याय मंत्री (श्री विदेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी, हाँ। महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि. (मेन) ने वर्ष 1988-89 की अंतिम तिमाही तथा वर्ष 1989-90 की दूसरी तिमाही में मलेशिया तथा जापान को सिलिको-मैंगनीज का निर्यात किया था। दूसरा पोतलदान मैसर्स कोटिया इंटरनेशनल, परेबिली टोपो डेगा कोबो कम्पनी लि., जापान तथा मेल के बीच हुए करार के अनुसार था। यद्यपि माल में रासायनिक संमिश्रण विनिर्देशन के अनुकूल था, फिर भी मैसर्स कोटिया ने शिकायत की कि इसमें यह निश्चित मात्रा से अधिक थी। मैसर्स एस. जी. एस. इंडिया प्रा. लि. ने जिसे मैसर्स कोटिया इंटरनेशनल तथा मेल के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत भारतीय एजेंसी नियुक्त किया गया है, ने बाइजाग में अपनी नमूना परीक्षणों के आधार पर माल को नंजूर कर दिया था।

2. यह माना गया है कि जापानी खरीददारों से क्वालिटी के सम्बन्ध में मिलने वाली शिकायतें मेल के वाणिज्यिक हित में नहीं होंगी। अतः मेल के दो बरिष्ठ अधिकारियों का एक दल जापान गया और सामग्री की जांच के बाद सामग्री की स्वीकृति तथा अधिक मात्रा वाली कुछ सामग्री की रिसाईजिंग के लिए जापानी दल को व्यय की प्रतिपूर्ति के बारे में एक समझौते प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए गए।

जापानी दल को यह भुगतान अपरिहार्य था; अन्यथा मेल को भारी क्षति के साथ-साथ अपनी सामग्री को वापस लेना होता।

(ग) निर्यात से सम्बन्धित मामलों पर मेल प्रबंधन द्वारा एक विभागीय जांच की गई तथा इस रिपोर्ट के आधार पर क्वालिटी के बारे में इस प्रकार की शिकायतें बुझा न होने से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेल ने माल के प्रेषण के लिए मलत डंग से मंजूरी देने पर मैसर्स सी. जी. एस. इंडिया प्रा. लि. के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

10498. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितनी विदेशी मुद्रा भेजी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के कितने मामलों का पता लगा और इनमें कितनी घनराशि अन्तर्गस्त है; और

(ग) इस घनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : क। निजी अन्तरण विषयक प्राप्ति, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीयता के अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धन-राशियाँ भी शामिल हैं, का व्योरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1985-86	2716
1986-87	2991
1987-88	3533

(क) "फेरा" के अन्तर्गत पकड़े गए मामलों की संख्या का और उनमें अन्तर्ग्रस्त घनराशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	जारी किए गए कारण बताओ नोटिमें की संख्या	कारण बताओ नोटिसों में अन्तर्ग्रस्त घनराशि
1986-87	6278	40.87 करोड़ रुपए
1987-88	8509	203.48 करोड़ रुपए
1988-89	5077	166.35 करोड़ रुपए

(ग) "फेरा" के उपबन्धों के अन्तर्गत श्याय-निर्णय विषयक कार्यवाहियों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के उल्लंघन करने पर अभियोजन की कार्यवाही करने की भी व्यवस्था है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर कानून के अन्तर्गत यथापेक्षित कार्रवाई की जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बम्बई

10499. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृत्त चित्रों और लघु फिल्मों के लिए मूलतः एक वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाले बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को अब दो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है;

(ग) द्विवार्षिक फिल्म समारोह आयोजित करने में लगभग कितनी घनराशि खर्च होगी;

(घ) क्या कलकत्ता शहर में, जो कभी फिल्मों का सांस्कृतिक केन्द्र था और जिसमें इस प्रयोजन की आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं; यह समारोह कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उषेन्द्र) : (क) जी, हां। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हर दो वर्ष में एक बार अथवा द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाए।

(ख) यह निर्णय 8वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिया गया।

इसके अलावा यह महसूस किया गया है कि बेहतर यह होना कि वृत्तचित्र और लघु फिल्म समारोह तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह बारी-बारी आयोजित किए जाएं।

(ग) वर्ष 1992 और वर्ष 1994 में समारोह पर क्रमशः 62 लाख रुपये तथा 71 लाख रुपये के अन्तिम व्यय का अनुमान लगाया गया है।

(घ) सरकार ने यह समारोह द्विवाषिक आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसलिये कलकत्ता में वर्ष में कम से कम एक बार फिल्म समारोह आयोजित करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है।

तथापि, कलकत्ता में बारी-बारी से फिल्म समारोह आयोजित करने के प्रश्न पर मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समय पर यथोचित विचार किया जायेगा।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

यूको बैंक की स्कीमें

[हिन्दी]

10500. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में यूको बैंक ने योजना-वार विभिन्न योजनाओं में कितनी पूंजी सगाई है;

(ख) इस बैंक की राजस्थान में जिला बार कितनी शाखाएं हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इस बैंक की कितनी जमा राशियां हैं और उसने राज्य में कितने ऋण दिये हैं;

(घ) निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुये हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बैंक में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इसका तत्सम्बन्ध क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री श्री अनिल शास्त्री) : (क) यूको बैंक ने सूचित किया है कि 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के वर्षों के दौरान, विभिन्न योजनाओं में बैंक द्वारा निम्नलिखित निवेश किया गया है :

योजना का नाम	स्वीकृत रकम (लाख रुपये में)		
	1986-87	1987-88	1988-89
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2972	3310	2219
सिखित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना	2296	1346	1780

शहरी शरीरों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम योजना का नाम	496	563	542
	शेष बकाया (लाख रुपये में)		
	मार्च 87	मार्च 88	मार्च 89
विभेदी व्याज दर	2102	1954	1810
2। सूत्री कार्यक्रम	19688	23536	29347
कमजोर वर्ग	20186	24997	29771

(ख) बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.1990 को राजस्थान में यूको बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 135 थी। जिला-वार स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

जिला	संख्या	जिला	संख्या
1	2	3	4
अलवर	2	श्री गंगा नगर	4
भरतपुर	2	जोधपुर	33
जयपुर	39	पाली	1
झुंझुनू	4	अजमेर	7
जुहू	1	भीलवाड़ा	1
सीकर	1	बून्दी	1
टोंक	2	कोटा	5
बाड़मेर	1	नागौर	23
बीकानेर	6	उदयपुर	2

कुल संख्या 135

(ग) यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में बैंक की कुल जमा राशियां और राज्य में दिए गए ऋणों की रकम निम्नानुसार है :—

शेष बकाया (लाख रुपये में)

	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989
जमा राशियां	14642	19510	24364
ऋण	7906	8839	10727

(घ) यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में शहरी उन्मुख कार्यक्रम के अन्तर्गत हितार्थिकारियों की योजना-वार संख्या नीचे दर्शाई गई है

कार्यक्रम/योजना का नाम उन हितार्थिकारियों की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया

	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989
1	2	3	4
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4972	6781	6205
शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना	986	539	618
शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम	1492	1905	1419
उन हिताधिकारियों की संख्या जिनके नाम गृहण बकाया है			
विभेद: ब्याज दर	7683	5518	5570
20 सूत्र कार्यक्रम	32510	37938	44077
कमजोर वर्ग	35603	41039	46731

(इ और च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान में यूको बैंक के कार्यालयों में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याएँ थी। बैंक ने राज्य में अपने शाखाओं के सामान्य कार्यक्रम के वास्ते उपयुक्त कार्यवाही की है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चेयरमैन की नियुक्ति

[अनुवाद]

10501. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल }

(क) क्या किसी सरकारी क्षेत्र के किन्हीं बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तारीख क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के क्या नाम हैं जिनमें चेयरमैन की नियुक्ति अभी की जानी है; और

(घ) ये नियुक्तियाँ कब तक की जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) से (घ) इस समय न्यू बैंक आफ इंडिया के केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद विनांक 11 अप्रैल, 1990 से खाली है। सरकार का इस रिक्त पद को शीघ्र भरने का प्रयास होगा। वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए किसी अध्यक्ष की नियुक्ति के विरुद्ध कोई विशिष्ट, शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भारत पर्यटन विकास निगम का कुल लाभ

10502. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1987 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम को कुल कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो वृद्धि दर क्या है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के किन-किन एककों को सबसे अधिक लाभ हुआ है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) (क) भारत पर्यटन विकास निगम का गत दो वर्षों का कुल कारोबार नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल कारोबार
	(लाख रुपये में)
1988-89	10616.69
1989-90	11854.26
(अनन्तिम)	

(ख) जी, हाँ।

(ग) वर्ष 1986-87 की तुलना में 1989-90 के दौरान कुल कारोबार में हुई वृद्धि (अनन्तिम परिणामों के आधार पर) 42.43% बैठती है।

(घ) अशोक होटल, नई दिल्ली ने 1989-90 के दौरान 248.68 लाख रुपए (अनन्तिम) का अधिकतम लाभ कमाया है।

दंत उपकरणों का आयात

10503. श्री मुल्लापल्लो रामचन्द्रन : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार का चालू वर्ष के दौरान दंत उपकरणों के आयात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दंत उपकरणों पर लगाए गए करों/शुल्कों में वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले कुछ दिनों में दंत उपस्कर पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए दंत उपस्कर पर लगाए गए करों/शुल्कों में हुई वृद्धि के दुष्प्रभावों का

मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कोई अध्ययन किए जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

मैंडक की टांगों का निर्यात

10504. श्री सुल्तापल्ली रामचन्द्रन : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैंडक की टांगों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) प्रथम बार प्रतिबन्ध कब लगाया गया था; और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) प्रतिबन्ध लगाए जाने से पूर्व कुल समुद्री जाल पदार्थों के निर्यात में मैंडक की टांगों की प्रतिशतता कितनी थी?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीवरेण) : (क) और (ख) जी हां, मैंडक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध अब भी लागू है।

(ग) पर्यावरण सम्बन्धी महत्त्व को देखते हुए पहली बार दिनांक 1 अप्रैल, 1987 को प्रतिबन्ध लगाया गया था।

(घ) प्रतिबन्ध लगाए जाने से पहले कुल समुद्री जाल के निर्यात में मैंडक की टांगों के निर्यात की प्रतिशतता वर्ष 1981-82 में मात्रा के रूप में 5.8% से लेकर 1986-87 में 0.5% के बीच रही।

घातु एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा गैर-सरणीकृत

मर्चों का निर्यात

10505. श्रीमती बलुचरा राजे : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घातु एवं खनिज विभाग का वर्ष 1890-91 के दौरान ऐसी मर्चों का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसका निर्यात किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए ऐसे मर्चों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी मदवार ग्योरा क्या है?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीवरेण) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए एम.एम.टी.सी. ने गैर-सरणीकृत निर्यात लक्ष्य 550 करोड़ का निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) एम.एम.टी.सी. ने अनेक गैर सरणीकृत निर्यात समूह बनाए हैं। इन्हीं निर्यात परियोजनाओं के निर्यात पर अलग के ग्रुप डिजाइन ध्यान दे रहा है। एम.एम.टी.सी. निर्यात

के लिए बुनिन्दा मर्दों का पता लगाने के लिए तथा सप्टाई के लिए ऐसे विषयसनीय बरेतू श्रोतों का पता लगाने के लिए बाजार अध्ययन करता रहा है, जो एम.एम.टी.सी. के सहयोगी सप्टायसं के रूप में कार्य कर सकें।

वर्ष 1990-91 के दौरान गैर सरणीकृत मर्दों के निर्वात के निम्न एम.एम.टी.सी. द्वारा विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:—

मर्द	मूल्य (करोड़ रु. में)
खनिज	65
कृषि उत्पाद	25
औद्योगिक उत्पाद	40
हीरे/रत्न	120
वाणिज्यिक कारोबार	15
परियोजनाएं	80
प्रति व्यापार	205
कुल	550

महाराष्ट्र में सातवीं योजना में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

10506. श्री हरीशंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. जयेश्वर) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में दिनांक 4.4.86 को शोलापुर में एक आकाशवाणी केन्द्र थापू किया गया है।

तथापि, आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में महाराष्ट्र राज्य में, कील्हापुर, नासिक, अहमदनगर, धुले, बीड, चन्द्रपुर, नांदेड, अकोला, यवतमास, सतारा और ओस्मानाबाद में एक-एक बर्षात कुल 11 नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें तैयार हैं। इन स्कीमों के 1990-91 के दौरान पूरा किए जाने का आशय है।

(स) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय जर्बंटन और वास्तविक लक्ष्य को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही महाराष्ट्र राज्य में अन्कासावाणी सेवा का और बिस्तार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

[अनुवाद]

10507. श्री श्रीकान्त बल नरसिंह राव बाबिवर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने देश का कुम्बकीय मानचित्र तैयार करने और हवाई भौगोलिक सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये कार्य पूरे किये जा चुके हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने अथवा किसी अन्य संस्था ने समुद्र तल का मानचित्र प्राप्त करने हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने १९४९ से कुल १५ वर्षीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के कुम्बकीय मानचित्र तैयार करने का कार्य आरम्भ किया है जो चालू है। ३६% लक्षित क्षेत्र पर कार्य पूरा हो चुका है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दो ही वर्षों के क्षेत्रीय पैमाने पर आर्थिक एकाधिकार क्षेत्र के ६०% क्षेत्र को समुद्रतलीय मानचित्रण में शामिल कर लिया है।

नमक का उत्पादन

10508. श्री के० एस० राव : क्या बाबिल्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पञ्च तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना नमक का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) "त तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना नमक निर्यात किया गया;

(ग) नमक का निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(घ) क्या नमक बाजार में अंगना देश के प्रवेश से नमक के भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) यदि हाँ, तो कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ब) आगामी वर्षों में नमक का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक का उत्पादन :

वर्ष	मात्रा लाख मी० टन में
1987	99
1988	83
1989	99

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए नमक की मात्रा

वर्ष	मात्रा लाख मी० टन में
1987	4.3
1988	5.5
1989	6.1

(ग) जिन देशों से नमक का निर्यात किया गया वे निम्नलिखित हैं:— बंगला देश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, नेपाल, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, तन्जानिया, उगाण्डा, संयुक्त अरब, अमीरात, जैरे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे ।

(घ) और (ङ) बंगला देश नमक का एक आयातक है और वर्तमान संकेतों के अनुसार अगले कुछ वर्षों तक नमक का आयात करता रहेगा ।

(च) नमक का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों में शामिल है खासकर निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नमक वर्कर्स की स्थापना, नमक विनिर्माताओं को बैंक से वित्तीय सहायता का प्रावधान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नमक विनिर्माण के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र साना, नमक की गुणवत्ता में सुधार करना आदि ।

समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान

10509. श्री जे० चोक्का राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी समाचार-पत्रों के पृष्ठ विज्ञापनों से भरे होते हैं और उनमें समाचारों के लिए बहुत कम स्थान रह जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार विचार समाचार-पत्रों को अलबारी कागज का कोटा आवंटित करते समय विज्ञापनों से होने वाली उनकी आय को ध्यान में रखने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उषेन्द्र) : (क) कैंसेलर वर्ष 1988 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार 345 दैनिकों ने विज्ञापनों के स्थान के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये थे। इनमें से 5 दैनिकों ने विज्ञापनों को 60 प्रतिशत और उससे अधिक स्थान दिया था। 16 दैनिकों ने 50-59 प्रतिशत के बीच स्थान दिया। शेष 333 दैनिकों में विज्ञापनों का स्थान 50 प्रतिशत से कम था।

(ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करना प्रेस की आजादी जिसके लिए सरकार बचनबद्ध है, का, उल्लंघन होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पोषक संबंधी सामग्री का निर्यात

10510. श्री के० एस राव : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पोषक सामग्रियों, सिने-सिलाए कपड़ों, कपड़े की अन्य मर्चों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिन पर कुरान आयतें छपी होती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इसके लिए निर्यात नियन्त्रण आदेश में संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी धोरा क्या है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल जीधरन) : (क) जी, हाँ।

(ख) अजुमन अहले नामक एक मुस्लिम संगठन ने ऐसी पोषक सामग्री/परिधान और अन्य फॅब्रिक्स/वस्त्र मदों के निर्यात के विरुद्ध अभिवेदन किया था, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें छपी हैं, क्योंकि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचता है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) दिनांक 16-3-1990 को सार्वजनिक सूचना सं० 26-ई टी सी (पीन एन) 90 के साथ पठित निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ, 88/ए एम (49) जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आयात-निर्यात नीति 1990-93 (अण्ड-2) की घोषणा करते समय दिनांक 30-3-90 का निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० ई (सी) ओ, 1988/ए एम (50) जारी किया गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र में वस्तुता

10511. श्री प्रकाश कोको लहुरामहू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जा रहे बंधागत ऋणों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की

समीक्षा के लिए गठित एक उच्च स्तरीय स्थायी सलाहकार समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती रुग्णता की प्रकृति पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में बढ़ती रुग्णता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) अप्रैल 1986 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उप गवर्नर की अध्यक्षता में स्थाई सलाहकार समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र की संस्थागत ऋण के प्रवाह और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस क्षेत्र के लिए बड़ी हुई सहायता सुरक्षित करने के वास्ते ऋण प्रदान करने की प्रणाली के कार्यानिष्पादन में सुधार लाने के लिए उगाय सुझाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समिति की समय-समय पर बैठकें होती हैं और इसकी छठा बैठक 21 अप्रैल, 1990 को बुलाई गई थी। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु उद्योगों में रुग्णता की बढ़ती प्रकृति को समिति ने संभरीता से लिया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये मार्गनिर्देश प्रारम्भिक रुग्णता का शीघ्रता से पता लगाने और समय पर उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों को राहत, रियायत उपलब्ध करा के लिए अर्थक्षमता मानदण्ड और पैरामीटर निर्धारित किए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनर्वास सहायता देने के लिए एक पुनर्वित्त योजना तैयार की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1987 में शुरू की गई राष्ट्रीय ईन्विटो निधि योजना भी लघु उद्योग क्षेत्र में संभावित अर्थक्षम रुग्ण एककों को, जो योजना के अन्तर्गत पात्र हैं, पुनर्वास के लिए ईन्विटो जैसी सहायता उपलब्ध कराती है।

सुपर जिक स्मेल्टर प्लांट

10512. श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या इस्पात और लौह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तौड़गढ़ के निकट सुपर जिक स्मेल्टर प्लांट का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा और इसमें उत्पादन कब से प्रारम्भ हो जाएगा;

(ख) क्या इसमें रोजगार देने के मामले में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और लौह मन्त्री तथा बिधि और म्हाय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) चित्तौड़गढ़ के निकट हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड के प्रदायक का कार्य अप्रैल, 1989 में आरंभ हुआ था। जून, 1991 से उत्पादन आरंभ हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) कामगारों की मर्ती, उनकी उपयुक्तता के आधार पर, जिला रोजगार कार्यालय की मार्फत, कां जा रही है। रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को पद की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त न पाये जाने पर, खुले विज्ञापन द्वारा मर्ती की जा रही है।

घरेलू क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देना

10513. श्री चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का घरेलू क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन से अन्य उपाय करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी राशि की बचत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार द्वारा शासित अल्प बचत योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है और अब भी आवश्यकता होती है, सप्रहो को अधिकाधिक करने के उद्देश्य से उनमें परिवर्तन किए जाते हैं।

इसके अलावा, सरकार का प्रस्ताव है कि सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की जमा योजना, 1989 का विस्तारण सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया जाए। राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के अन्तर्गत जमा राशियों की सीमा एक वर्ष में 30,000 रुपये से 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत 5,500 करोड़ रुपये के निवल संग्रह होने का अनुमान है।

खाद्यान्नों का निर्यात

[हिन्दी]

10514. श्री हरिसंकर महाले : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन खाद्यान्नों/दालों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) ये जिन्हें किन-किन देशों को निर्यात की जा रही है;

(ग) पिछले वर्ष कितने मूल्य के खाद्यान्नों/दालों निर्यात की गई;

(घ) चालू वर्ष के लिए इन वस्तुओं के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन जिन्हें का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

बाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीधरन) : (क) और (ख) निर्यात के लिए अनुमत खाद्यान्न है : बासमती चावल, जिसकी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है, और और बासमती चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी और जी जिसकी सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है जो निर्यात बेगीमान की उपलब्धता पर निर्भर होती है। इन सबों की भारी मात्रा का निर्यात मध्य पूर्व देशों, सोवियत संघ, छिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है।

अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, पास हुए के अन्तर्गत या अनुमोदित 100 प्रतिशत निर्यातोग्रहण एकक द्वारा आयातित दालों से बनी संसाधित दालों के अतिरिक्त दालों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान निर्यातित खाद्यान्नों का कुल मूल्य अनुमानतः 427 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ङ) चूंकि सीमित सीमा के अन्तर्गत मदों का निर्यात अनुमानित उत्पादन, खपत और ग्रेजी माल तथा उनकी कीमत प्रतिस्पर्धा क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए खाद्यान्नों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। इन मर्यादाओं के अन्तर्गत परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्धों का सामना करके निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास किए जाते हैं।

अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों की संख्या में कमी

[अनुवाद]

10511. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) निम्नलिखित विवरण में, अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदनों की संख्या औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अनुसूचित प्रस्तावों की संख्या (औद्योगिक अनुमोदनों के लिए सचिवालय) और अनिवासी भारतीय निवेश की प्रस्तावित राशि दर्शाई गई है :—

	1988	1989
(I) प्राप्त आवेदनों प्रस्तावों की संख्या	162	112
(II) अनुमोदित आवेदनों की संख्या	102	54
(III) अनिवासी भारतीय निवेश	(करोड़ रुपए)	
(क) प्रत्यावर्तन आधार पर	17.78	64.26
(ख) अप्रत्यावर्तन आधार पर	28.89	13.59
(VI) परियोजना लागत	228.98	577.08

उपरोक्त तालिका से पता लगता है कि यद्यपि आवेदनों की संख्या में कमी आई है, तथापि भारत में अनिवासी भारतीय निवेश से संबंधित अनुमोदनों में वृद्धि हुई है।

पोत तोड़ने के यादें

10516. गोपीनाथ मल्होत्रा : क्या इस्पात और लौह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोत तोड़ने के यादों की संख्या कितनी है और वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक में कितने पोत तोड़ने की अनुमति दी गई;

(ख) क्या सरकार का उद्देश्य है पारादीप और गोपालपुर में पोत तोड़ने के यादें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ख़ास क्या है ?

इस्पात और लौह मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनोद गोस्वामी) : (क) देश के विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित मेटल स्कैप ट्रेड कारपोरेशन से पंजीकृत जहाज तोड़ने के 95 यादें हैं। इनके अतिरिक्त, बम्बई में लगभग 100 तथा कलकत्ता में 30 जहाज तोड़क हैं जिन्हें जब भी संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा तोड़ने के स्थलों का आवंटन किया जाता है, तो उन्हें जहाज तोड़ने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 1989-90 के दौरान अलग (गुजरात में इस प्रकार के प्रत्येक 3 पंजीकृत यादें को एम.एम.टी सी. द्वारा 3-3 जहाज आवंटन किए गए। इनके अतिरिक्त भार. ई. पी./अतिरिक्त लाइसेंस योजना के अन्तर्गत जहाज तोड़कों द्वारा तोड़ने के लिए 44 जहाजों को सीधे आयात करने की जानकारी मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत को अमेरिकी आर्थिक सहायता बन्द

10517. श्री बमरेश प्रसाद वर्मा } : क्या विस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री चिरा बसु }

(क) क्या अमेरिका ने वर्ष 1991 के लिए भारत के लिए पहले ही निर्धारित 2 करोड़ 50 लाख डालर की आर्थिक सहायता बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

विस्स मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासन द्वारा कांग्रेस के समक्ष रखे गए प्रस्तावों के अनुसार भारत को राजकोषीय वर्ष 1991 में विकास सहायता के रूप में 220 लाख सं० रा० अमेरिकी डालर की राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में कृषि के बचकों का सर्वेक्षण

[बिहार]

10518. श्री तेज नारायण सिंह : क्या विस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकृति को रोकने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

बिहार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) बिहार में पकड़ी गई विभिन्न नशीले औषध द्रव्यों की मात्राओं के संबंध में नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना से उम राज्य में नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार में वृद्धि होने के मामले का कोई संकेत नहीं मिलता है। तथापि हमके नेपाल के समीप होने के कारण, बिहार नशीले औषध द्रव्यों, विशेषतया हशीश और गांजा का अवैध व्यापार किए जाने के लिए एक सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए हमारी प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क रहती हैं। इस क्षेत्र में नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखने के लिए तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित राज्य एजेंसियों के साथ तालमेल रखने के लिए वाराणसी में नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो के एक क्षेत्रीय कार्यालय की भी स्थापना की गई है जिसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार राज्य भी आता है।

लोहे और इस्पात के वितरण के लिए कर्षदल

[अनुवाद]

10519. श्री के० एस० राव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात के वितरण के बारे में सुधारों का सुझाव देने और इस हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिधि और ग्याय मंत्री श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) कार्यदल ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे वर्गीकरण प्राथमिकता संविदा दल पात्रता निर्धारित करने के आधार, लघु उद्योग, नई और रुग्ण इकाइयों आदि की सप्लाई करने की पद्धति का उल्लेख किया है और उनमें से कुछ के बारे में सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

व्यापारिक बैंकों के लिए मार्ग निर्देश

10520. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने हाल ही में व्यापारिक बैंकों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

- (क) यदि हाँ, तो उक्त मार्गनिर्देशों का ब्योरा क्या है;
- (ग) क्या छोटे व्यापारिक बैंकों ने मार्गनिर्देशों में निहित अनुबन्धों पर अपना रोष व्यक्त किया है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;
- (ङ) छोटे व्यापारिक बैंकों के भय को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?
- वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार ने व्यापारिक बैंकों के लिए 9 अप्रैल, 1990 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं।
- (ख) मार्गनिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मार्गनिर्देशों वा, कुल मिलाकर स्वागत किया गया है। संभव है कि कुछ व्यापारिक बैंकों को मार्गनिर्देशों के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में संकोच हो जिनसे उनके कार्यकलाप विनियमित होते हैं। फिर भी भारतीय प्रतिभूति तथा एक्मर्चेंट बोर्ड ने यह बताया है कि अभी तक किसी भी छोटे व्यापारिक बैंक ने मार्गनिर्देशों में परिकल्पित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से लिखित में या मौखिक रूप से कोई विरोध प्रकट नहीं किया है, हालांकि कुछ समाचार पत्रों में उनके बारे में रिपोर्ट छपी हैं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

व्यापारिक बैंकों के लिए मार्गनिर्देश

1. प्राधिकार

व्यापारिक बैंकिंग का कारोबार करने का प्रस्ताव करने वाले किसी भी व्यक्ति या निकाय को भारतीय प्रतिभूति तथा एक्मर्चेंट बोर्ड से उनके निर्धारित फार्मेट में प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह बात उन पर भी लागू होगी जो प्रबन्धकों, निर्गमों के परामर्शदाताओं या सलाहकारों सहित इस समय व्यापारिक बैंकिंग कार्यकलाप में कार्यरत हैं।

2. प्राधिकृत कार्यकलाप

- (क) निगम प्रबन्ध, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विवरण पत्र तथा निगम संबंधी अन्य जानकारी की तैयारी, विसर्पोषण ढांचे का निर्धारण, विसर्पोषणों का संयोजन तथा अमिदान का अन्तिम आबंटन और/या वापसी शामिल हैं।
- (ख) निर्गम संबंधी निगमित सलाह सेवाएं।
- (ग) हमीदारी
- (घ) पोर्टफोलियों प्रबन्ध सेवाएं
- (ङ) निर्गम में प्रबन्धक, परामर्शदाता या सलाहकार

3. प्राधिकार मानदण्ड

सभी व्यापारिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी कार्यों को सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के साथ करेगे भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकों के लिए एक आचरण संहिता निर्धारित करेगा। इसी संदर्भ में भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के प्राधिकार-मानदण्ड में मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा :—

- (क) व्यावसायिक दक्षता।
- (ख) कार्मिक, उनकी पर्याप्तता व गुणवत्ता तथा अन्य आधारभूत संरचना।
- (ग) पूंजी पर्याप्तता।
- (घ) उनके समस्त लेन-देनों में उनका पिछला रिकार्ड, अनुभव, सामान्य रूपाति तथा ईमानदारी।

4. प्राधिकार की शर्तें :

- (क) मौजूदा व्यापारिक बैंकों सहित सभी व्यापारिक बैंकर इन मार्ग निर्देशों के जारी होने के तीन महीने के भीतर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करेंगे। भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड इस अवधि की अपने विवेका-नुसार अधिक से अधिक तीन महीने तक और बढ़ा सकता है।
- (ख) सभी व्यापारिक बैंकों की कम से कम एक करोड़ रुपए की निवल मालियत होनी चाहिए।
- (ग) प्राधिकार आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।
- (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकों से आरम्भिक प्राधिकरण शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क वसूल कर सकता है।
- (ङ) सभी निर्गमों का प्रबन्ध एकमात्र प्रबन्धक या मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने वाले कम से कम एक प्राधिकृत व्यापारिक बैंकर द्वारा किया जाए आम तौर पर, किसी सार्वजनिक निर्गम के लिए मुख्य प्रबन्धक, सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में दो से अधिक व्यापारिक बैंकर सम्बद्ध न किए जाएं। 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निर्गमों में, व्यापारिक बैंकों की संख्या अधिक से अधिक चार हो सकती है।
- (च) निर्गम से पूर्व मुख्य प्रबन्धक की विशिष्ट जिम्मेदारियों भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को अवश्य प्रस्तुत की जाएं।
- (छ) निदेशक, प्रवर्तन तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो विवरण पत्र का निर्गम प्राधिकृत करता है, विवरण पत्र की विषय वस्तु की पूरी जिम्मेदारी लेगा, व्यापारिक बैंकर स्वतन्त्र रूप से विवरण-पत्र की विषय वस्तु और उसमें अभिव्यक्त किए गए विचारों के औचित्य को स्थापित करते हुए सम्पूर्ण तत्परता बरतेंगे। निर्गम

सम्बन्धी व्यापारिक बैंकर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

- (ज) इनके द्वारा प्रबन्ध किए जाने वाले निर्गम में व्यापारिक बैंकर (बैंकरों) का प्रत्यक्ष दावा सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य प्रबन्धकों से निर्गम में उच्चतम सीमा के अधीन रहते हुए न्यूनतम 5 प्रतिशत हामीवारी की बाध्यता स्वीकार करने की अपेक्षा की जाएगी ।
- (झ) मुख्य प्रबन्धक/व्यापारिक बैंकर निवेशकों की प्रतिभूतियों के समय पर आर्बटन और वापसियों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।
- (ञ) व्यापारिक बैंकरों की एक निर्गम में सम्बद्धता कम से कम अनिवार्य अनुवर्ती कार्रवाई पूरी होने तक बनी रहेगी, जिसमें लिखत का सूचीबद्ध करना और प्रमाण पत्रों/वापसियों का प्रेषण कार्य शामिल है । चाहे इनमें से बहुत से कार्यकलाप अन्य मध्यस्थों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी व्यापारिक बैंकर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ये एजेंसियां अपने कार्य पूरा करें और निर्गमकर्ता कम्पनी के साथ उपयुक्त करारों के जरिए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के योग्य हों सकें ।
- (ट) व्यापारिक बैंकर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को ऐसी जानकारी वस्ता-वेज, विवरणियां और रिपोर्टें उपलब्ध कराएगा जो निर्धारित की जाएं या मांगी जाएं ।
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों के लिए आचार संहिता तैयार करेगा और निर्धारित करेगा जिसका उन्हें अनुपालन करना चाहिए ।
- (ड) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड मार्ग निर्देशों के उत्सर्जन होने पर, व्यापारिक बैंकरों के प्राधिकार उपयुक्त अवधि के लिए निर्लंबित/रद्द कर सकता है । ऐसे सभी मामले पूंजी निर्गम नियन्त्रक के ध्यान में लाए जाएंगे । इस बारे में सुसंगत ध्योरे भारतीय बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे ।
- (ड) इन मार्ग निर्देशों में से कोई भी बात कम्पनी उसके कार्यकर्ताओं अथवा अन्य को किसी मौजूदा विधि, विनियम, मार्ग निर्देशों या किसी स्वीकृति सहित लगाई गई शर्त द्वारा री गई किसी की जिम्मेदारी में छूट प्रदान नहीं करेगी ।

निर्यात में प्रत्येक राज्य का अंशदान

10521. श्री चम्पूनाई वैशम्पुः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या उनके मन्त्रालय ने यह जानने के लिए कोई अध्ययन किया है कि गत एक वर्ष के दौरान भारत से किये गये कुल निर्यात में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का अंशदान कितना कितना रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या ऐसे आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं जिनके आधार पर विभिन्न राज्य निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकें ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) राज्यवार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) 19 राज्यों की निर्यात संभावना को बढ़ाने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण/ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने राज्यवार कार्य योजनाएं/सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

पश्चिमी महाराष्ट्र में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

10522. श्री हरीशंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी महाराष्ट्र में जिल्हा-वार कितने-कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र के अनेक गांवों में दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं देखे जा सकते;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी क्षेत्र सहित आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र के करीब आधे गांव राज्य के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। तथापि वास्तविक संग्रहण मध्यमवर्ती दूरी और स्थलाकृति पर निर्भर करता है। चालू वर्ष के दौरान अम्बाजीगई में लगाए जा रहे उच्च शक्ति 10 कि० वा० दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू किए जाने और औरंगाबाद के मौजूदा 1 कि० वा० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने पर दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर होन वाले गांवों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार/सुधार दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन हेतु साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्र

महाराष्ट्र के निम्नलिखित प्रत्येक जिलों में एक-एक आकाशवाणी केन्द्र की व्यवस्था की गई है :—

1. औरंगाबाद
2. बम्बई

3. जलगांव
 4. नागपुर
 5. परगनी
 6. पुणे
 7. रत्नागिरी
 8. सांगली
 9. सोलापुर
- दूरदर्शन केन्द्र

दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों की संख्या

	(2 चैनल)
1. ग्रेटर बम्बई	1
2. रत्नागिरी	1
3. नासिक	3
4. धुळे	3
5. जलगांव	4
6. अहमदनगर	1
7. पुणे	1
8. सतारा	2
9. सांगली	1
10. सोलापुर	3
11. कोलापुर	1
12. औरंगाबाद	2
13. परमनी	1
14. बीड	2
15. नागपूर	2
16. ओस्मानागाड	2
17. बुलढाना	1
18. अकोला	1

1	2
19. अमरावती	2
20. यवतमाल	2
21. वर्धा	1
22. नागपुर	1
23. भंडारा	1
24. चन्द्रपुर	2

रायगढ़ और याणे जिले उच्च शक्ति ट्रांसमीटर बंबई से कवर होते हैं।

महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक साप्ताहिक समाचार-पत्र

10523. श्री हरिशंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्रों को जिले-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखे गए रिकार्ड के अनुसार महाराष्ट्र में पंजीकृत दैनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्रों की दिनांक 31.12, 1988 तक जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिला	दैनिकों की संख्या	साप्ताहिकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	13	14
2.	अकोला	7	41
3.	अमरावती	8	32

1	2	3	4
4.	बीरगाबाव	12	35
5.	बीड	7	10
6.	भण्डारा	8	33
7.	बम्बई	51	194
8.	बुल्ढाना	1	10
9.	चन्द्रपुर	4	17
10.	छुले	5	22
11.	जसगांव	7	27
12.	जासना	3	5
13.	कोल्हापुर	12	17
14.	लतूर	3	4
15.	नागपुर	18	46
16.	नांदेड	7	16
17.	नासिक	11	51
18.	परभणी	6	95
19.	पुणे	20	53
20.	रायगढ़	—	1
21.	रत्नागिरी	4	16
22.	सांगली	9	22
23.	सतारा	6	6
24.	सिधुगढ़	1	2
25.	शोलापुर	10	17
26.	थाणे	6	20
27.	उस्मानाबाद	1	11
28.	वर्धा	3	28
29.	यवतमाळ	8	28

(स) वर्ष 1989-90, 1988-89 तथा 1987-88 के दौरान महाराष्ट्र में अखबारी कामज का जिलेवार आकटन

क्र.स. जिला	1989-90		1988-89		1987-88	
	समाचार पत्रों की संख्या	मात्रा मी०टन में	समाचार पत्रों की संख्या	मात्रा मी०टन में	समाचार पत्रों की संख्या	मात्रा मी०टन में
1. अहमदनगर	8	655.58	5	350.92	5	233.86
2. अकोला	4	118.51	5	93.56	4	193.06

1	2	3	4	5	6	7	8
3. अमरावती		1	42.22	1	33.14	1	15.18
4. औरंगाबाद		9	2893.18	9	2436.05	6	2574.05
5. बीड		1	37.03	1	19.61	—	—
6. भण्डारा		—	—	—	—	1	1.12
7. बम्बई		53	61227.90	61	58094.27	63	52721.84
8. चन्द्रपुर		1	33.11	1	54.58	1	62.19
9. धुले		1	44.79	1	37.56	1	30.45
10. जलगांव		4	905.47	5	916.53	5	906.85
11. कोल्हापुर		5	2117.17	6	1781.20	6	1593.56
12. लतूर		1	43.60	1	16.31	1	56.46
13. नागपुर		12	6929.95	9	6353.83	12	5929.90
14. नांदेड		3	272.64	3	129.97	2	212.50
15. नासिक		9	1234.84	10	1293.94	9	1191.03
16. परभणी		—	—	1	7.16	2	25.49
17. पुणे		13	8556.91	15	5979.64	15	7260.92
18. रत्नागिरी		2	273.60	5	196.70	1	99.91
19. सांगली		2	307.96	3	295.23	2	216.49
20. सतारा		3	369.22	2	148.59	1	96.68
21. सोलापुर		5	950.02	2	650.43	2	432.31
22. रायगढ़		—	—	1	1.18	1	0.82

यूको बैंक के कारोबार की जांच

[अनुवाद]

10524. श्री प्रकाश कोको बहामट } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री एन० जे० रायबा

- (क) क्या सरकार ने यूको बैंक में कारोबार की स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है;
(ख) यदि हाँ, तो सस्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

बिल मंत्रालय में उर: मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं। यूको बैंक में कारोबार की स्थिति की जांच करने का कोई आवेस नहीं दिया गया है।

(ग) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वविवेक से बैंक का वित्तपोषण

10525 श्री प्रकाश कोको बहामदु } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री एम० जे० रायबा

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक दृष्टि से संकट-ग्रस्त बैंकों को उबारने के लिए स्वविवेक से उनका वित्त-पोषण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल कितना वित्तपोषण करने पर सहमति प्रकट की है;

(घ) इससे बैंकों को कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस समय, उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे किन बैंकों को, यदि कोई हैं, सहायता उप-सब्ध कराए जाने का विचार किया गया है ?

बिल मंत्रालय में उर: मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकों को छोड़े समय के लिये स्वविवेक पुनर्वित्त सहायता देता है ताकि बैंकों के संसाधनों और उनकी निधियों के बीच अस्थायी रूप से जो असमानता आ जाती है, उसे दूर किया जा सके। विवेकाधीन पुनर्वित्त, बैंकों की निधि सम्बन्धी स्थिति की शोरचना सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के इरादे से उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को वर्ष 1936-87 में उनकी औसत कुल जमा राशियों के 0.50 प्रतिशत हिस्से के बराबर विवेका-धीन पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके आधार पर, विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमा की कुल रकम 460.63 करोड़ रुपये बैठती है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर, नकदी सम्बन्धी अस्थायी समस्याओं को दूर करने के वास्ते अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त की व्यवस्था कर सकता है। 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बैंकों को वास्तविक रूप से मंजूर की गयी कुल सीमा की रकम 404.92 करोड़ रुपये बैंकों ने इसमें से कुल 277.54 करोड़ रुपये की रकम वास्तविक रूप से निकाली है।

बेलाडिला खानों से लौह-अयस्क का निर्यात

10526. श्री प्रकाश कोको बहामदु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानीज स्टील मिस्स ने लौह-अयस्क की दुलाई के लिए जहाज नामनिर्दिष्ट नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इससे देश के लिए विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है तथा गैलाडिला खानों में उत्पादन रुक गया है;

(घ) क्या सरकार ने यह मामला जापान सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीबरन) : (क) और (ख) अप्रैल में जापानी पस्तनों पर भीड़-भाड़ के कारण जापानी स्टील मिल्स द्वारा जहाजों के नामांकन में कुछ कमी आ गई थी।

(ग) विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि अप्रैल में आई कमी को बाद के महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। तथापि, गैलाडिला परियोजना नं० 5 में उत्पादन दिनांक 17-4-90 से 24-4-90 तक आठ दिनों के लिए रुका रहा।

(घ) और (ङ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) ने यह मामला जापानी क्रेताओं के साथ उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप मई और जून, 1990 के दौरान पर्याप्त संख्या में जहाज नामांकित कर दिए गए हैं।

राजस्थान में पुष्कर और अजमेर की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या

[हिन्दी]

10527. प्रो० रासा सिंह रावत : नया पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के अजमेर जिले में प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर और दरगाह शरीफ स्थल की यात्रा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटक आये और इससे कुल कितने राजस्व की आय हुई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल बलिक) : राज्य सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गत 3 वर्षों के दौरान पुष्कर तथा अजमेर की यात्रा करने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	
	पुष्कर	अजमेर
1987	11,187	6,657
1988	11,889	7,553
1989	14,104	8,097

पर्यटन से होने वाली विदेशी-मुद्रा आय का अनुमान राज्यवार अथवा स्थानवार नहीं लगाया जाता।

भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

[अनुवाद]

10528. श्री मिश्रसेन यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने समूचे देश में अपने यूनिटों/डिबीजनों में अपने कार्यकारी अधिकारियों के लिए ठोस और व्यापक स्थानान्तरण नीति नियम बनाने हेतु वर्ष 1989-90 में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी नियम तैयार किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्थानान्तरण नियमों की व्यापक रूप-रेखा क्या है और इन नियमों को भारत पर्यटन विकास निगम में किस तारीख से अविरोधित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इसी प्रकार के व्यापक और ठोस स्थानान्तरण नियम भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-सरकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी तैयार करके कार्यान्वित किये जाएंगे, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा आयातित फिल्मों पर प्रतिबन्ध

10529. श्री बमेश प्रसाद वर्मा
श्री पी० एम० सईद
श्री माणिकराव होडल्या गावीस
श्री आर० एन० राकेश } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से फिल्मों आयात करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी० जयेश्वर) : (क) और (ख) सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा फीचर फिल्मों के आयात की नीति की पुनरीक्षा कर रही है ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा (अप्रैल, 1990 मार्च, 1993-माग-1) घोषित आयात-निर्यात नीति के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पहले ही फिल्मों का आयात कर रहा है। इसमें विदेशी फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों तथा वीडियो फिल्मों का आयात शामिल हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा यह आयात सरकार द्वारा निगम को जारी की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर सामान्य खुले लाइसेंस के तहत किया जाता है।

नीबें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्टें

10530. श्री धर्मेन्द्र प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीबें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में कुछ विंगतियों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है और सरकार ने इन विंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को रियायती दर पर सहायता

10531. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत को एशियाई विकास बैंक से रियायती दर पर सहायता पाने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने हमारी सरकार से औद्योगिक विनियमों में ढील देने में और औद्योगिक लाइसेंस देने में उदारता बरतने में तेजी लाकर व्यापार में सुधार करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या नई आयात-निर्यात नीति से उदारीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने में सहायता मिली है जिससे निजी क्षेत्र एशियाई विकास बैंक की सहायता का लाभ उठा सके;

(च) यदि हां, तो भारतीयों खासकर निजी क्षेत्र की मंजूर किए गये ऋणों का ब्योरा क्या है;

(छ) क्या एशियाई विकास बैंक ने अपने दाता और सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अपनी भावी कार्य संचारानक पद्धति और नीतियों का अध्ययन किया है; और

(ज) यदि हाँ, तो उस अध्ययन की विशेषकर भारत को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

बिस्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अमिल सास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नहीं निर्यात-आयात नीति में इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

(छ) जी, हाँ,। एशियाई विकास बैंक ने प्रख्यात विशेषज्ञों के एक विदेशी पैनल द्वारा एक अध्ययन करवाया था। और "दशवें दशक में एशियाई विकास बैंक" नामक अपनी रिपोर्ट में इसके विकासशील सदस्य देशों की उमरती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एशियाई विकास बैंक के लिए भावी संक्रियात्मक तरीकों और नीतियों का सुझाव दिया गया है।

(ज) पैनल की सिफारिशों में सामाजिक आधार भूत ढाँचे सम्बन्धी क्षेत्र, विशेष रूप से लोक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नया गरीबी को दूर करने के लिए, बैंक से उधार को बढ़ाना गरीबों पर सभी परियोजनाओं के प्रभाव की जांच करना, रोजगार पहलू पर विशेष ध्यान देना; सभी परियोजनाओं में पर्यावरणीय जोखिमों को कम से कम करके पर्यावरण का संरक्षण करना; पर्यावरण सम्बन्धी नति तैयार करना में विकासशील सदस्य देशों की सहायता करना; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र का सर्वाधन, विकासशील सदस्य देशों के साथ बैंक की नीति सम्बन्धी चर्चा को व्यापक व सुदृढ़ करना, लोक शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं के माध्यम से जनसंख्या के क्षेत्र में बैंक की सक्रियताएँ; नयी प्राथमिकताओं के समर्थन में तकनीकी सहायता देना; बैंक के एशियाई विकास निधि खातों के लिए विकासशील सदस्य देशों की पात्रता का विस्तार करना; दाता सम्बन्धन में सक्रिय भागीदारों, बैंक के सह-वित्तीय कार्यक्रमों का विस्तार, बैंक संक्रियाओं में बिस्तीय नवीकरण करना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक के प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता, छोटे विकासशील सदस्य देशों को बैंक की सहायता देना सम्मिलित हैं।

पर्यटन का विकास

10532. श्री कुसुम कुब्ज मूर्ति : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को कई बातानुकूलन एककों का आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(घ) क्या ऐसे एककों की स्वदेशी स्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है; और

(च) यदि हाँ, तो उनका आयात करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) अभी हाल ही में सरकार ने 300 वातानुकूलन एककों का आगामी 2 वर्षों के दौरान आयात करने के लिए अनुमति प्रदान की है जिसके लिए भारत पर्यटन विकास निगम को 50 प्रतिशत की घटी हुई दर पर इन आयातों के सम्बन्ध में नोटल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

(ख) अभी तक कोई पक्की कोटेशन प्राप्त नहीं हुई है परन्तु ऐसी सम्भावना है कि 2 वर्ष की अवधि के दौरान 10.50 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

(ग) और (घ) देश में निमित्त बस वातानुकूलक विदेशी पर्यटकों को बेसा आराम नहीं दे पा रहे हैं जिसके वे आदी होते हैं, इसलिए वातानुकूलक एककों को आयात करने की जरूरत महसूस की गई। इन आयातों से भारत पर्यटन विकास निगम सहित पर्यटन उद्योग को विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

लघु उद्योग समूह द्वारा नई आयात निर्यात नीति की आलोचना

10533. श्री समरेन्द्र कुण्डू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग समूह ने सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई आयात-निर्यात नीति के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियाँ की हैं;

(ख) क्या उन्होंने इन सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो लघु उद्योग समूह किन-किन पहलुओं पर यह महसूस करता है कि उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) आयात-निर्यात नीति, 1990-93 की घोषणा के बाद नीति में निहित कुछ प्रावधानों के खिलाफ कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, मूलभूत रूप में ये सुझाव निर्यात स्तर की मंजूरी के लिए निर्धारित उस न्यूनतम सीमा से सम्बन्धित हैं जोकि पहली नीति के दौरान 2 करोड़ रु० की तुलना में नई नीति में निबल विदेशी मुद्रा आय के आधार पर 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। प्राप्त अभिवेदनों के आधार पर निर्यात सदन के रूप में मान्यता के लिए न्यूनतम स्तर उपयुक्त परिवर्तों व्यवस्थाओं के साथ अब 4 करोड़ रुपये तक (निबल विदेशी मुद्रा अर्जन आधार पर) कम कर दी गयी है। ताकि निर्यात सदनों को निर्यात के उपयुक्त स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

प्रौद्योगिकी बिस्स और विकास के लिए भारतीय औद्योगिक बिस्स निगम की योजना

10534. श्री लाल कृष्ण आडवाणी } : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री शंकर सिंह बघेल }

(क) क्या प्रौद्योगिकीय अविव्कारों को बढ़ावा देने और देश में इनके वाणिज्यिकीकरण के लिए, भारतीय औद्योगिक बिस्स निगम द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी बिस्स निगम

लिमिटेड द्वारा आवश्यक वित्त समर्थन की व्यवस्था कराने के लिए वर्ष 1988 के अंत में प्रौद्योगिकी वित्त और विकास की एक नई योजना आरम्भ की गई थी;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ग) साफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेंस, एजुकेशनल रोबोट्स डिजिटाइज्ड फोन्ट्स कीटनाशी और संकर बीज के लिए "इन्टरमिडियेट्स" के क्षेत्रों में किन परियोजनाओं की सहायता की गई;

(घ) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की तथा कितने पूंजी-निवेश की सम्भावना है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिक वित्त निगम लि० ने 1988 के अन्त में प्रौद्योगिक वित्त एवं विकास की एक योजना शुरू की थी और मंजूरीयां 1989 के शुरू से आरम्भ की गई।

बताया गया है कि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कुल 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। उल्लिखित निम्नलिखित क्षेत्रों में मंजूर की गई कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजना का नाम
1.	साफ्टवेयर विकास	सिस्टम्स डायनिमक्स प्रा० लि० नई दिल्ली।
2.	कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेंस)	मिथान्ति इन्जीनियर्स प्रा० लि० कनकता।
3.	शैक्षिक रोबोट	प्रवाक साइबरनेटिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।
4.	अकीय समुच्चय (डिजिटাইज्ड फोंट)	आई० टी० आर० ग्राफिक प्रा० लि०, पुणे।
5.	कीटनाशकों के मध्यस्थ	मेवाड़ आयल एण्ड जनरल मिल लि०, उदयपुर ट्राबनकोर कोचीन केमिकल्स लि०, उद्योग मंडल, केरल
6.	संकर बीज	हिन्दुस्तान एग्रीजेनेटिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं में, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं परिकल्पित निवेश 1696 लाख रुपये हैं और 640 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम का वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल 12 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर करने का प्रस्ताव है।

**महाराष्ट्र में वर्ष 1988-89 के दौरान स्थापित किए गए दूरदर्शन
प्रसारण केन्द्र**

10535. श्री बसन्त साठे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : महाराष्ट्र में वर्ष 1988 और 1989 के दौरान किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किये गये और प्रत्येक प्रसारण केन्द्र की क्षमता कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : महाराष्ट्र में वर्ष 1988 और 1989 के दौरान चालू किए गए टी०वी० ट्रांसमीटरों के स्थान और उनकी क्षमता का व्योरा नीचे दिया गया है :

चालू होने का वर्ष	स्थान	ट्रांसमीटर
1988	गडचिरोली	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
	पुसाड	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
1989	अमलपुर	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
	अमलनर	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
	वर्शी	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
	बम्बई	उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.)

(द्वितीय चैनल के लिए 1 कि.वा. ट्रांसमीटर के स्थान पर)

चालिस गांव	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
डिंगलुर	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
हिंगोली	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
इच्छलकरंजी	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
किनवट	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
कराड	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
मनमाड	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
नन्दुरबार	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
उस्मानाबाद	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
पन्डरपुर	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
पुणे	उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.)

(0.6 कि.वा. ट्रांसमीटर को बदलकर)

साहय	अ.श.ट्रा. (100 वाट)
तर्धा	अ.श.ट्रा. (100 वाट)

नागपुर में एल्यूमिनियम अनुसन्धान संस्थान

10536. श्री बलराम साठे क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर में एल्यूमिनियम अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने का विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिचि और म्याय मंत्री (श्री विमल गोस्वामी) : (क) जी हां, सरकार ने नागपुर में अब्राहम साल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसन्धान विकास तथा डिजाइन केन्द्र की स्थापना का मजूरी दी है; जिसकी अनुमानित लागत यू. एन. डी. पी. की 4.11 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता राशि सहित 15.94 करोड़ रुपये है।

(ख) नागपुर में केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि मिल गयी है। इस स्थल पर आधार-भूत सुविधायें जुटाने का आरम्भिक कार्य शुरू हो गया है। उपकरणों की खरीद तथा वैज्ञानिकों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती का काम चल रहा है। यू. एन. डी. पी. के अन्तर्गत केन्द्र निदेशक तथा मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति हो गयी है। हंगरी के मैसर्स एलुतर्व—एफ. के. आई. को अन्तर्राष्ट्रीय सब-कन्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया है।

केन्द्र को रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

भंडारा, महाराष्ट्र में मैंगनीज/क्रोमाइट अयस्क भंडार

[हिन्दी]

10537. प्रो० महादेव शिबनकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मैंगनीज और क्रोमाइट अयस्क के बहुमूल्य भंडार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां जनन कार्य शुरू कर दिया गया है और क्या सरकार को इस संबंध में 29 जनवरी, 1990 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिचि और म्याय मंत्री (श्री विमल गोस्वामी) : (क) भंडारा जिले के डूंगरी बुजुर्ग, बिकला—एवं हिवाडा असोलपानी नौ गांव-हिवाडा जी० एफ० काग्लो तथा जी० एफ० भवानचली क्षेत्रों में मैंगनीज के तथापावणी में क्रोमाइट के भण्डार होने की सूचना है।

(ख) और (ग) अभी केवल डूंगरी बुजुर्ग, चिकना एवं हिवाड़ा और मैगनीज खानों में खनन हो रहा है।

महारा जिले के चन्डी गांव में मैगनीज और क्रोमाइट अयस्क होने और उनके खनन की संभावनाओं के बारे में माननीय सदस्य का 2-1-1990 का पत्र मिला था। भारतीय खान ब्यूरो की मार्फत इस बाबत जांच करायी गई, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि चन्डी गांव में मैगनीज तथा क्रोमाइट अयस्क नहीं है।

औरंगाबाद महाराष्ट्र में आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाना

10538. प्रो० महादेव शिचनकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की वर्तमान प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता से वृद्धि करने का है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग)

आकाशवाणी

आकाशवाणी, औरंगाबाद में इस समय 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर है। इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

दूरदर्शन

दूरदर्शन की अनुमोदित सान्नी योजना में औरंगाबाद के अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर उच्च शक्ति (10 किलोवाट) करने की स्कीम शामिल है। औरंगाबाद में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगा दिया गया है और यह 7-5-90 से 1 किलोवाट कम की गयी शक्ति पर कार्य कर रहा है। योंकि दूरदर्शन टावर से सम्बन्धित कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। टावर पूरा हो जाने पर इस ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू करने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि

[अनुबाद]

10539. श्री श्री. एन. बासबराज } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्रीमती बासब राजेश्वरी }

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के लिए सहायता देना है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

बिना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) में (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अप्रैल, 1990 में गौहाटी, असम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना की है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण एवं शहरी निर्धन तथा शारीरिक रूप से विकलांग और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में लगी या परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगी स्त्री-व्यक्तियों को स्थापित करना, उनका विकास करना, उन्हें सहयोग देना तथा विकसित करना है। आरम्भ में संस्था का उद्देश्य अपने कार्यों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ही सीमित रखना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का दो करोड़ रुपये तक की संचित निधि (कोरपस फण्ड) प्रदान करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत है।

चमड़े और चमड़ा उत्पादों का निर्यात

10540. श्री जे० चोक्का राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़े और चमड़ा-उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए बाजार संबंधित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निर्यात के कड़े अभियान के लिए कौन-कौन से विशिष्ट बाजारों का पता लगाया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीवरन) : (क) चमड़े उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने वाले बाजार संबंधित उपायों में विशेषीकृत उत्पादों के लिए सर्वेक्षण, क्रेता-विक्रेता संगठन की बैठक आयोजित करना विक्रय स्थल का प्रायोजन देना, विशेषीकृत वस्तु मेरों में भाग लेना आदि तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रीय सहायता एवं सहयोग योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकियों को डिजाइन एवं विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ख) पश्चिम यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान कठोर निर्यात अभियान के अन्तर्गत खोजे जा रहे विशेष बाजार हैं।

बैंक और विदेशी संस्थाओं में नतीं हेतु प्रश्न-वच

[हिन्दी]

10541. कुमारी उमा भारती : क्या क्या बिना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनमें सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी माध्यम से देने की अनुमति नहीं दी जाती है और प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार नहीं किये जाते हैं; और

(ख) इन परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से उत्तर देने की अनुमति कब तक प्रदान की जायेगी और प्रश्न-पत्र दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जबकि बैंकों के लिए झुली भर्ती परीक्षा विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती है, विभागीय पदोन्नति परीक्षाएँ प्रायः बैंकों द्वारा स्वयं ली जाती हैं या बैंक कर्मचारी चयन संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषिक रूप में तैयार किये जाते हैं और उम्मीदवारों की परीक्षाओं में हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाता है।

अधिकांश बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ अपनी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दे रही हैं और परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप में दिये जा रहे हैं। सरकार ने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से सभी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम उपलब्ध करवाने तथा बिना किसी और देरी के प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप से तैयार करने के काम को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

शुल्क-मुक्त पूंजीगत का सामान का आयात

[अनुवाद]

10542. श्री बालासाहिब बिडे पाटिल } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री रामदास सिंह }

(क) क्या सरकार ने निर्यात अनुबंध के एवज में कुछ औद्योगिक इकाइयों को शुल्क मुक्त पूंजीगत सामान का आयात करने की अनुमति इस शर्त पर दी है अथवा दी जायेगी कि उन्हें अपने उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अनिवार्यतः निर्यात करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) राजस्व विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने घरेलू टेरिफ क्षेत्र में स्थित एककों के लिए निर्यात दायित्व के बदले शुल्क मुक्त पूंजीगत सामान के आयात को न तो अनुमति दी है और न ही अनुमति देने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करना

10543. श्री कवल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब में स्थापित किए गए आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब में और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (बी पी. उषेन्द्र) : (क) से (ग) पंजाब राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान किसी आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है। तथापि, आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में पंजाब राज्य के भटिन्डा और पटियाला में 2×3 किलोवाट एक० एम० ट्रान्समीटर्स, बहु प्रयोजन स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टरों सहित एक-एक अर्थात् कुल दो नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों के 1990 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

पत्रकारों की काम की दशा

10544. प्रो० विजय कुमार बरहोबा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सम्बद्ध स्वतंत्र पत्रकारों के काम की दशाओं और उनको मिलने वाले भुगतान के बारे में अध्ययन करने का विचार है ताकि उनका शोषण न हो, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ख) उनकी काम की दशाओं में सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (बी पी० उषेन्द्र) : (क) और (ख) आकाशवाणी या दूरदर्शन के माध्यम से स्थायी आधार पर कोई स्वतंत्र पत्रकार सम्बद्ध नहीं है। विभिन्न विषयों में पत्रकारों की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यक्रमों के लिए उन्हें बुलाया जाता है और वर्तमान नियमों के अनुसार उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा आय कर अपव्ययन

10545. श्री बरसराय भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृह गैस्ट हाउसेज के रख-रखाव पर भारी मात्रा में व्यय किया कर आय कर अपव्ययन कर रहे हैं जब कि वास्तविकता यह है कि इन गैस्ट हाउसेज का इन कंपनियों के निदेशकों के आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस्ट हाउसेज पर प्रत्येक वर्ष में किए गए अनुमानतः व्यय का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (बी अमिल शास्त्री) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 37 (4) के अधीन किसी रिहायशी आवास के रख-रखाव पर किसी कर-निर्धारती द्वारा एक अतिथि गृह के रूप में उस पर किए गए किसी व्यय को उचित कर निर्धारित की कुल आय की संगणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाती है। यदि किसी कम्पनी का कोई निदेशक उचित कम्पनी के किसी भवन का इस्तेमाल; जिसमें अतिथि-गृह भी शामिल है, यशोचित किराए की अदायगी किए बिना ही अपने रिहायशी-योगियों के लिए करता है तो आयकर नियमावली के अनुसार संगणित की गयी परिलब्धियों के मूल्य को-उचित निदेशक की कुल आय में शामिल किया जाता है तथा उस पर कर लगाया जाता है।

(ख) बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से संबंध रखने वाली कम्पनियों द्वारा, जिनके नाम विनि-दिष्ट नहीं किए गए हैं, विगत तीन वर्षों के दौरान अतिथि-गृहों के रख-रखाव पर किए गए व्यय के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की उन सभी कम्पनियों के कर-निर्धारण विषयक फिकाडों का हवाला देना अपेक्षित होगा, जिनका समूचे देश में विविध कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण किया जाता है। इस सूचना को हतारों फाइलों में से एकत्र करने में किया जाने वाला प्रयास तथा लगाया जाने वाला समय उसकी उपयोगिता के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) चूंकि अतिथि गृहों के दुरुपयोग को कर-अपवंचन का एक तरीका महसूस किया गया था, इसलिए उपर उल्लिखित आयकर अधिनियम की धारा 37 (4) के उपबन्धों को बनाया गया था ताकि आयकर विभाग को किसी रिहायशी आवास के रख-रखाव पर एक अतिथि-गृह के रूप में उस पर किए गए समूचे व्यय को अनुमति नहीं देने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण की समय-सीमा से प्रतिबन्ध हटाना

10546. श्रीमती बासब राजेश्वरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों की समय-सीमा पर लगे प्रतिबन्ध को हटाए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (बी पी० उदयेन्द्र) : (क) के (ग) 10

सैंकिड की न्यूनतम निर्धारित अवधि के अलावा प्रसारण के लिए वाणिज्यिक विज्ञापन की सम्झाई पर प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, किसी विशेष कैपसूल के लिए विज्ञापनों को स्वीकार करना सम्बन्ध कैपसूल अवधि पर निर्भर करता है।

एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक

10547. श्रीमती वासन्त राजेश्वरी } : क्या बिरा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री जी० एस० वासन्तराज }

(क) क्या हाल में एशियाई विकास बैंक की तेइसवीं वार्षिक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक की नीतियों के निर्माण में विकसित देशों की बहुत अधिक दखलअन्दाजी और ऋणों के लिये शर्तें निर्धारित करने से विकासशील देश परेशानी में पड़ गए; और

(ग) इस वार्षिक बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

बिरा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक की नीतियां निदेशक बोर्ड द्वारा तय की जाती हैं, जहाँ एशियाई देशों की शेयरों में भागीदारी बहुमत में है।

(ग) एशियाई विकास निधि में आगामी पुनः भरण चौथी सामान्य पूंजीगत वृद्धि, विकास-शील देशों में निम्नतर बढ़ती गरीबी और टर्की तथा मंगोलिया दोनों देशों के बैंक में प्रवेश सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, इन मामलों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

तलाशी और जब्ती के मामले

10548. श्री मनोरंजन अस्त : क्या बिरा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार, तलाशी और जब्ती सम्बन्धी कितने मामलों में कर अपबन्धन का मूल्यांकन किया जाना बाकी है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान कोई अभियोग चलाए गए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

बिला मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार तलाशी एवं अमिग्रहण के मामलों में 16,211 कर-निर्धारण विचाराधीन थे।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान 8,929 अमियोजन की कार्यवाहियां शुरू की गईं। जिनमें से 595 कार्यवाहियां कर-अपवंचन के लिए शुरू की गईं।

लोह और इस्पात सामग्री का वितरण

10549. श्री नकुल नायक
श्री केशरी लाल
श्री ए० विजयराघवन } : क्या इस्पात और लौह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या शाखा बिक्री कार्यालय, स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से लाइसेंस युक्त क्षमता तथा पार्टियों की माल उठाने सम्बन्धी हकदारी के मानदण्डों का उल्लंघन करके इस्पात का वितरण किया है;

(ख) विभागीय प्रतिनिधि/सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा क्रमशः दिनांक 21-10-89/1-1-1990 और 26-12-89 को दर्शाया गया मारी अनियमितताओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्टों से सम्बद्ध पार्टियों का, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् अपनी मांग में परिवर्तन करने की अनुमति देने, कम्प्यूटर गणना के बाद बुकिंग लेने अधिक मात्रा में बुकिंग करने और अधिक माल के व्यावहारिक रूप से निर्गम की गयी के रूप में पक्ष लिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्टों से सम्बद्ध प्रत्येक पार्टी का इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत अप्रैल, 1989 से जून 1990 तक का प्रति तिमाही ब्योरा, उसकी लाइसेंस क्षमता, कम्प्यूटर गणना के हिसाब से मांग की तुलना में मद/मात्रावार निर्गम, मद-वार माल उठाये जाने/बुक की गयी और निर्गम की गयी मदों/मात्राओं से सम्बन्धित हकदारी के विवरण सहित, क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

इस्पात और लौह मंत्री तथा बिधि और ग्यायमंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) बी० एस० ओ० सेल; नई दिल्ली ने जे० पी० सी० के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर लोहे और इस्पात की सामग्री सप्लाई की थी।

दिल्ली शाखाओं से सम्बद्ध एक पार्टी से शिकायत मिलने पर सेल की आन्तरिक समिति से इसकी जांच करने को कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21-10-1989 को पेश कर दी थी। रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गयी। पार्टी द्वारा प्रकाशित मुद्दे दिसम्बर, 89 और जनवरी, 90 में लेखा परीक्षा भेजो की थी बिषय बस्तु थी।

वितरण नीति से सम्बन्धित लेखा परीक्षा मेमो का "सेल" द्वारा उत्तर दे दिया गया है, और चेकों को अस्वीकार किये जाने से सम्बन्धित अन्य मामले के बारे में उत्तर भेजा जा रहा है। चूंकि "सेल" विपणन संगठन मुख्यालय का इस मामले के बारे में जानकारी मिली है अतः इस मुद्दों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए "सेल" ने दो बरिष्ठ स्तरीय समितियाँ भी नियुक्त की थी। समित इस निष्कर्ष पर पहुँची कि :—

(I) न तो जे० पी० सी० और न ही "सेल" के आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया था।

(II) शाखा ने अनेक वर्षों से प्रचलित पद्धतियों का अनुसरण किया है।

(III) सभी बुकिंग सामान रूप से की गई है।

(ग) मांग पंजीकरण का एक बाहरी कम्प्यूटर एजेंसी द्वारा सारंशकृत किया है। इसके साथ-साथ सारांश हाथ से भी तैयार किया जाता है। हाथ से तैयार सारांश का प्रयोग आर्डर बुक करने के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर से तैयार किए गए सारांश तथा हाथ से तैयार किए गए सारांश में कुछेक भिन्नता समिति की जानकारी में आई हैं। हालांकि शाखा को पंजीकरण की अन्तिम तारीख बढ़ाने का अधिकार है फिर भी पंजीकरण की अन्तिम तारीख और कम्प्यूटर सारांश तैयार करने की तारीख में परस्पर निवेशन (जो सामान्यतया चार सप्ताह से अधिक नहीं होती) को नकारा नहीं जा सकता। सतर्कता को इस मामले की ओर अधिक जांच करने के लिए कहा गया है। इसी बीच पुनरावृत्ति से बचने के लिए कार्रवाई की गई है। निवेशन, यदि कोई हो, से उन अन्य पार्टियों को मिलने वाली सप्ताह में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिन्होंने तिमाही के दौरान सप्ताह के लिए पंजीकरण करवाया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जापान को निर्यात

1055C. डा० बेंकटेश कावड़े : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जापान को चमड़े का सामान, जिलोनों, और हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात करने में किन्हीं परेष्ठानियों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो उससम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का जापान को उपयुक्त वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरुणिल श्रीबरन) : (क) व्यापार मंडल ने इस मन्त्रालय को कोई ऐसी सामान्य कठिनाइयां नहीं बताई हैं, जिन्हें जापानी सरकार के साथ उठाया जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, क्रोता-विक्रोता बैठकों का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और भारत में उत्पाद विकास-प्रयास।

हंगरी को लौह अयस्क के टुकड़ों का निर्यात

10551. श्री वी० कृष्णराव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने कर्नाटक के कुद्रेमुख से लौह अयस्क के टुकड़े आयात करने के लिए एक सोदे पर हस्ताक्षर किये हैं ?

(ख) यदि हां तो, हंगरी द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का लौह अयस्क के टुकड़ों का आयात करने का विचार है और इस सोदे की अवधि कितनी है,

(ग) क्या हंगरी कुद्रेमुख से लौह अयस्क टुकड़े आयात करने वाला प्रथम देश है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा बिधि और ग्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के. आई. ओ. सी. एल.) ने वर्ष 1990 तक के लिएबंध, एक तीन वर्षीय करार किया है जिसके तहत वर्ष 1990 में 6.0 लाख मी. टन पैलेटों का निर्यात किए जाने की संभावना है। मूल्यों के बारे में बताना वाणिज्यिक रूप से कम्पनी के हित में नहीं होगा।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने हाल ही में आगामी 4 वर्षों (1991 से 1994 तक) के लिए हंगरी को पैलेटों का निर्यात करने हेतु एक अन्य करार किया है। आपूर्ति की जाने वाली मात्रा का दायरा 4.0 लाख मी. टन से 7.5 लाख मी. टन वार्षिक के बीच रहेगा। इन आपूर्तियों के मूल्य का निर्धारण संविदागत फार्मूला के आधार पर प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) हंगरी को अब तक निर्यात किए गए प्लेटों की मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टन)
1986-87	0.94
1987-88	4.35
1988-89	5.94
1989-90	5.31

छापों के दौरान स्वर्ण और नक्कीले पदार्थों का जस्त किया जाना

[हिन्दी]

10552. श्री राजवीर सिंह क्या बिना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों का व्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान जस्त की गई नकदी, सोना, तस्करी के सामान तथा मादक पदार्थों आदि का व्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा पार से तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

बिना मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। तस्करी-रोधी तन्त्र को विविधतया तटीय तथा भू-सीमाओं और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों तथा समुद्र पत्तनों के सुगम्य स्थानों पर मजबूत बना दिया गया है। एक्स-रे असबाबी मशीनों, धातु खोजी यन्त्रों, रात को प्रयोग में लाई जाने वाली दूरबीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का—अधिक-अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने में कार्यरत सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

बैंक लाकरों से चोरी

10553. श्री राजवीर सिंह : क्या बिना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1989 के दौरान बैंक लाकरों से गहनों की चोरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1989 के दौरान बैंक आफ महाराष्ट्र के अमृतसर शाखा में 7/8 जनवरी, 1989 को एक सेंधमारी की घटना की सूचना दी गई थी, जिसमें 44 सेफ डिपाजिट लाकर टूटे पाए गए थे। इसके अलावा, ग्राहकों की दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक केनरा बैंक की मंसूर शाखा और दूसरा देना बैंक की पार्क सर्कस (कलकत्ता) शाखा के संबंध में थी, जिनमें लाखों में से कुछ आभूषणों के लापता होने का आरोप लगाया गया है।

(ग) लाखों के रख-रखाव और संचालन के लिए बैंकों के अपने आंतरिक अनुदेश/मार्ग-निर्देश होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए कहा है जिनमें विशेष रूप से बाल्ट की अवस्थिति, लाखों का प्रकार, सेंधमारी अलार्म प्रणाली की आवश्यकता और स्थानीय पुलिस के साथ सम्पर्क पर जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की कुछ शाखाओं का अध्ययन भी किया है और अपने अध्ययन के आधार पर बैंकों से कहा है कि वे कमियों को दूर करके प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि सुरक्षा खर्चा कर्मों से वस्तुओं की क्षति न हो।

जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को दी गई वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

10554. प्रो० के० बी० चामस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इन योजनाओं का व्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम को तत्काल क्षतिपूर्ति की गई है; और

(ग) केरल की कौन-कौन सी योजनाएं जीवन बीमा निगम के विचाराधीन हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कोई नहीं।

विवरण

(क) पिछले तीन सालों के दौरान केरल की समाजोन्मुखी योजनाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश।

		(करोड़ रुपए)		
आयोजना-क्षेत्र		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	राज्य सरकार सामाजिक आवास योजनाएं	7.33	7.36	10.62
2.	जल-आपूर्ति/मल-जल योजनाएं	6.60	8.61	9.47
3.	राज्य विद्युत बोर्ड	8.34	9.17	10.10
4.	राज्य सड़क परिवहन निगम	3.93	3.23	3.55
आयोजना मिन्न क्षेत्र				
1.	शिखर (एपेक्स) सहकारी आवास वित्त सोसाइटी	11.00	12.00	13.00
2.	केरल स्वास्थ्य अनुसंधान और कल्याण सोसाइटी	—	—	0.40
(1.70 करोड़ रुपए 1989-90 के दौरान स्वीकृत किए गए थे)				

(ख) अन्य वर्गों के अंतर्गत निवेश

		(करोड़ रुपए)		
		1987-88	1988-89	1989-90 (अव्ययित)
1	2	3	4	5
1.	राज्य सरकार प्रतिभूतियां	13.20	15.09	17.28
2.	भूमि विकास बैंक ऋण-पत्र	11.72	6.80	9.43
3.	विद्युत बोर्ड बांड	5.00	5.50	6.00
4.	वित्तीय निगम बाण्ड और शेयर	—	—	1.50
5.	निवमित क्षेत्र (शेयर ऋण-पत्र और कंपनियों को ऋण)	11.77	6.35	नगण्य नहीं होता

काजू का निर्यात

10555. श्री ए० चार्ल्स : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का संसाधित काजू निर्यात किया गया;

(ख) चालू वर्ष में काजू निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) काजू का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) काजू निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्त अनन्तित आंकड़ों के अनुसार 1989-90 के दौरान निर्यात किए गए काजू की गिरी मात्रा एवं मूल्य क्रमशः 45,196 मीट्रिक टन तथा 363.52 करोड़ रुपए थे ।

(ख) 1990-91 के दौरान काजू गिरी के निर्यात का अनुमानित लक्ष्य 400 करोड़ रुपए निर्धारित किया है । इसमें संशोधन किया जा सकता है ।

(ग) काजू गिरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (1) निर्यात खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है;
- (2) काजू गिरी के निर्यात पर 10% की आर० ई० पी० प्रदान की गई है;
- (3) एक किलो या उससे कम के उपभोक्ता-पैकों में भूनी एवं नमकीन काजू गिरी के निर्यात पर 8% की नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई है;
- (4) विदेशों में स्थित भारतीयों मिशनों द्वारा प्रचार विभिन्न विदेशी भाषाओं में संवर्धनात्मक साहित्य का प्रकाशन और विदेशों में उसका वितरण किया जाता है ।
- (5) आयातकों के साथ सम्पर्क को मजबूत करने एवं बढ़ाने के लिये तथा समस्याओं का पता लगाने के लिये निर्यातकों के शिष्टमंडल ।

केरल को वित्तीय सहायता

10556. श्री ए० चार्ल्स : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान केरल को नियोजित योजनाओं के अन्तर्गत आर्बिट्ररी अनुदान राशि के अलावा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(क) किन उद्देश्यों के लिये यह सहायता दी गई और प्रत्येक मामले में किसनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने दी गई सहायता को सही ढंग से और पूरा खर्च किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन मामलों में आबंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया था दुरुपयोग किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगिन्दा लाल) : (क) और (ख) राज्य की वार्षिक योजना तथा उस वर्ष की केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त केरल सरकार को 1989-90 के दौरान कुल 636.03 करोड़ रुपये की राशि दी थी, जो नीचे दिखाई गई है :—

		(करोड़ रुपये)	
मदें		राशि	प्रयोजन
1	2	3	4
(1)	केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा	455.90	आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य को संसाधनों का अनन्तरण
(2)	रेल यात्री किराए पर कर के बढ़ने अनुदान	3.42	—तईव—
(3)	प्रशासन के स्तर को सुधारने के लिये अनुदान	0.87	नवें वित्त आयोग के कार्यों के लिये 65.00 लाख रुपये और आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रशासन के स्तरों को सुधारने के लिये 22.26 लाख रुपये।
(4)	सबू बच्चों को निवास उपाधियों के प्रति ऋण	144.43	सबू बच्चों की इकाइयों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन
(5)	बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	24.06	बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास और

(I) योजना निम्न अनुदान	19.56	बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त
(II) सीमान्त राशि का केन्द्र का हिस्सा	4.30	सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत/पुरख़दार करने के लिए।
(6) 1989-90 में सूखे के कारण केन्द्रीय सहायता (1988.89 का खर्च आदि छोड़कर)	7.35	सूखे के कारण सूखे द्वारा प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए।
जोड़	636.03	

(ग) और (घ) केन्द्राय करों और शुल्कों में हिस्सा तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत रेलवे यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान राज्य को सामान्य सहायता के स्वरूप के थे तथा इस प्रकार उनका जारी किया जाना किसी विशेष प्रयोजन से जुड़ा हुआ नहीं था। इसी तरह से, राज्य में निवल उगाहियों के आधार पर दिए गए लघु बचत ऋण किसी विशेष प्रयोजन से नहीं जुड़े हुए थे।

प्रशामन के स्तर को सुधारने और प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिये केन्द्रीय सहायता स्कीमों में हुई प्रगति/पूरा होने के आधार पर दी गई थी।

प्राकृतिक रबड़ की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर

10557. श्री ए० चार्ल्स : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती का विस्तार करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने हेक्टेयर नू-क्षेत्र पर रबड़ की खेती शुरू की गई; और

(घ) अधिक उपज देने वाले रबड़ के पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य संचालक में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द जीबरेन) : (क) देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा किए जा रहे मुख्य उपायों में

शामिल हैं : रबड़ की खेती का विस्तार करके स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना। इस कार्य के लिए आवश्यक आयात भी किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हाँ। गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करना, पौध-शालाओं की स्थापना करना, विस्तार सेवाओं का प्रावधान, रबड़ बागान विकास योजना के तहत आपूर्ति और प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता देना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ के अन्तर्गत नायें गये क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1987-88	4,000
1988-89	6,000
1989-90	8,000 (अनन्तित)

(घ) रबड़ बोर्ड द्वारा स्थापित पौध-शालाएं छोटे मूस्वामियों को रियायती दरों पर रोपण सामग्री वितरित करती है। इसके अलावा गैर-सरकारी मूस्वामियों और रबड़ उपजकर्ताओं की समितियों द्वारा संचालित पौधशालाएं भी रबड़ उपजकर्ताओं को अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री देती हैं।

10558. श्री श्रीकांत बल नरसिंहराज बाडियर : क्या इस्पात और ज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ऐलुमिनियम का उत्पादन कर रहे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐलुमिनियम के उत्पादन में वृद्धि किए जाने की दिशा में सरकारी क्षेत्र की उक्त कम्पनियों की क्या उपलब्धि रहा है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना में ऐलुमिनियम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और ज्ञान मंत्री तथा बिबि और म्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) ऐलुमिनियम धातु का उत्पादन करने वाली सरकारी सेक्टर की दो कम्पनियाँ भारत ऐलुमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) तथा नेशनल ऐलुमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) हैं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान बाल्को का उत्पादन 90% अधिक मात्रा पर हुआ।

नाल्को ने वर्ष 1987-88 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और 25,753 टन का उत्पादन किया, जो क्रमशः बढ़कर सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 में 135,018 टन हुआ।

(ग) और (घ) जो हाँ, आठवीं योजना के दौरान कुछ प्राथमिक ऐल्युमिनियम उत्पादक का आधुनिकीकरण और अपनी वर्तमान क्षमता के विस्तार का कार्यक्रम है।

रज्य-वार दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

10559. श्री ए० विजयराघवन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं; और

(ख) पूरे केरल में कब तक दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाए जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रवार और जनसंख्यावार दूरदर्शन कवरेज संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 तक कालीकट में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (विद्यमान अल्प शक्ति) :00 वाट (ट्रांसमीटर को बदलकर) के चालू हो जाने पर केरल के लगभग 97 प्रतिशत क्षेत्र को दूरदर्शन कवरेज के अंतर्गत लाने की उम्मीद है। (इनमें सीमावर्ती सेवा प्राप्त करने वालों के क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ सन्तोषजनक संग्रहण प्राप्त करने के लिए ऊँचे एन्टीना और बूस्टर आदि की आवश्यकता होती है) केरल में दूरदर्शन कवरेज में और सुधार, इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	टी. वी. कवरेज (25 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार कवर होने वाले क्षेत्र का प्रतिशत)	कवर हुई जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	52.7	68.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.0	44.4
3.	असम	73.1	80.8

1	2	3	4
4.	बिहार	74.0	78.2
5.	बोवा	100.0	100.0
6.	गुजरात	63.0	76.8
7.	हरियाणा	96.6	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	37.2	58.7
9.	जम्मू और कश्मीर	26.2	89.8
10.	कर्नाटक	44.4	57.1
11.	केरल	84.0	86.3
12.	मध्य प्रदेश	43.5	52.1
13.	महाराष्ट्र	50.0	68.0
14.	मणिपुर	31.3	66.4
15.	मेघालय	94.6	97.2
16.	मिज़ोरम	42.1	53.1
17.	नागालैण्ड	43.4	47.2
18.	उड़ीसा	50.0	65.5
19.	पंजाब	100.0	100.0
20.	राजस्थान	29.9	51.8
21.	तमिलनाडु	89.5	89.2
22.	सिक्किम	36.6	63.1
23.	त्रिपुरा	93.3	93.3
24.	उत्तर प्रदेश	75.8	87.6
25.	पश्चिम बंगाल	94.3	95.1
संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.00	99.0

2. चंडीगढ़	100.0	100.0
3. दादर और नागर हवेली	40.0	43.6
4. दिल्ली	100.0	100.0
5. दमण और दिव	100.0	100.0
6. पाण्डिचेरी	100.0	100.0
7. लक्ष द्विप समूह	99.00	99.0
राष्ट्रीय औसत		55.3
		76.7

नोट : 1. उपरिलिखित कवरेज आंकड़ों में सीमान्त क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ सतोषजनक रिसेप्शन के लिये ऊँच एंटीना तथा बूस्टर आदि लगाने पड़ते हैं।

2. कवरेज आंकड़ों का परिकलन करते समय भूभागीय परिस्थितियों को हिसाब में नहीं लिया गया है।

खाने क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्ति

10560. श्री मनोरंजन भक्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितना क्षेत्र खान क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;

(ख) खान क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को लाने की क्या समग्र योजना बनाई गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खान कार्य के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों से कितने व्यक्ति विस्थापित हुए और वर्ष 1990-91 में कितने व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) देश में खान पट्टों के अन्तर्गत समाहित कुल क्षेत्र 9,26,923 हेक्टर है।

नये क्षेत्रों को खान कार्यों के अन्तर्गत लाना क्षेत्र की खनिज सम्पन्नता और खनिज की मांग सहित विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। इस बारे में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं है।

खान क्षेत्रों से सामान्यतः बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन नहीं हुआ है। बड़ी खान परियोजनाओं के प्रसंग में कुछ विस्थापन होता है और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का ज़रूरत होती है तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उनके पुनर्वास के उपाय अनिवार्यतः किचे जाते हैं।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लोह की खरीद और निर्यात

10561. श्री गोपीनाथ वल्लभति रायू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न लोह अयस्क खानों में लोह अयस्क का भण्डार जमा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने लोह अयस्क की खरीद और निर्यात कम कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जरंगिल बीबरन) : (क) और (ख) जापानी इस्पात मिलों द्वारा विज्ञापन पत्र के लिए जहाजों के नामांकन में हुए बिलम्ब के फलस्वरूप बेला-डोला खानों पर अप्रैल, 1990 में लोह अयस्क के कुछ स्टॉक जमा हो गए थे जिसका कारण जापानी पत्तनों पर भीड़-भाड़ होना था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काफी बोर्ड के बिजली केन्द्र

10562. श्री एच०सी० श्रीकांतय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में काफी बोर्ड के बिजली केन्द्र सप्ताह में पांच दिन चलते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार जनता की सुविधा के लिए इन बिजली केन्द्रों का छः दिन का सप्ताह लागू करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जरंगिल बीबरन) : (क) और (ख) जी हाँ। काफी बोर्ड के सभी कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय सप्ताह (40 घंटे) को देखते हुए यह महत्वपूर्ण होगा कि काफी बोर्ड के रिटेल डिपों के लिए पूरक मानदंड अपनाया सम्भव नहीं होगा।

विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्र और कवर आपरेशन

10563. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली में विदेशी मुद्रा लेन-देन केन्द्र खोले हैं और वहाँ डीवरों को नियुक्त किया है जिससे विदेशी मुद्रा लेन-देन और कवर आपरेशन को विकेन्द्रीकृत किया जा सके जो अब तक इसके विदेशी मुद्रा विभाग, कलकत्ता में केन्द्रीकृत थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने केवल वाणिज्यिक आवश्यकताओं और विदेशी बैंकों सहित अन्य बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा के मामले में होने वाली प्रतियोगिता के कारण ही बम्बई, मद्रास और दिल्ली में लेन-देन कक्ष स्थापित किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, इन केन्द्रों में लेन-देन कक्षों की स्थापना के बाद भी विदेशी मुद्रा का कार्य और कवर आपरेशन का काम केन्द्रीय रूप से विदेश विभाग, कलकत्ता में ही किया जा रहा है।

पर्वतीय पर्यटन स्थानों पर होटलों का निर्माण करने की योजना

[हिन्दी]

10564. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विदेशी पर्यटकों को आवास सम्बन्धी और अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से देश के पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थानों पर होटलों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक आवासों का विकास करने के लिए होटल उद्योग को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) जी, हां। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों पर बनने वाले होटलों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से, पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 फुट से ऊपर स्थापित नए अनुमोदित होटलों को, जिनमें उचित मानक (3-स्टार और उससे ऊपर) के 300 से अधिक कमरे हों, 10 वर्ष की अवधि के लिए व्यय कर से छूट मिलेगी और साथ ही आय-कर अधिनियम की धारा 80-आई के अंतर्गत कर में 50% की छूट भी दी जाएगी बशर्ते कि होटल दिसम्बर 1993 तक चालू हो जाए।

(ग) और (घ) होटलों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई है।

उत्तर प्रदेश में भारभूता में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

10565. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पिबौरागढ़ जिले के कुछ सीमान्त क्षेत्रों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं पहुँचते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस क्षेत्र के निवासियों के हित के लिए धारचूला में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार को अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वहाँ पर 1990-91 में एक आकाशवाणी केन्द्र मंजूर करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी० ज्योत्सना) : (क) उत्तर प्रदेश के पिबौरागढ़ जिले के सीमान्त क्षेत्रों में मोडियम वेव पर आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं पहुँचते हैं। तथापि, इस जिले में शाटवेव पर लखनऊ तथा दिल्ली से सेवा उपलब्ध है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान धारचूला में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। धारचूला को लखनऊ तथा दिल्ली के 10 कि० मा० शा० वेव ट्रांसमीटरों से शाटवेव सेवा प्राप्त हो रही है। आकाशवाणी के सातवीं योजना प्रस्तावों में लखनऊ तथा दिल्ली के शाटवेव ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाकर 50 कि० मा० शा० वेव करने की स्कीम शामिल है। जब ये ट्रांसमीटर चालू हो जाएंगे तो आशा है कि धारचूला सहित समूचे पिबौरागढ़ को अतिरिक्त शाटवेव सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

फलों का निर्यात

10566. श्री हरीश रावत : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान फलों के निर्यात हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में फलों का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) किन-किन फलों का निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

बाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद जीवरतन) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान फलों के निर्यात हेतु कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात सम्बर्धन के प्रयोजन से सरकार द्वारा गठित दि एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्राउक्टेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है जिनमें कृता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और नए बाजार विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, आदि शामिल हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान फलों के निर्यात का पक्का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण आदि जैसे अनेक

कारकों पर निर्भर करेगा। जिन फलों का निर्यात किया जा रहा है उनके नाम हैं : आम, अंगूर, सेब, चीकू, नीबू जाति के मल, तरबूज आदि।

उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में बैंक शाखाएं खोलना

10567. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(ख) वे किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के भांडा और मुक्खु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दो शाखाएं खोली गई थीं।

विदेशी बैंक

[अनुवाद]

10568. श्री एम० एम० फल्लम राजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से विदेशी बैंक चल रहे हैं तथा इनकी शाखाएं कहां-कहां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इन सभी विदेशी बैंकों को कितना-कितना लाभ हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इन बैंकों की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि/निक्षेप कितना-कितना रहा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन बैंकों ने कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा सांविधियों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घेनाइट का निर्यात

10569. श्री एम० एम० फल्लम राजू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितना परिष्कृत घेनाइट प्रतिवर्ष निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) किन-किन देशों को अधिकृत परिष्कृत घेनाइट निर्यात किया जाता है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कौन-कौन से देश भारत के मूल प्रतिस्पर्धी हैं; और

(घ) घेनाइट उद्योग को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

व्यापिक्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीवरन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टाइम्स सहित पालिश किए हुए घेनाइट का अनुमानित निर्यात निम्नलिखित है :

1987-88	—	895 लाख रुपए
1988-89	—	1400 लाख रुपए
1989-90	—	2300 लाख रुपए

(ख) पालिश किए हुए भारतीय घेनाइट के मुख्य क्रेता जापान, ब्रिटेन, यू.एस.ए. पश्चिम जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर हैं ।

(ग) भारतीय घेनाइट के प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन, दक्षिण कोरिया, ताजील, दक्षिण अफ्रीका, यू.एस.ए. कनाडा आदि हैं ।

(घ) घेनाइट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में से कुछ नीचे दिए गए हैं—तरासे गए और पालिश किए गए घेनाइट के निर्यात उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन, घेनाइट के पट्टों के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थायी नीतियों की घोषणा करना, प्रयासों के लिए घेनाइट उद्योग को यूस्ट क्षेत्र में शामिल करना आदि ।

बिदेशों में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान

10570. श्री एम.एम. पल्लव राजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिदेशों में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में हमारे वित्तीय संस्थान कितने सफल रहे हैं;

(ख) बिदेशों में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली सभी वित्तीय संस्थानों/बैंकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन देशों में उक्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;

(ग) क्या बिदेशी बैंकों को देश में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दिए जाने के बारे में नियमों में कोई छूट देने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उच मंत्री (श्री जमिन् लालजी) : (क) और (ख) इस समय बाहर के

25 देशों में 9 भारतीय बैंक कार्य कर रहे हैं, इन देशों में ये बैंक विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात व्यवसाय का वित्त पोषण, अप्रत्यक्षी साख्त-पत्र आदि सहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन बैंकों ने भारत सम्बद्ध व्यापार वित्त पोषण, अनिवासी निवेशों के प्रवाह का संवर्धन, तदनुकूपी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने एवं भारतीय कम्पनियों के लिए संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मेरिल लिच के सहयोग से 1988 में अनिवार्सी भारतीयों से निधियां जुटान के लिए भारतीय विकास निधि नाम की एक समुद्र पारीय निधि आरम्भ की। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, उपलब्ध होने पर, विदेशों में परामर्शी सेवाओं का कार्य भी हाथ में लेता है। भारतीय बैंकों के नाम और जहां ये कार्य कर रहे हैं, उन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों को उनकी वित्तीय सेवाओं के प्रदान करने में किसी तरह की रियायत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

बैंक का नाम	देशों के नाम जहां समुद्र-पारीय शाखाएं कार्यरत हैं
1. भारतीय स्टेट बैंक	यू०के०, यू०ए०ए०, बांगला देश, बाहमास, बहरीन, गैल्जियम, फ्रांस, जापान, हांग-कांग, पनामा, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव समूह द्वीप समूह, पूर्वी जर्मनी, कैमे आइलैण्ड्स,
2. बैंक आफ इण्डिया	यू० के०, यू० एस० ए०, जापान हांग-कांग; सिंगापुर, ओमान आइलैण्ड्स, फ्रांस केनया, चैनल आइलैण्ड्स,
3. बैंक आफ बड़ौदा	यू० के०, यू० एस० ए०, बाहमा, गैहरीन, गैल्जियम, फिजी आइलैण्ड्स, गोयाना, केनया, मोरिशस दुबई, सिधली, ओमान
4. इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्रीलंका, सिंगापुर, हांग-कांग, साउथ कोरिया
5. इण्डियन बैंक	श्रीलंका, सिंगापुर
6. यूको बैंक	यू०के०, सिंगापुर, हांग-कांग
7. केनरा बैंक	यू०के०,
8. सिडिकोट बैंक	यू०के०,
9. भारत ओवरसीज बैंक	बाइलैण्ड

आर्थिक केन्द्रीकरण और जनसंख्या विभाजन के बारे में अध्ययन

10571 श्री ए० के० राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच आर्थिक केन्द्रीकरण और जनसंख्या विभाजन के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में बेतन न पाने वाले, जो आय कर की सीमा में हैं, आयकर का दायरे से बच जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जनसंख्या के व्यय-वितरण का अध्ययन करने के लिए घरेलू खपत व्यय का सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के नवीनतम दौर अर्थात् 43वां दौर (1987-88) से प्राप्त अनन्तिम परिणामों के आधार पर दो आर्थिक समूहों नामतः "निर्धन" तथा "गैर-निर्धन" के बीच जनसंख्या का बंटवारा निम्नानुसार किया गया है :—

	व्यक्तियों की संख्या (मिलियन में)	कुल व्यक्तियों का प्रतिशत अनुपात
निर्धन	232	29.2
गैर-निर्धन	563	70.8

(ग) और (घ) ऐसे व्यक्तियों की सही सही संख्या का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है, जिनके पास करयोग्य आय तो है लेकिन वे आयकर के जाल से बाहर हैं। फिर भी, आयकर विभाग सभी श्रेणियों के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहा है, जिनके पास कर योग्य आय तो है लेकिन अभी तक उन पर कर नहीं लगाया गया है। ऐसे सभी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए निरीक्षण स्कंध आयकर अधिनियम की धारा 133 अ के अध्याधीन व्यापारिक तथा वाणिज्यिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सूचना शाखाएं भी ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र करती हैं तथा उसकी जाँच-पड़ताल करती हैं।

विदेशों के साथ सम्बन्ध

[हिन्दी]

10572. श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

जनवरी, 1989 से 31 मार्च 1990 के दौरान भारत में किन-किन देशों के साथ व्यापार समझौते किए और इन समझौतों के अंतर्गत आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण]

देशों के नाम	कराजिन पर हस्ताक्षर किए गए	इन करारों के तहत आयात तथा निर्यात होने वाले माल के ब्योरे
1. भूटान	भारत तथा भूटान के बीच दिनांक 2.3.1990 को व्यापार एवं वाणिज्य करार पर हस्ताक्षर हुए।	इन व्यापार करारों में आयात एवं निर्यात के लिए माल का कोई उल्लेख नहीं था।
2. बांग्लादेश	भारत तथा बांग्लादेश के बीच हुए व्यापार करार की वैधता अवधि दिनांक 3.10.1989 से तीन वर्षों के लिए बढ़ाई गई।	
3. बेल्गे-लक्जेंबर्ग इकानामिक यूनियन	दिनांक 26.3.1990 को आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी निगम पर करार।	इस करार में आयात तथा निर्यात होने वाले माल के ब्योरों का उल्लेख नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में खनिजों का खनन

10573. श्री रेशम लाल झांगड़े } : क्या इरफात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल }

(क) वर्ष 1984 से दिसम्बर, 1989 के दौरान, वर्षवार मध्य प्रदेश की खानों से कितनी मात्रा में कोयले, लोहे, कोरडम टिन, डोल्सोमाइट, तांबे, हारे और चूना-पत्थर का खनन किया गया तथा उस समय उनका बाजार माव क्या था; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को इन खनिजों के लिए राश्ट्री की कितनी घनराशि का भुगतान किया गया गया ?

इस्पात और लान मंत्री तथा बिबि और म्बाय मंत्री श्री विमल मोस्मान, : (क) केन्द्र सरकार द्वारा सामान्यतः सीधे कोई खनन कार्य नहीं किया जाता।

केन्द्र सरकार ने 1984 से दिसम्बर, 1989 के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसा कोई खनन कार्य नहीं किया।

(ख) राज्य सरकार को पट्टाधारी द्वारा ही रायस्ती देय होती है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के आलोक में, केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन को रायस्ती अबायमी का प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्तर से जापान को लौह अयस्क का निर्यात

[अनुवाद]

10574. श्री रेशम लाल जांगड़ : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की इजाजत करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने बस्तर से जापान को अयस्क के निर्यात से कितना राजस्व अर्जित किया; और

(ख) बस्तर से लौह अयस्क के निर्यात की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

बाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीधरण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम०एम०टी०मी० द्वारा बस्तर क्षेत्र से जापान को निर्यात किए गए डेलाडी ग्रे लौह अयस्क का विली मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य (रुपए/करोड़)
1987-88	119.69
1988-89	163.42
1989-90 (अन्तिम)	203.83

(ख) बस्तर से डेलाडी ग्रे लौह अयस्क के डरों की निर्यात बचनबद्धता वर्ष 1990-91 के लिए कम कर दी गयी है। इन किस्म के अयस्क की घरेलू मांग के कारण ऐसा किया गया है।

मध्य प्रदेश में सोने का भण्डार

[हिन्दी]

10575. श्री रेशम लाल जांगड़ : क्या इस्पात और लान मंत्री यह बताने की इजाजत करेंगे कि :

क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर और रायगढ़ जिलों के कुछ गांवों में बड़ी संख्या में लोग बालू को छान कर सोना निकाल रहे हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी क्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मू-सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में सोने का पता लगाने का कभी कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में और उसका क्या परिणाम निकला ?

इ-पात और स्नान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री बिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार, रायगढ़ जिले के वजोर, तपकरा, फर-जबाहर, मन्देरबहर, पन्डरीपानी, खुटगांव, कन्हाई भर, सेमर, कच्छार, गरियाबन्द, सबदमुण्डा, सोनात्रपुरी नाला भद्रखुण्डा नाला, गरीघाट नाला, आदि स्थानों तथा रायपुर जिले के बाघमारा, देबगांव, सोना झरिया नाला के डुमरपाला, श्रीनी क्षेत्र, बजातपुर और खरनकोई तथा कुम्हारी आदि की बालू को छानने से अति अल्प मात्रा में बजरी स्वर्ण मिलने की सूचना है।

(ग) और घ) भारतीय मू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रायगढ़ जिले के धरमजय-गढ़ और जसपुर तहसीलों में तफरा-पन्डार-पानी लुडे क्षेत्रों में स्वर्ण खनिजीकरण के बारे में सन् 1981 से प्रारम्भिक मूल्यांकन कर रहा है। अब तक के कार्य से, प्राथमिक जलों के बेड राक में 0.1 से 8.2 पी.पी.एम. रेशाडुअल मिट्टी में 0.1 से 0.7 पी०पी०एम०, तथा ग्रेवाल जोनो/एलूवियन प्लेसर्स में 0.1 ग्राम से 0.8 ग्राम/टन मात्रा में स्वर्ण के संकेत मिले हैं।

गंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा कन्नड़ फीचर फिल्में दिखाया जाना

[अनुवाद]

10576. श्री एच०सी० श्रीकांतय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रत्येक शनिवार को कन्नड़ फीचर फिल्म दिखाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रत्येक रविवार को कन्नड़ फीचर फिल्म दिखाए जान के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक शनिवार को क्षेत्रीय कन्नड़ भाषा के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(स) जी, नहीं।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, गंगलीर से गंगलीर को क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रसारण पहले ही सप्ताह के अन्य दिनों से आधा घंटा पूर्व शुरू हो जाता है।

गंगलीर दूरदर्शन द्वारा कन्नड़ दूरदर्शन धारावाहिक का प्रसारण

10577. श्री एच० सी० श्रीकांतम्बा : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और के दौरान गंगलीर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कन्नड़ दूरदर्शन धारावाहिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन धारावाहिकों के निर्देशकों के नाम क्या क्या हैं और उन्हें गंगलीर दूरदर्शन से कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या गंगलीर दूरदर्शन कुछ ही निर्देशकों द्वारा निर्मित धारावाहिकों में से चयन करता है; और

(घ) कन्नड़ दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. जयप्रकाश) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, गंगलीर से वर्ष 1988-89 में सात तथा 1989-90 में 22 कन्नड़ धारावाहिक वित्ताए गए। इन धारावाहिकों के निर्देशकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये सभी प्रायोजित टी० वी० धारावाहिक उनके लिए दूरदर्शन द्वारा उनके निर्देशकों को कोई राशि देने की जरूरत नहीं थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी दूरदर्शन धारावाहिकों जिनमें कन्नड़ धारावाहिक भी शामिल हैं, का चयन पटकथा के गणों निर्देशक और निर्माता वल के अन्य सदस्यों की साख तथा कार्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1988-89 में प्रसारित धारावाहिक

धारावाहिक का नाम	निर्देशक का नाम
1. कण्ठकटर करियप्पा	महादेवन
2. बंध माणयन हरि	विश्व प्रसाद

1 2

3

3. जन जीवन	जी०आर० श्रीनिवास
4. कृष्णा नी बेजने बारो	एच०एम०के० मूर्ति
5. सप्तस्वर	गोविन्द
6. बिसिलु कुदुरे ।	श्याम सुन्दर
7. नम्बर 55	बी०एन० चन्द्रकांत

वर्ष 1989-90 में प्रसारित धारावाहिक

1. सर्वदागुल	ए०एन० प्रसना
2. आसफगलि नूराक ।	राजवर्धन
3. बिसिलु कुदुरे-2	श्याम सुन्दर
4. हिम श्वेता	पद्मिनी रामचन्द्रा
5. कावेरी	विश्व प्रसाद
6. परिवर्तन	रवि किरण और महादेव
7. असेगुल नूराक-2	राजवर्धन
8. प्रेमावेन्दरे इदे इदे	रवि किरण
9. चन्द्र चकोरी	श्रीधर
10. दीड़ड़ा मन	राघवेन्द्र
11. मेक्कनिक मुहडा	रमेश भट्ट
12. अलंगुल	कट्टा रामचन्द्र
13. मि० टेनेट	सिही कहि चन्द्रशु
14. नम्मा नम्माली	अर्जुन देव और टी.एन. नरसिम्हन
15. प्रेमदा करंजी	विश्व प्रसाद
16. कौजी कोलनल	लिमराज
17. नागालेसू	कट्टारामचन्द्र
18. नीम्पू नागू	ए०एस० मूर्ति
19. बडुकु न्नाडा चिलरा	एच०टी० नगेन्द्रप्पा
20. स्फोट	आर. नागेश
21. कम्मा मुचे काइ कोडे	आर०एस० कौशिक
22. प्रीति प्रेम	अर्जुन देव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का समाचार (आडिटोरियम)

10578. श्री प्रसादराव श्री० जोसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा किन-किन स्थानों पर आडिटोरियम बनाए गए हैं,

(ख) क्या इन समाचारों को प्राइवेट पार्टियों के लिए भी बुकिंग की जाती है।

(ग) यदि हां, तो इन समाचारों की बुकिंग और शुल्क का स्थान-वार ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार वर्ष 1990 और 1991 के दौरान ऐसे कुछ और समाचारों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा मंसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपने निम्नलिखित समाचार हैं।

(1) सिरि फोर्ट समाचार, नई दिल्ली

(2) फिल्म प्रभाग समाचार, महादेव रोड, नई नई दिल्ली

(3) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम समाचार, बम्बई

(4) आकाशवाणी समाचार, बम्बई

(5) आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली

(6) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान समाचार, पुणे

(ख) उपरिलिखित (1) से (3) तक के समाचारों की प्राइवेट पार्टियों के लिए बुकिंग की जाती है।

(ग) प्राइवेट बुकिंग पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर की जाती है। बुकिंग प्रचार का विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी हां। आकाशवाणी का पुणे में एक छोटा समाचार तथा मद्रास में एक रिकार्डिंग सह-समाचार का निर्माण करने का कार्यक्रम है।

विवरण

1. सिरि फोर्ट आडिटोरियम, नई दिल्ली

(क) नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम :

प्रातःकालीन एक शो (प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक)
7,500/- रुपये

सांयकालीन एक शो (सांय 4.00 बजे से राशि 10.00 बजे तक)
10,000/- रुपये

अतिरिक्त शो (उसी दिन)- 4,500/- रुपये (अधिकतम 3 घंटे)

पूषाम्यास :—

- | | |
|--|----------------|
| (1) प्रातः कालीन सत्र (वातानुकूलन सहित) | -7,500/- रुपये |
| (2) प्रातः कालीन सत्र (बिना वातानुकूलन के) | -3,000/- रुपये |
| (3) सांयकालीन सत्र (वातानुकूलन सहित) | -7,500/- रुपये |
| (4) सांयकालीन सत्र (बिना वातानुकूलन के) | -5,000/- रुपये |

(ख) सिनेमा शो

(1) केवल एक शो के लिए -10,000/- रुपये

(2) एक शो से अधिक के लिए :—

पहला शो 10,000/- रुपये

दूसरा शो 10,000/- रुपये

तीसरा शो 8,000/- रुपये

बाद के शो (प्रत्येक शो) 6,000/- रुपये

(ग) सम्मेलन :

अधिकतम आठ घंटे 12,000/- रुपये

आठ घंटे से अधिक होने पर प्रत्येक

1 घंटे के लिए 2,000/- रुपये का

अतिरिक्त शुल्क

टिप्पणी :—समागार किराये पर लेने वाली पार्टी आवश्यकतानुसार निम्नलिखित अतिरिक्त स्थान भी प्रत्येक के सामने दशाये गये शुल्क पर ले सकती है :—

1. सिरी फोटो सांस्कृतिक केन्द्र काम्पलेक्स में कार्यालय कमरे
211/-रु. प्रति कमरा प्रतिदिन/प्रति शो
2. दो ग्रीन रूम तथा बैंक स्टेज :
498/- रु० प्रतिदिन/प्रति शो
11. फिल्म प्रभाग सभागार, नई दिल्ली

- | | |
|--|------------|
| (1) सप्ताह के दिनों में कार्यालय समय में शो पहले एक घंटे या उसके एक भाग के लिए | -260/- रु० |
| (2) प्रत्येक अतिरिक्त आधे घंटे या उसके भाग के लिए | |
| (3) रविवार, छुट्टी के दिन तथा सप्ताह के दिनों में कार्यालय समय के बाद शो | -330/- रु० |
| (4) प्रत्येक अतिरिक्त आधे घंटे या उसके भाग के लिए | 165/- रु० |
- 11 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बम्बई
प्रत्येक शो शुल्क 800/- रु०

नववर्ष की पूर्व, संख्या पर आयोजित कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए
ओताओं/बर्सकों को आमंत्रित करना

10579. श्री प्रताप राव श्री० मोसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नववर्ष की पूर्व संख्या पर कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के सम्बन्धियों/परिवर्तियों को दर्शक के रूप में आमंत्रित करने के बजाय आम जनता को आमंत्रित करने के मानदण्ड को व्यापक बनाने का है;

(ख) यदि हाँ; तो इस मानदण्ड को कब तक व्यापक बनाया जायेगा, और

(ग) इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा ससदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) नववर्ष की पूर्व संख्या पर तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जाता है। दर्शकों को उनसे प्राप्त अनुरोधों और ऐसे कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किए जाने वाले दर्शकों के पैनल के आधार पर आमंत्रित किया जाता है जिसे ओता अनुसंधान एकक तैयार करता है।

बंजोदेवी मन्दिर पर पर्यटन सुविधाएं

10580. श्री प्रतापराव श्री० मोसले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंजोदेवी मन्दिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है,

(ख) क्या पर्यटन विभाग ने वहाँ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये है;

(ग) यदि हाँ, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष और आगामी दो वर्षों में दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल-मलिक) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे प्रस्तावों पर उनके गुणावगुणों, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। वैद्यों देवी की यात्रा करा जाने पर्यटकों को सुविधाएँ मुहैया कराने के बारे में जम्मू-कश्मीर सरकार से ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सल्टेंट्स लिमिटेड

10581. श्री एस० सी० वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सल्टेंट्स लिमिटेड की वित्तीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है; और

(ख) क्या एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सल्टेंट्स लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति ब्यूरो आफ पब्लिक एटरप्राइजेस बोर्ड द्वारा की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस कन्सल्टेंट्स लि० की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति (1) परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन करने, निगरानी और अन्य अध्ययनों से प्राप्त परामर्श शुल्क तथा (2) सदस्य बैंकों और सरकारी क्षेत्र के निगमों में निवेश निधि से अर्जित व्याज से की जाती है।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में सूरी ब्रदर्स के कार्यालय परिसरों में छापे

10582. श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशक और आयकर विभाग ने इस महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान दिल्ली में सूरी ब्रदर्स के कार्यालय और आवास परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हाँ, तो छापों के दौरान जप्त किये गये अभिलेखी दस्तावेजों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जमिल शास्त्री) : (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 2 मई, 1990 को तलाशियां ली गई थीं। आयकर, विभाग के अधिकारियों को भी उनमें शामिल किया गया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सीमा शुल्क और आयकर की दृष्टि से कतिपय अपराध-आरोपणीय वस्तुओं को अभिग्रहीत किए गए हैं।

(ग) राजस्व-एजेंट्सियों द्वारा जांच-पड़ताल पूरी किए जाने पर संगत कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब की ओवरड्राफ्ट सुविधा

10583. श्री कमल चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से पंजाब सरकार को ओवरड्राफ्ट वापस करने के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या पंजाब सरकार ओवरड्राफ्ट को समय पर वापस कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जमिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों द्वारा कर अपव्ययन

10584. श्री कमल चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में स्टील के बर्तन बनाने वाली विभिन्न फैक्ट्रियां, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं हैं, विथी व खरीद का कोई लेखा-जोखा नहीं रख रही हैं और इस प्रकार करों का अपव्ययन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो फैक्ट्रियों द्वारा कर अपव्ययन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार की फैक्ट्रियों द्वारा किए गए कर अपव्ययन के कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जमिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्तनों पर केन्द्राव्य उत्पाद टेरिफ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत शुल्क से छूट प्राप्त है।

जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 44 ए ए में विनिर्दिष्ट है, बर्तन बनाने वालों को, जिनकी आय 25,000/- रु. से अधिक हो अथवा जिनका कुल व्यवसाय 2,50,000/- रु० से अधिक हो अथवा जिनका कुल व्यवसाय 2,50,000/- रु० हो, लेखा-जोखा रखना अपेक्षित होता है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान आयकर-अपवंचन का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा मशीनों का आयात

10585. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने हाल ही में कई मशीनों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो आयात की गई मशीनों का ब्योरा क्या है और इन मशीनों का आयात किस प्रयोजन के लिए किया गया है;

(ग) उन विदेशी कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिनसे इन मशीनों का आयात किया गया है;

(घ) क्या इन मशीनों में कोई खराबी पायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने दोषयुक्त मशीनों के आयात के लिए क्या जिम्मेदारी की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र जा रही है।

प्रकाश-सुपाही (फोटोसेन्सिटिव) पदार्थों के आयात और वितरण हेतु लाइसेंस

10586. श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने सरकार से प्रकाश सुपाही (फोटोसेन्सिटिव) पदार्थों के आयात और वितरण हेतु लाइसेंस देने की प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार का प्रकाश-सुपाही (फोटोसेन्सिटिव) पदार्थों के आयात और वितरण पर लाइसेन्स की प्रथा समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वदेश में ही उपलब्ध होने के कारण कुछ विशेष प्रकार की एक्सरे फिल्मों जैसे (1) लो-डोज मॅमोग्राफिक फिल्मस (2) मोस मिनिमेचर फिल्मस (3) चॅम्बर्स के लिये प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रकार की एक्सरे फिल्म (4) कैंट-स्कॅनर्स के लिए एक्सरे फिल्मस को नई आयात-निर्यात नीति 1990-93 में इन्हें खुले आम साइसेंस से हटाकर सीमित अनुमेष सूची में शामिल किया गया है। ऐसा उपमहानिदेशक स्वास्थ्य सेवा की अध्यक्षता में गठित कुशल रेडियोलोजिस्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अन्य प्रकार-के प्रकाश मुद्राहीकृत माल के आयात की अनुमति खुले आम साइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है।

विचारप्रस्त अग्रत्यक्ष कर

10587. श्री जर्नेस प्रसाद वर्मा : क्या बिस्ल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रत्यक्ष करों और विशेष रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बहुत बड़ी घनराशि विवाद में फंसी है। और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का अग्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने के लिए निपटान आयोग के पेटर्न पर एक मंच की स्थापना करने की विचार है ?

बिस्ल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जमिल शास्त्री) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था पर विचाराधीन है।

सातवीं योजना के दौरान पंजाब में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

10588. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में कितने और कहाँ-कहाँ आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये हैं,

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान पंजाब में नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी स्थापना के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० ज्येष्ठ) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब राज्य में कोई नया आकाशवाणी केन्द्र चालू नहीं किया गया है। तथापि, आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में मटिडा तथा पटियाला में नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें हैं। इन केन्द्रों क वर्ष 1990 के दौरान चालू किये जाने का कार्य क्रम है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय आबंटन को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् ही पंजाब राज्य में आकाशवाणी सेवा के और विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

विदेशी कारों का आयात

10589. श्री ई० एन० एम० पाकीर मोहम्मद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कारों के आयात से संबंधित नियमों को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में गैकों की शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

10590. श्री रेशमलाल जांगड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में किन-किन स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 की अवधि के दौरान अपनी शाखाएं खोली हैं, और इनमें से अनुसूचित जाति बहुल स्थान कितने हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 की अवधि में, मध्य प्रदेश में स्थित बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर जिलों में जिन केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोली थीं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले केन्द्रों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती।

विवरण

जिला/केन्द्र का नाम	बैंक का नाम
1. बिलासपुर	
1. कोडरी.	इलाहाबाद बैंक
2. बिलासपुर	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स

1	2	3
3.	कोरबा	पंजाब एंड सिंध बैंक
4.	सेवार	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
5.	सिरगिट्टी	स्टेट बैंक आफ इंदौर
6.	बुदगाहन	पंजाब नेशनल बैंक
7.	भोतिया	स्टेट बैंक आफ इंदौर
8.	कोठारी	भारतीय स्टेट बैंक
9.	सोहागपुर	स्टेट बैंक आफ इंदौर
10.	गेबरा	भारतीय स्टेट बैंक
11.	लेंगनमाडा	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
12.	छापोरा (कोटा)	पंजाब नेशनल बैंक
13.	सेमारसल	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
14.	रामेपुर	पंजाब नेशनल बैंक
15.	खपरीकला	पंजाब नेशनल बैंक
16.	अचनकमर	पंजाब नेशनल बैंक
17.	बांदली	भारतीय स्टेट बैंक
18.	सिंगाड़ा	इलाहाबाद बैंक
19.	गौड़	पंजाब नेशनल बैंक
20.	कटाउड़	भारतीय स्टेट बैंक
21.	उतारबा	यूनियन बैंक आफ इंडिया
22.	पोंडी	यूनियन बैंक आफ इंडिया
23.	कोसाला	इलाहाबाद बैंक
24.	कोनार	बैंक आफ महाराष्ट्र
25.	साधा	पंजाब नेशनल बैंक
26.	छिल्पी बंगला	भारतीय स्टेट बैंक
27.	मोहगांव	भारतीय स्टेट बैंक
28.	बैचलपुर	भारतीय स्टेट बैंक
29.	बामाबुर	यूनियन बैंक आफ इंडिया
30.	सिलदाहा	इलाहाबाद बैंक
31.	अमोरा	स्टेट बैंक आफ इंदौर
32.	मोरना	भारतीय स्टेट बैंक

1 2

3

33. सकृती
34. बेलपान
35. छटोना
36. मोच बिलासपुर

- स्टेट बैंक आफ इंदौर
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
स्टेट बैंक आफ इंदौर
स्टेट बैंक आफ इंदौर

II. रायगढ़

37. बिमदा
38. साराबकोम्बो
39. लारीपानी
40. खुलरापाड़ा
41. कोंडालारी
42. संकारा
43. गाजियादीह रायगढ़

- रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
रायगढ़ ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक

III. रायपुर

44. रायपुर
45. रायपुर
46. रायपुर
47. नारा
48. गंजार
49. सोनादीह
50. चाहनत
51. लाम्बार
52. कोलियादेबरी
53. बिछिया
54. पंडरावन
55. धनसिर
56. सामोदा
57. गोदी
58. बाना
59. चन्वलूरी
60. पालौड़
61. झाकरापाड़ा
62. धवलपुर
63. पथरसा
64. कोहाकुड़ा

- बैंक आफ महाराष्ट्र
इंडियन ओवरसीज बैंक
स्टेट बैंक आफ सीराष्ट्र
देना बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
देना बैंक
देना बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
देना बैंक
देना बैंक
देना बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक आफ इंदौर
यूनियन बैंक आफ इंडिया
देना बैंक
देना बैंक
भारतीय स्टेट बैंक

1	2	3
65.	बोरसी	इलाहाबाद बैंक
66.	मेघा	देना बैंक
67.	शोभा	पंजाब नेशनल बैंक
68.	उरमल	यूनियन बैंक आफ इंडिया
69.	नरटोरा	पंजाब नेशनल बैंक
70.	शेर	भारतीय स्टेट बैंक
71.	सोरिडखुर्द	भारतीय स्टेट बैंक
72.	बमहानी	भारतीय स्टेट बैंक
73.	गीतापुरी	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
74.	देवसुन्दरा	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
75.	रोहंसी	भारतीय स्टेट बैंक
76.	गुमा	यूनियन बैंक आफ इंडिया
77.	उरला	स्टेट बैंक आफ इंदौर
78.	बालोदा	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
79.	खेड़वा	इंडियन बैंक
80.	सुहेला	इलाहाबाद बैंक
81.	गट्टासीली	देना बैंक
82.	मेचका	पंजाब नेशनल बैंक
83.	केरागांव	पंजाब नेशनल बैंक
84.	खोना रायपुर	देना बैंक

एम० आई० टी० सी० ओ० के कर्मचारियों के वेतनमान

[अनुवाद]

10591. श्री ए० के० राय : बाबुजय्य जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम०आई०टी०सी०ओ० कारखानों के ऐसे कर्मचारियों की अंजीवार संख्या कितनी है जिनको एम०एम०टी०सी० से केन्द्र सरकार के वेतनमान मिल रहे हैं;

(ख) एम०आई०टी०सी०ओ० कारखानों के ऐसे कर्मचारियों की अंजीवार संख्या कितनी है जिनको एम०आई०टी०सी०ओ० के वेतन बोर्ड के वेतनमान मिल रहे हैं;

(ग) इन दो वेतनमानों के अनुसार कुल वेतन में कितना अंतर है;

(घ) क्या एम०आई०टी०सी०ओ० का एम०एम०टी०सी० में विलय कर दिया गया है और यह इसमें प्रमाण के रूप में कार्य करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को भी एम०एम०टी०सी० में खपाया जायेगा और उन्हें उसके वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलेगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) एम. एम. टी. सी. का वेतनमान पाने वाले मिटको के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

अधिकारी	—	134
कर्मचारी	—	341

यह कार्यालय या कारखानों में उनकी नियुक्ति से असम्बद्ध है।

(ख) मिटको के कामगारों को मजदूरी समझौते के अनुसार मजदूरी मिलती है। मजदूरी समझौते के अन्तर्गत आने वाले मजदूरों की कुल संख्या 916 है।

(ग) मिटको और एम०एम०टी०सी० के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान बराबर होने के कारण उन दोनों संगठनों में वेतन के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक मजदूरी का सम्बन्ध है, एम० एम० टी० सी० में नियोजन एवं वेतनमानों का कोई समान ग्रंथ नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मिटको को एम० एम० टी० सी० के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। मिटको को एम० एम० टी० सी० के साथ मिलाने के प्रस्ताव में शामिल बहुत सारी बातें, जिनमें उनके वेतनमान तथा कैंडर शामिल हैं, की जांच एम० एम० टी० सी० द्वारा की जा रही है।

सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष के सामर्थ्य

10592. श्री रीतलाल प्रसाद बर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष के कुल कितने सामर्थ्य हैं,

(ख) सिनेमा कर्मकारों को क्या-क्या कल्याण और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) ऐसे क्या उपाय करने का विचार है जिनसे अधिकतम संख्या में सिनेमा कर्मकारों का कल्याण हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उषेन्द्र) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) (i) कल्याण कमिश्नरों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि अन्य कल्याण निधियों के अंतर्गत मौजूदा बिक्रिसा प्रतिष्ठानों के माध्यम से सिने कर्मचारों और उनके परिवारों को बिक्रिसा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(II) अन्य कल्याण निधियों के अंतर्गत खलाई जा रही छात्रवृत्ति स्कीम सिने-कर्मकार कल्याण निधि पर भी लागू की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बी गई छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	राशि
1987-88	1,17,700 रुपये
1988-89	1,41,550 रुपये
1989-90	3,55,000 रुपये
बजट प्राप्कसन	

(ग) निधि के सीमित साधनों (वार्षिक आय 7 से 8 लाख रुपये) को ध्यान में रखते हुये, फिलहाल सिने कर्मचारों के लिये नई कल्याण स्कीम शुरू करना सम्व प्रतीत नहीं होता। तथापि, अधिक से अधिक लाभार्थियों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम का काम देने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। कल्याण सुविधाएं साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रदान की जाती हैं।

सिनेमा कलाकार कल्याण कोष में धनराशि का अंतरण

10593. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बलचित्र धमिक कल्याण कोष के नाम लाभ के अन्तरण के बारे में दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के तारकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर में यह बतान का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा कलाकार कल्याण कोष में अन्तरित की जान वाली समूची धन राशि को उक्त कोष में अन्तरित किया जा चुका है, और

(ख) यदि नहीं तो उक्त धन राशि को शीघ्र अन्तरित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उषेन्द्र) : (क)जी, नहीं।

(ख) सर रिचर्ड एटनबरो के, जो "गांधी" फिल्म के सहनिर्माण और वित्तपोषण करार के एक पक्षकार हैं वकील के साथ अप्रैल, 1990 में हुई एक बैठक में "गांधी" फिल्म के सहनिर्माण और वित्तपोषण करार के प्रावधानों के अनुसार सिने आर्टिस्ट्स वेल्फेयर फंड के नाम से एक अलग ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसा ट्रस्ट, राष्ट्रीय फिल्म

विकास निगम द्वारा बनाया जाये। निगम ने मिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के नाम से 10,001 रु० के वार्षिक अंशदान से एक ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के विलेख का अंतिम प्रारूप तैयार किया जा रहा है। "गांधी" फिल्म के निवल साम को 5 प्रतिशत राशि सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड में अन्तर्गत करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श हेतु एक भारतीय सिनेमटोग्राफिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्षों का प्रस्ताव अलग से विचाराधीन है।

रुग्ण एककों द्वारा सहायता का उपयोग

10594. श्री राम नाईक : क्या बिस्म मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बोर्ड फोर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्सट्रक्शन" और/अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक रुग्ण एककों को दी गई अन्तरिम धनराशि के खर्च पर नियन्त्रण रखते हैं;

(ख) कर्मचारियों द्वारा रुग्ण एकक संचालन हेतु बनाई गई को-ऑपरेटिव सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में मालिकों के रिश्तेदार और/अथवा विश्वसनीय मित्रों का न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त प्राधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक देय राशि का जो श्रम कानून के अन्तर्गत सुरक्षित नहीं है, नियत तारीखों को भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा रुग्ण एककों के छोटे जमाकर्ताओं और डिबेंचर धारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

बिस्म मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में किये गये प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास रुग्ण/कमजोर एककों को धनराशि देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे संवितरण अन्यो के साथ-साथ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे संवितरित की गई रकम के उपयोग पर नजर रखें।

औद्योगिक तथा वित्तीय; पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि अभी तक उसने केवल एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी अर्थात् कमानी ट्यूब्स लिमिटेड को कर्मचारियों की भागीदारी के साथ पुनरुज्जीवित करने की योजना को मंजूर किया है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है (I) कंपनी के (लगभग 91.6 प्रतिशत) और अन्यो के 95 लाख रुपये के अंकित मूल्य के शेयरों का कर्मचारी सहकारी समितियों में अन्तरण (II) कंपनी के प्रबन्धन को पुनर्गठित निदेशक मण्डल को सौंपना जिससे व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त/अनुभवी व्यक्ति होंगे और उनमें से दो प्रतिनिधि कर्मचारी सहकारी समिति के हों, (III) छंटनी मुआवजे का भुगतान (IV) अन्य के साथ-साथ जमाकर्ताओं आदि को किये जाने वाले भुगतान की व्यवस्था। इस योजना के कार्यान्वयन पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा नजर रखी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उपचारी कार्रवाई आरम्भ की जा सके।

ईरान द्वारा भारतीय कम्पनियों का रोकना क्या था

10595. श्री इरा अम्बारासु : क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने कुछ भारतीय कम्पनियों का 59 करोड़ रुपये रोक लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर ईरान के साथ बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

बिस्व मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, ईरान को किए गए परियोजना निर्यातों तथा वस्तु निर्यातों के सम्बन्ध में 31.3 89 को बकाया राशि 46.98 करोड़ रुपये के बराबर थी ।

(ख) और (ग) विभिन्न भारतीय कम्पनियों को देय भुगतानों का मामला, भारत सरकार ने अगस्त, 1989 में ईरान सरकार के साथ उठाया था । इस बात पर सहमति हुई थी कि ईरान सरकार भारतीय कम्पनियों के दावों की जाँच करेगी और वैध बकाया दावों के सम्बन्ध में ईरानी फर्मों/सरकारी अधिकरणों व अन्य कानूनी अस्तित्व वाली संस्थाओं के भुगतान दिखवाने में उनकी सहायता करेगी ।

गरीबों को बैंक ऋण

10596. श्री इरा अम्बारासु : क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को गरीबों को अधिक ऋण देने के कोई निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

बिस्व मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे अपने कुल अधिमों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले हिस्से को बढ़ाकर क्रमशः 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दें । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बैंक सरकार द्वारा चलाए जा रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बिभेदी ब्याज दर योजना और शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के विशेष कार्यक्रमों में सक्रीय भाग ले रहे हैं । बिभेदी ब्याज दर योजना गरीबों में अधिक गरीब की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उनके छोटे उत्पादक उद्यमों के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पता लगाए गए निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता और संस्थागत वित्तपोषण प्रदान करके उनकी उत्पादक परिसम्पत्तियाँ प्राप्त करने के योग्य बनाकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता प्रदान करना है । शहरी गरीबों

की स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी शहर/नगर आते हैं जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है। जिन व्यक्तियों की कुल पारिवारिक आय 600/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, वे सभी इस कार्यक्रम के तहत सहायता पाने के हकदार हैं।

सिक्कों की काला बाजारी

10597. श्री इरा अम्बारासु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिक्कों की काला बाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सिक्कों के उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, देश में सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। सिक्कों की काला बाजारी करने के लिये किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई गिरफ्तारी कि! जात की रिपोर्ट नहीं मिली है।

तमिलनाडु में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

10598. श्री इरा अम्बारासु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि तीन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड ने गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु स्थित परियोजनाओं को निम्नलिखित राशियां मंजूर और संवितरित की :

(करोड़ रुपये)
(अप्रैल-मार्च)

	1987-88	1988-89
मंजूरियां	667.34	1029.96
संवितरण	421.13	647.85

बोकारो इस्पात संयंत्र

10599. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और लौह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र से पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात तथा अन्य सामग्री की चोरी की कितनी घटनाएँ हुई तथा इसके कारण हुई हानि का वर्षवार व्यौरा क्या है,

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान संयंत्र की सुरक्षा पर कितनी खनराशि व्यय की गई,

(ग) क्या उपर्युक्त दोनों चीजों में वृद्धि हो रही है,

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इनकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गए हैं।

इस्पात और लौह मंत्री तथा बिबि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	सूचित किये गये कुल मानकों की सं० ×	हानि
1985	36	1,00,115
1986	32	70,260
1987	30	2,68,800
1988	35	73,550
1989	45	57,257

× इसमें निजी खानों के मामले भी शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान संयंत्र की सुरक्षा पर 2406.29 लाख रुपए राशि खर्च किए गए।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ऐसा कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है।

अन्नक व्यापार निगम में भ्रष्टाचार

10600. श्री ए० के० राय : क्या खाजिग्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्नक व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों सरकार के ध्यात में आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

बाजिबब मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को कुछ शिकायतें मिली थीं। अन्नक व्यापार निगम से तथ्यों के सत्यापन के बाद पाया गया कि आरोप प्रत्यक्षतः सत्य नहीं थे।

सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों पर होने वाला व्यय

10601. श्री सुधीर गिरि : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के दोनों सदनों पर सत्र के दौरान प्रति घंटा कितनी घन-राशि व्यय होती है; और

(ख) सत्रावसान की अवधि के दौरान प्रति घंटा कितनी घन-राशि व्यय होती है ?

बिस्स मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) संसद के दोनों सदनों के सत्र के दौरान और सत्रावसान की अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा किए गए खर्च के संकलन के लिए इस समय कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। संसद के एक दिन के बैठने पर सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च में केवल संसद के दोनों सचिवालयों का खर्च ही सम्मिलित नहीं होता अपितु विभिन्न संसद सम्बन्धी कार्यों में अपेक्षित भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों का खर्च, भी सम्मिलित होता है। इन मूलमूल कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अत्यपूर्ण ढंग से अपेक्षित सूचना का संकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

10602. श्री बसंत साठे : क्या बिधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत रहे, और

(ख) बकाया पड़े अनिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने तथा निर्णय शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और स्लान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विमलेश गोस्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई उच्च न्यायालय में संबित मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	मामलों की संख्या
1987	139548
1988	142891
1989	156454

12. (क) मुम्बई उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने का मामला सरकार के ध्यान में है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय का सुझाव देने के लिए जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक समिति गठित की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन

10603. श्री बसंत साठे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रथम पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के उत्कृष्टता-वार नाम क्या हैं जिनका कार्य निष्पादन वर्ष 1989-90 के दौरान उत्कृष्ट रहा है और उनकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या हैं और ऐसे निम्नलिखित तीन बैंकों के नाम क्या हैं जिनका कार्य निष्पादन सबसे अधिक असंतोषजनक रहा है;

(ख) बेहतर कार्य निष्पादन हेतु दिये गये प्रोत्साहन तथा असंतोषजनक कार्य-निष्पादन हेतु दिये गये हतोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं। करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अमिल सास्त्री) : (क) बैंकों के कार्यनिष्पादन की जाँच उनके कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न पैरामीटरों द्वारा की जा सकती है। जहाँ तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है, जिनके लिए कुल अधिमों का क्रमशः 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दिसम्बर, 1989 के अंत में (अद्यतन उपलब्ध) उनके कार्य निष्पादन के अनुसार पहले पांच और आखिरी तीन राष्ट्रीयकृत बैंक (20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से) नीचे दिए गए हैं :—

बैंक का नाम	कुल अधिमों के मुकाबले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अधिमों की प्रतिशतता के अनुसार रैंक (लक्ष्य 40 प्रतिशत)
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	1 (50.5 प्रतिशत)
इलाहाबाद बैंक	2 (48.6 प्रतिशत)
कारपोरेशन बैंक	3 (48.5 प्रतिशत)
देना बैंक	4 (46.5 प्रतिशत)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5 (46.3 प्रतिशत)
स्यू बैंक आफ इण्डिया	18 (41.8 प्रतिशत)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	19 (41.1 प्रतिशत)
यूको बैंक	20 (39.4 प्रतिशत)

बैंक का नाम

कुल अग्रिमों के मुकाबले कमजोर वर्गों के अग्रिमों की प्रतिशतता के अनुसार रैंक
(सदस्य 10 प्रतिशत)

पंजाब नेशनल बैंक	1 (13.5 प्रतिशत)
आंध्रा बैंक	2 (13.2 प्रतिशत)
इलाहाबाद बैंक	3 (12.8 प्रतिशत)
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	4 (12.3 प्रतिशत)
विजया बैंक	5 (11.9 प्रतिशत)
न्यू बैंक आफ इण्डिया	18 (10.3 प्रतिशत)
देना बैंक	19 (10.2 प्रतिशत)
बैंक आफ बड़ौदा	20 (10.1 प्रतिशत)

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार बैंक को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

संसद सदस्यों को पेंशन

10604. श्री के.बी.० चामस : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं लोक सभा से त्यागपत्र देने वाले संसद सदस्यों को पेंशन देने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति ने भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन की दर आदि के सम्बन्ध में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है। यह सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में निर्णित मामले

10605. श्री अनादि चरण दास : क्या बिधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार अनिर्णित पड़े मुकदमों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से दीवानी और आपराधिक मुकदमों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार मुकदमों का निपटारा शीघ्र कराने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्कात और खान मन्त्री तथा बिबि और न्याय मन्त्री (बी बिलस गोस्वामी) : (क) 31 दिसम्बर, 19०9 को उड़ीसा उच्च न्यायालय में 37330 मामले (32888 सिविल और 4442 दांडिक मामले) संबन्धित थे।

(ख) और (ग) जी हां। उड़ीसा उच्च न्यायालय के स्थायी अपर न्यायाधीशों के 14 स्वीकृत पदों में से 2 रिक्त पदों को भरने का मामला सरकार के ध्यान में है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास के लिए जीवन बीमा निगम की सहायक यूनिट की स्थापना

10606. श्री ए० आर० अन्तुले : क्या बिला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों को आवास ऋण देने से सम्बन्धित कार्य को देखने के लिए जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत एक अलग निगम अथवा सहायक यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

बिला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सरकार के अनुमोदन से अपनी गतिविधियों को आवास वित्त के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक सहायक आवास वित्त के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक सहायक आवास वित्त कम्पनी की स्थापना की है।

जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड नामक कम्पनी, जिस की स्थापना जीवन बीमा निगम द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक ऋण और विशेष निगम और आई. एफ. सी. आई. के साथ संयुक्त रूप से की गई थी, जीवन बीमा निगम से परमबद्ध ङग से उसके अलग आवासीय ऋण पोर्टफोलियो को अपने अधिकार में ले रहा है और अब यह 8 केन्द्रों से अपना कार्य कर रही है।

बंडमान निकोबार द्वीप समूह के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई सहायता

10607. श्री मनोरजन नक्त : क्या बिला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की विविध वित्तीय संस्थाओं ने पिछले दो वर्षों के दौरान बंडमान

और निकोबार द्वीपसमूह के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से कितनी राशि वास्तव में इस संघ राज्य क्षेत्र में वितरित की गई ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि चार अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने अंशमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एककों को गत दो वर्षों के दौरान मिलकर जो राशि मंजूर और सवितरित की है वह निम्नलिखित है :—

	(लाख रुपये)	
	1987-88	1988-89
मंजूरिया	62.0	23.0
संवितरण	42.0	39.0

अंशमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

10608. श्री मनोरंजन मजत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंशमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान खोले गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी तक किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लिखित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत

दिए गए ऋण

[हिन्दी]

10609. श्री राजवीर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत, अब तक कितने लोगों को ऋण दिया गया है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी बचत राशि का ऋण दिया गया; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 से 1988-89 की अवधि के दौरान 12.36 लाख व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए । शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए हितार्थिकारियों की संख्या और उन्हें मंजूर ऋणों की राशि के आंकड़े अर्थात् तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) योजना के अन्तर्गत सरकार ऋण राशि का 25 प्रतिशत पूंजीगत सम्पत्ति के रूप में उधारकर्ताओं को देती है जिसके लिए वर्ष 1990-91 में 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त किये गये विदेशी परियोजनाओं के ठेके

10610. श्री राजबीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों को विदेशों में कितनी परियोजनाओं के ठेके प्राप्त हुए हैं; और

(ख) ऐसे ठेके किन-किन देशों ने दिये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द जीबरेन) : (क) इण्डियन बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त सूचना के अनुसार 1987, 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त विदेशी परियोजनाओं के ठेकों की कुल संख्या 100 थी ।

(ख) परियोजनाएं प्रदान करने वाले देशों के नाम निम्नानुसार थे :—

1. अल्जीरिया
2. बहरीन
3. बांग्ला देश
4. इथियोपिया
5. इण्डोनेशिया
6. ईरान

7. ईराक,
8. कन्या
9. कुवैत
10. जाइँन
11. लीबिया
12. मलेशिया
13. मलावी
14. मारुटा
15. मालद्वीप
16. मौजाब्बक
17. नेपाल
18. नाइजीरिया
19. नाइजर
20. ओमान
21. पी०डी०आर०वाई०
22. कतर
23. सउदी अरब
24. श्रीलंका
25. सोमालिया
26. सूडान
27. सीरिया
28. ताइवान
29. थाइलैंड
30. टर्की
31. संयुक्त अरब अमीरात
32. यमन अरब गणराज्य
33. जाम्बिया

राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शर्तों

[अनुवाद]

10611. श्री आर० श्रीचरत्तन : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के सम्बन्धित शाखा प्रबंधकों द्वारा पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिहाड़ी पर रखा जाता है तथा बाद में उन्हें नियमित किया जाता है;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार का विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शर्तों के लिए अनुपालन हेतु नियम एवं प्रक्रिया तैयार करने का विचार है; और

(ग) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में अस्थायी/दिहाड़ी पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनकी सेवाएं कब नियमित की जाएंगी ?

बिस्स मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जमिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ स्तरों में नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालयों/जिला सैनिक बोर्डों, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से की जाती हैं। बैंकों के अधीनस्थ स्तरों में नियमित नियुक्तियाँ सीधे शाखा प्रबंधक द्वारा नहीं की जाती हैं। अलबत्ता, अस्थाई प्रकृति के कार्य में हुई बृद्धि/नियमित अधीनस्थ कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने के कारण हुई कमी का सामना करने के लिए बैंक अस्थाई प्रकृति के खाली स्थानों को अस्थाई तौर पर/दैनिक मजदूरी के आधार पर भरते हैं। द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों और औद्योगिक कानूनों के अंतर्गत अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति पर विचार किया जाता है, वशतः कि वे योग्यता आदि की शर्तों के साथ-साथ द्विपक्षीय समझौता/औद्योगिक कानूनों के समूचित प्रावधानों के अनुसार पात्र हों। प्रविष्ट की रिक्तियों में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बैंक सामान्य तौर पर इन कर्मचारियों का पैनल रखते हैं। कुछ बैंकों के अधीनस्थ स्तरों के लिए नियुक्तियाँ अचल/अधीनस्थ/महिलाय कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ स्तर पर की जाती हैं, अतः उनके पास उपलब्ध आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसे कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में अपेक्षित ढंग से सूचना तत्काल एकत्र नहीं करती है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में दिये गये ऋण

10612. श्री आर० श्रीचरत्तन : क्या बिस्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जारी रखने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में लोगों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी राशि के ऋण वितरित किये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण वितरित करने की प्रक्रिया से स्थानीय संसद सदस्यों को सम्बद्ध करने का है ताकि वे ऋण वास्तव में ग़रिब-मन्द लोगों को वितरित करा सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी हाँ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वर्ष 1990-91 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा संचितरित ऋण का राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये)
1987-88	8374.05
1988-89	8487.48
1989-90	7357.18
(फरवरी 1990 तक)	

(ग, और (घ) कार्यक्रम को जिलास्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का एक शासी निकाय होता है जिसका अध्ययन कलक्टर होता है। अन्य लोगों के साथ-साथ जिले के सभी संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य होते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय की बैठक प्रत्येक तिमाही को होती है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में घाटा

10613. श्री आर० श्रीधरलाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और कितना घाटा हुआ है; और

(ग) भविष्य में कम्पनी में हो रहे घाटे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा बिधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) पुराना प्रौद्योगिकी, पुराने सयंत्र तथा उपस्कर, और मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टि से कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई जिससे ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि हुई है; उत्पादकता तथा क्षमता का उपयोग कम होता है, के कारण संयंत्र को मुख्य रूप से घाटा हुआ है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हुए घाटे की वास्तविक धनराशि का पता लेखाओं के लेखा-परीक्षण को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही लग पायेगा फिर भी संयंत्र को वर्ष 1989-90 के दौरान घाटा होने की संभावना है।

(ग) पुराने संयंत्र का प्रतिस्थापन तथा संयंत्र की प्रौद्योगिकी का उन्नयन और अत्यन्त लागत प्रभावी ढंग से इस्पात का उत्पादन करने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। इस आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप विशिष्ट ऊर्जा की

खपत में कमी होने, क्षमता और उसके उपयोग उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार होने की आशा है।

महाराष्ट्र में शिरडी का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जाना

10614. श्री बालासाहिब बिछे पाटिल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में शिरडी को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(क) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण मालिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र के सभी जिलों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का देखा जाना

10615. श्री बालासाहिब बिछे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिलों में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में नहीं देखे जा सकते;

(ग) क्या सूक्ष्मतरंग प्रणाली के अन्तर्गत इन शेष जिलों को जोड़ने का कार्य आरंभ हो गया है; और

(घ) इन जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक आरंभ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. ज्येष्ठ) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में (1981 की जनगणना के अनुसार) सभी 26 जिलों में पूर्णरूप से या आंशिक रूप से दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं। बालू विल बर्ष के दौरान औरंगाबाद तथा अम्बाजोगई लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि.वा.) ट्रांसमीटरों के बालू हो जाने पर इनमें से कुछ जिलों में दूरदर्शन कवरेज में पर्याप्त सुधार होने की आशा है।

(ग) और (घ) प्राथमिक (जेम्पीय) सेवा को रिक्त करने के लिए महाराष्ट्र के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटर उपग्रह की माफ़त दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से जुड़े हुए हैं।

नशीली दवाओं के दुष्परिणामों से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण

10616. श्री श्रीकांत दत्त तरसिहराज बाबियर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के खतरे को रोकने के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था,

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के विचार प्राप्त किये गये हैं,

(घ) क्या ये कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों से भी प्रसारित किए जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० ज्येन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न फार्मेटों में नशीली दवाओं के दुष्परिणामों पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

इसी प्रकार आकाशवाणी केन्द्र नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के विषय पर प्रतिमाह करीब 400 कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी ने 28 भागों का "रेडियो डेट" नामक विशेष धारावाहिक आरम्भ किया है जिसे 8 अप्रैल, 1990 से प्रसारित किया जा रहा है।

(ग) इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के विचारों को प्रतिबिम्बित किया गया है/ध्यान में रखा गया है। "रेडियो डेट", (रेडियो, नशीली दवाइयाँ, मद्य, तम्बाकू शिक्षा) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र, नामतः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, धीनवर, मद्रास, जसंवर, लखनऊ, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम अपनी कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार नशीली दवाओं के दुष्परिणामों पर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के विषय पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और "रेडियो डेट" धारावाहिक 15 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है।

रिबर्स पोड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

10617. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पोड़ी गढ़वाल में रिबर्स नामक स्थान का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

मछुआरों को ऋण सुविधाएं

10618. श्री टी० बक्षीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे मछुआरों के लिए ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने और अन्य प्रोत्साहन देने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल शात्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मत्स्यन के लिए दिया जाने वाला अधिम प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आता है क्योंकि यह क्षेत्र से सम्बद्ध कार्य है और अतः रियायती व्याज दर और उधार माजिन तथा प्रतिभूति मानदण्डों जैसे विभिन्न रियायतों के पात्र हैं ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि मत्स्यन के लिए आवश्यकता पर आधारित अल्पावधिक ऋण दिया जाना चाहिए । इसके लिए व्याज दर निम्नलिखित है—

(वार्षिक प्रतिशत)

(क) 7,500/- रु० तक की ऋण राशि के लिए 10.00

(ख) 7,500/- रु० से अधिक और 15,000 रु० तक की ऋणों पर

11.50

(ग) 15,000/- रु० से अधिक और 25,000/- रु० तक के ऋणों पर	12.00
(घ) 25,000/- रु० से अधिक ऋणों पर	14.00 से 15.50

मत्स्यन को 3 वर्षों से अधिक के सावधि ऋण निम्नलिखित दर पर दिए जाते हैं।
(वार्षिक प्रतिशत)

(क) छोटे किसानों को	10.00
(ख) अन्य को	12.50

10,000/- रु० तक की ऋण राशि पर मार्जिन नहीं लिया जाना चाहिए। इससे अधिक की ऋण राशि पर मार्जिन 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक अलग-अलग होगा। चल परि-सम्पत्तियाँ अर्जित की जाती हैं, वहाँ 10,000/- रु० तक के ऋणों पर बैंक को भूमि को दृष्टिबन्धक बना कर सम्पाशिवक प्रतिभूति या अन्य पक्ष गारंटी नहीं लेना चाहिए।

मत्स्यन के सभी पहलुओं के विकास के लिए अर्थात् मछली पकड़ने से लेकर निर्यात के स्तर तक, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरणों के वित्तपोषण, टैंकों (साफ पानी में मत्स्यन) के पुनरुज्जीवन, मछली उत्पादन आदि के लिए बैंक सावधि ऋण देते हैं।

केरल के निर्यात में कमी

10619. श्री टी० बक्षीर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान केरल से होने वाले विभिन्न मर्दों के निर्यात में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) कोचीन पत्तन तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से प्रमुख वस्तुओं के समग्र निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, इलायची, काली मिर्च और चाय के निर्यात में गिरावट रही।

(ख) गिरावट सम्बन्धी व्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वस्तुएं	88 अप्रैल - 89 फरवरी		89 अप्रैल - 90 फरवरी	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
इलायची	112	118.37	13	11.93
काली मिर्च	31306	13575.22	23858	11403.67
चाय	18975	4252.93	11251	3898.26

(ग) इसके कारण थे:—

काली मिर्च : कमजोर फसल, फसल की देर से आवक तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक आपूर्ति स्थिति का होना ।

इलायची : कमजोर फसल तथा उच्च घरेलू कीमतों का होना ।

चाय : कम उत्पादन होना ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनिजों की खोज

10620. श्री एन० डेविस : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने गत वर्ष के दौरान खनिजों के खण्डारों का पता लगाने के लिए कोई खोज कार्य प्रारंभ किया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वर्ष 1989-90 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये खोज कार्य का राज्यवार ब्योरा निम्नानुसार है :—

राज्य	किए गए खोज कार्य का संक्षिप्त ब्योरा
(क) आंध्र प्रदेश	—बुक्कगुडन्दा तथा ठापस कोंडा में टंगस्टन तथा ग्रेफाइट हेतु, कृष्णा जिले में हीरायुक्त लौह मिश्रण, बिसाखापट्टणम जिले में मेमिनाइट बियरिंग बीच संप्रदत्त ।
(ख) हिमाचल प्रदेश	—अर्को में कम सिलिकायुक्त चूना-पत्थर ।
(ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य	—पंचाल में कम सिलिकायुक्त मैग्नेसाइट तथा डोलोमाइट निक्षेप ।
(घ) कर्नाटक	—करवार तथा सिमोगा जिले में बौने-डिकरस मैग्नेसाइट निक्षेप ।
(ङ) मध्य प्रदेश	—जीलाबिला में लौह अयस्क निक्षेप ।

पाली में ब्रूदरक्षण रिले केन्द्र की स्थापना

10621. श्री गुमान मल लोढा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के पाली में एक ब्रूदरक्षण रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) राजस्थान के पाली नगर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर मार्च, 1988 से पहले से ही कार्य कर रहा है।

भुवनेश्वर में प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्यालय खोला जाना

10622. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कटक और भुवनेश्वर के समाचार केन्द्रों के रूप में महत्व को देखते हुए भुवनेश्वर में सूचना केन्द्र और बन्धालय के साथ-साथ प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी शर्तों क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी हाँ, इसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकार ने यह कार्यालय शीघ्र खोलने हेतु सभी सम्भव सहायता देने का भी प्रस्ताव किया। समाचार केन्द्र के रूप में नगर के महत्व को देखते हुए, आठवीं योजना में एक प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसे कार्य रूप देना साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बैंकों द्वारा कम मूल्य वर्ग के मोटों की सप्लाई

10623. श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आदि जैसे कम मूल्यवर्ग के मोटों की कोई कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है ?

और बाहकों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के बाहकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्यौरा क्या है और इसके लिए एक क्या सुधारार्थक कदम उठाये गये हैं ?

बिस्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अमिल साहू) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए जैसे कम मूल्य वर्ग के नोटों की कोई कमी नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि नई दिल्ली स्थित कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक 100/- से कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट नहीं देते हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति

10624. श्री बाई० एच० राजशेखर रेड्डी : क्या बिस्त सभी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की ऋण देने सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन है;

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन क्या हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

बिस्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अमिल साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सेबिस्ला स्पेन) में आयोजित यूनिवर्सल

एक्सपोजिशन में भारत का भाग लेना

10625. श्री बाई० एच० राजशेखर रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन के सेबिस्ला में अक्टूबर, 1992 में आयोजित की जाने वाली यूनीवर्सल एक्सपोजिशन में भारत के नाम लिए जाने को रद्द कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीचरण) : (क) और (ख) जी, हाँ। बजट सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सेविला (स्पेन) में अप्रैल, 1992 में होने वाले यूनिवर्सल एक्सपोजिशन में हम भाग लेने का कार्यक्रम रद्द कर दें।

स्वर्ण नीति

10626. श्री काशी राम राणा
श्री सन्तोष कुमार गंगवार
श्री शारदाराम पोठुखे
श्री विलीप सिंह अ. देव
श्री जनार्दन तिवारी
श्री बाई० एस० महाजन } : क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने की जमाखोरी समाप्त करने, गलत तरीके से कमाए गए धन को सोने में बदलने तथा सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या अभी किन्हीं "स्वर्ण बांडों" की अदायगी शेष है;

(ग) यदि हाँ; तो कितने मूल्य के बांडों की अदायगी की जाती है;

(घ) क्या सरकार की एक नई स्वर्ण नीति बनाने का विचार है; और,

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

बिस्व मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार का विचार है कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम को समाप्त किए जाने से व्यापार में होड़ के पैदा होने के साथ-साथ उसमें खुलापन आएगा तथा सोने के व्यवसाय में स्वतन्त्रता आएगी जिससे सोने की जमाखोरी समाप्त होगी।

सरकार, काले धन के उत्पादन, उसकी वृद्धि तथा उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के निमित्त ऐसे सभी आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपाय करती है जिससे स्वर्ण में काले-धन के निवेश पर रोक लगाई जा सके।

सोने की तस्करी की रोकथाम के लिए तस्करी-निवारण अभियान में तेजी लाई गई है और तस्करी-निवारण मशीनरी, विशेष रूप से, समुद्री-तट के सुगम्य क्षेत्रों, भू-सीमाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों तथा हवाई-अड्डों पर निपिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहती है। यात्रियों के ज़िम्मे पर और उनके असबाब/कारगो में छिपाए गए सोने का पता लगाने एवं इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के निमित्त तस्करी निवारण के अत्याधुनिक उपकरणों, जैसे एक्स-रे असबाब मशीनों तथा घातु-खोजी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तस्करी-निवारण और उसका पता लगाने से संबंधित सभी एजेंसियों के साथ निकट प्रमत्तव्य स्थापित किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार जिन स्वर्ण बांडों की पुनर्भेदायगी की जानी अपेक्षित थी.:-

स्वर्ण बांड	परिपक्वता की तारीख	बकाया धन-राशि
(I) 1977 के स्वर्ण बांडों का 6½% (रुपयों में पुनर्भेदायगी योग्य)	11.12.77	19.27 लाख रु.
(II) 1980 के स्वर्ण बांडों का 7% (रुपयों में पुनर्भेदायगी योग्य)	2.3.80	3.06 लाख रु.
(III) राष्ट्रीय राजा स्वर्ण बांड-1980: -- "क" सीरीज	27.10.80	5,72,760 घान
"ख" सीरीज (सोने में पुनर्भेदायगी योग्य)	27.10.80	2,55,353 घान

(घ) (ङ) सरकार ने वर्तमान स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है।

गुजरात के हिस्से के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशें

10627. श्री प्रकाश कोको गहलानहु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि उसका हिस्सा सातवें वित्त आयोग पंचाट के 4.6 प्रतिशत से गिरकर आठवें वित्त आयोग पंचाट में 3.87 प्रतिशत रह गया था तथा अन्ततः नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों में यह और घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने यह बताया है कि यह पंचाट राज्य के पक्ष में नहीं है तथा गुजरात सरकार के हिस्से के साथ भी बढ़ा अभ्यास किया गया है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपपत्री (श्री अनिल सास्त्री) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने नवें वित्त आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया था कि संसाधनों के समग्र अन्तरण में उनका हिस्सा कम होता जा रहा है।

(ग) नवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को संसाधनों के अन्तरण की सिफारिश करते समय गुजरात सरकार के निवेदन सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा।

दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाना

[द्वितीय]

10628. श्री० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की नीति में संशोधन करने का है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है, और

(ग) नए समाचार पत्रों (दैनिक और ग्राप्ताहिक) को विज्ञापन प्रदान किए जाने की सूची में शामिल करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० ज्येष्ठ) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार की विज्ञापन नीति के पहलुओं पर विचार करने के लिए गठित समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) सभी समाचार पत्र जो आवेदन करते हैं और जो विज्ञापन नीति (सलग विवरण के अनुसार) में दिए गए मानदण्ड को पूरा करते हैं, उन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की मीडियम सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाता है।

विवरण

(भारत सरकार की विज्ञापन नीति)

(अ) प्रस्तावना :

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों की ओर से विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक उद्यम भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं।

2. सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छापने वाले समाचार पत्रों तथा विज्ञान, कला, साहित्य, खेल व फिल्मों की मानक पत्रिकाओं के माध्यम से यथासमय अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापन देते समय सम्बद्ध प्रकाशन की राजनीतिक प्रतिबद्धता या संपादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है फिर भी ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, जो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों, अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर आघात करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदशों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों।

(ब) नीति निर्देश :

1. सरकारी नीति में प्रचार आवश्यकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों को एक संतुलित और नम्य आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाना है। सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचार पत्र-पत्रिका को आर्थिक सहायता देना नहीं है। सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न क्षेत्रों को पत्र/पत्रिकाओं के बीच बरों में समानता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार की पत्र/पत्रिकाओं को उपलब्ध धन (बेटेज) दिया जाएगा या उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है :—

- (अ) छोटे और मझौले समाचारपत्र/पत्रिकाएँ।
- (आ) विशेष सामग्रीयुक्त, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएँ।
- (इ) भाषाई समाचारपत्र/पत्रिकाएँ।
- (ई) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ।

2. छोटे, मझौले एवं बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :—

- (अ) छोटे—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 प्रति अंक तक हो।
- (आ) मझौले—जिनकी प्रचार संख्या 15,000 से 50,000 प्रति अंक के बीच हो।
- (इ) बड़े—जिनकी प्रसार संख्या 50,000 प्रति अंक से अधिक हो।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचारपत्र/पत्रिकाओं के चयन में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखा जाएगा :—

- (अ) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषतः राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुँचाना।
- (आ) विज्ञापन में निहित संदेश के आधार पर प्रचार अभियानों को समाज के सम्बद्ध विशिष्ट वर्ग तक पहुँचाना। छोटे और मध्यम वर्गों के समाचार पत्रों को प्रेरक तथा शिक्षा अभियानों के बारे में विज्ञापन देने को विशेष ध्यान में रखा जायेगा।
- (इ) समाचार पत्रिकाएँ/प्रकाशन की कोई अन्य क्षेत्री जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझे।
- (ई) घरेलू पत्र-पत्रिकाओं तथा स्मारिकों को सरकारी विज्ञापनों के लिए ब्यामछोर से हस्तोक्त नहीं किया जाएगा।

4. वि. दू. प्र. नि. ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 1000 है, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस सम्बन्ध में छूट दी जा सकती है :—

(अ) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं, जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम 500 प्रतिमां प्रति अंक हो ।

(ब) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमांत प्रदेश व दुर्गम क्षेत्र से अथवा जन-जातीय भाषा या जन-जातीय लोगों के लिए छपने वाली पत्र/पत्रिकाएं तथा जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाएं, जिनकी विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रति अंक हो ।

5. समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा हो और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का पालन किया गया हो । त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम से कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा ।

6. समाचार/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए :—

आवृत्ति	न्यूनतम मुद्रित स्थान
दैनिक	760 मानक कालम से. मी.
साप्ताहिक और पाक्षिक	480 मानक कालम से. मी.
मासिक और अन्य पत्रिकाएं	960 मानक कालम से. मी.

ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जन-जातीय भाषा या मुख्यतः जन जातीय लोगों के लिए प्रकाशित होते हैं ।

7. सभी समाचारपत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लेखाओं से सम्बन्धित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्था से प्रमाणित होनी चाहिए लेकिन जिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2000 प्रतियों तक है वे किसी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड एकाउंटेंट) या सम्बद्ध जिला दफाधिकारी (मजिस्ट्रेट) से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि किसी समाचार पत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी, तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए अयोग्य घोषित करने के अलावा सरकार उन पर अलग से भी कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह उचित समझे ।

(ख) विज्ञापन दर :

सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का ढांचा वि. दू. प्र. निदेशालय द्वारा उन सिद्धांतों के

आधार पर तैयार किया जाएगा, जिनकी व्याख्या ऊपर दी गई है। वि. वृ. प्र. नि. असम-असम पत्र-पत्रिकाओं के साथ यथोचित दरों पर अनुबन्ध करना।

मुम्बई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र तथा लघु चित्र फिल्म समारोह के बारे में जांच

[अनुवाद]

10629. श्री एम० जे० रायचा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग द्वारा फरवरी, 1990 के दौरान मुम्बई में आयोजित एक सप्ताह के अन्तर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र तथा लघु चित्र फिल्म समारोह के दौरान धन के अपव्यय और कुप्रबन्ध होने की शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में किसी जांच का आदेश दिया है, और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० जयन्त) : (क) "स्टेट्समैन" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दो लेख छपे थे जिनमें मुम्बई में आयोजित फिल्म समारोह के संचालन की आलोचना की गई थी। इन लेखों में फिल्म समारोह के संचालन में कथित कुप्रबन्ध और धन के अपव्यय का उल्लेख किया गया था। इन दो लेखों के जवाब, मुम्बई में आयोजित सप्ताह भर के इस समारोह पर कोई विशेष आलोचना नहीं की गई।

जातव्य रहे कि फिल्म समारोह की उल्लेखनीय सफलता की आमतौर पर सराहना की गई है। भारतीय तथा विदेशी समाचार पत्रों में इस समारोह की प्रशंसा में कई लेख प्रकाशित हुए हैं। इनमें विश्व भर में फिल्मों से सम्बन्धित विषयों पर टिप्पणी करने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका— "हालीवुड रिपोर्टर वीकली" भी शामिल है। इनके अलावा, 50 से अधिक प्रख्यात फिल्म हस्तियों ने अपने पत्रों में, इस समारोह के लिए फिल्म प्रभाग की प्रशंसा की और उसे बधाई दी है।

(ख) यह आलोचना प्रतिनिधियों के आतिथ्य, पुरस्कारों के वयन, प्रचार के अभाव प्रविष्टियों की घटिया बसालिटी आदि को लेकर की गई थी।

(ग) किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं है। तथापि, शिकायतों की जांच की गई है। फिल्म प्रभाग द्वारा कोई अधिक व्यय नहीं किया गया है। आशा है कि 60 लाख रुपये के स्वीकृत बजट की तुलना में कुल व्यय 54 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि समारोह पर्याप्त रूप से सफल रहा है और अधिकांश आलोचना बढ़ा बढ़ाकर की गई है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म नीति में संशोधन

10630 श्री प्रकाश बो० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म नीति की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित नयी फिल्म नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या नई फिल्म नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अधिक सक्षम बनाया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उषेन्द्र) : क से (घ) फिल्म नीति बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि प्रस्तावित फिल्म नीति का व्योरा क्या होगा और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा अथवा नहीं और उसे किस हद तक सुदृढ़ किया जायेगा।

भारत-अमरीका आर्थिक व्यापार सम्बन्धों पर विचार-विमर्श

10631. श्री मदन लाल खुराना : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1990 को "दि इंडियन एक्सप्रेस में" यू.एस. बिजनेसमैन नाट इम्प्रैसड विद इंडियाज प्रोमिसेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकषित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो की गई बातों और इस सम्बन्ध में अमरीकी व्यापारियों की प्रतिक्रिया का व्योरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी व्यापारियों से भारत में अधिकारी तंत्र द्वारा बिलंब किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाये गये अथवा प्रस्तावित कदमों का व्योरा क्या है ?

बाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल बीबरन) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत-अमरीका मधुक्त कारोबार परिषद की बैठक 5 और 6 अप्रैल, 1990 को वाशिंगटन में हुई। इस बैठक में दोनों देशों के कारोबार और उद्योग के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और विवादों पर मधुक्त रूप से विचारों

की : (I) प्रौद्योगिकी-अन्तरण । (II) भारतीय निवेश और संयुक्त उद्यम कानून । (III) द्विपक्षीय व्यापार ।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त कारोबार परिषद को संबोधित किया और उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया ।

(ग) संयुक्त कारोबार परिषद के सह-प्रध्यक्ष श्री डोनाल्ड एम. केंडल ने अपने भाषण में सामान्य रूप से नीकरसाही का उल्लेख किया और विनियमन समाप्त करने और अर्थव्यवस्थाओं की उदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया । जे०बी०सी० की बैठक के दौरान किन्हीं शासक-यत्नों को नहीं उठाया गया । सामान्यतया सरकारी प्रक्रियाओं के कारण होने वाले विलम्ब का जिक्र किया गया ।

(घ) प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारणों को लगातार मानाटर किया जा रहा है तथा उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ।

कपास की खरीद

10632. श्री बाई० एल० राजसेनर रेड्डी : क्या बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कपास की बसूली के लिए अधिक धनराशि देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

बिल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कपास की खरीद के लिए ऋण की आवश्यकताओं का सम्पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है बशर्ते कि मूलभूत सिद्धान्त की पूर्ति की जाए, अर्थात् आर्हरित ऋण साध के मूल्य से बेल खाता है ।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा फार्म व्यापार को उद्योग बनाया जाना

10633. श्री कैलाश मेहता : क्या आर्थिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मध्यम देशों द्वारा फार्म व्यापार को उद्योग बनाये जाने से भारत की कृषि विकास योजनाओं वित्तबकर साध प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या ऐसे उद्यारीकरण से हमारी निर्वात की संभावनायें नष्ट हो जायेंगी जो हमारी साध प्रसंस्करण योजनाओं का प्रमुख साधार है;

(ग) क्या सरकार ने इस आकस्मिकता का सामना करने के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

बाजिब्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के देशों द्वारा कृषि व्यापार को उदार बनाए जाने के कारण इन देशों को किए जाने वाले संशोधित कृषि उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात पर लाभकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुःख के साथ इस महान् सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री के० एस० हेगड़े के निधन की सूचना सदन को देनी है। वह जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक इस सभा के अध्यक्ष रहे थे। श्री हेगड़े कर्नाटक राज्य के बंगलूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 21 जुलाई, 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गये। इससे 1952 से 1957 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री हेगड़े एक प्रख्यात विधिवेत्ता और विद्वान् थे तथा 1957 से 1966 तक मैसूर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश रहे। वह 1966-67 के दौरान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने 1967-73 के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप कार्य किया।

अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के अलावा श्री हेगड़े दोनों सदनों की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। वह राज्य सभा में सभापति तालिका के सदस्य भी थे तथा इस सदन की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष भी रहे।

श्री हेगड़े 1954 में संयुक्त राष्ट्र के नौवे अधिवेशन में वैकल्पिक प्रतिनिधि थे तथा उसकी दूसरी समिति (सेक्रेटरी कमेटी) के सदस्य थे।

इस सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी टिप्पणियां और विनिर्णय बाद में आने वाले अध्यक्षों के लिए बड़े सहायक सिद्ध हुये।

श्री हेगड़े का निधन 81 वर्ष की आयु में कर्नाटक में उनके मूल निवास स्थान पर 24 मई, 1990 को हुआ।

प्रधानमंत्री (श्री बिस्मिल्लाह प्रताप सिंह) : श्री के० एस० हेगड़े के सम्बन्ध में जो भावनाएँ आपने व्यक्त की हैं; वही भावनाएँ हमारे मन में भी उठ रही हैं। श्री हेगड़े एक महान् विद्वान् थे तथा न्याय प्रक्रिया में उनकी गहरी पहुँच थी। वह दिल्ली और हिमाचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उनके लेखों और पुस्तकों से न्याय प्रक्रिया की समस्याओं को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो परम्पराएँ स्थापित कीं वे आने वाले समय के लिए हमारी पथ प्रदर्शक रहेंगी। उनके निधन से हमने एक विद्वान और देशभक्त को खो दिया है।

हुस की इस घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके परिवार को बस दुःख घटना को सहन करने की शक्ति दे।

प्रो० एन० बी० रंगा (गुंटूर) : इस अवसर पर आपने और प्रधान मंत्री ने जो कहा है हमारा दिल और मैं उसमें आपके साथ हूँ।

मुझे राज्य सभा में उनका सहयोगी रहने का सीमाव्य प्राप्त हुआ और मैंने पाया कि वह कृषकों के हितरक्षक थे। सभा में जब कभी प्रश्न किए जाते थे तो मैंने उन्हें सदैव ही अपना बहुत अच्छा समर्थक पाया। वह किसान आन्दोलन के अत्याधिक सुमन्वित थे। वह अपनी पीढ़ी के सभी देशभक्तों की भाँति धुस से कांग्रेसी थे तथा कर्नाटक के भी एक अत्यन्त प्रभावी कांग्रेसी नेता साबित हुए। महोदय, निधन पर मुझे गहरा शोक है। तथा मेरा दिल उनके परिवार को संवेदना प्रकट करने में आपके साथ है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल बैंगलोर से श्री के० एस० हेगड़े का सुपुत्र ने जब मुझे फोन से सूचना दी कि श्री हेगड़े का रात्रि को निधन की अवस्था में हो निधन हो गया है तो अनेक कारणों से बहुत शोक हुआ बहुत अफसोस हुआ। सामाजिक जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शालीनता, सहृदयता और साध-साध जिन सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, श्री के० एस० हेगड़े उन सिद्धान्तों की ऐसी उदाहरण प्रतिभूति थे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होने के बाद जब न्यायाधीश बनते हैं, तो फिर अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को अपने न्यायमूर्ति कर्तव्य के नाते जो दायित्व है, उनको कर्तव्य नहीं होना दिया। यह उनमें से थे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट इन सब से होते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन। 1973 में सुपरसेशन के इस्तेमाल पर उन्होंने त्यागपत्र दिया तब पहली बार उनसे सम्पर्क आया। तब से लेकर जीवन-पर्यन्त उनसे सम्बन्ध रहा और विगत दस वर्षों में वे मेरे दिल के बरिष्ठ नेता थे, बरिष्ठ सहयोगी थे। कभी भी कोई समस्या किसी बात पर होती थी तो उनकी सलाह हमारे लिये बहुत मूल्यवान् रहती थी।

रंगा जी ने अभी उनकी कृषकों में जो रुचि थी, उसका उल्लेख किया। मैं जानता हूँ कि 1981 में या 982 में जब गुजरात में एक बहुत प्रबल आन्दोलन आरम्भ के खिलाफ चला था, मेरी पार्टी में भी कुछ लोग थे जो कि उस आन्दोलन से प्रभावित हुए थे, तो उसके बाद जब हमने मिल करके कोचीन में इस विषय पर सम्मेलन से विचार किया तो उन्होंने हमारी पार्टी के प्रमुख सदस्यों को सबसे अधिक प्रभावित किया। श्री के० सदानन्द हेगड़े ने वर्षों तक हम सब को प्रभावित किया और

कहा कि इस मामले में हम को किसी भी प्रकार की कीमी बात नहीं करनी चाहिये और वह जो हमारे हरिजन या वनवासी बन्धु हैं, जिनके साथ शताब्दियों से अन्याय होता रहा है, थोड़ा बहुत लाभ आरक्षण से उनको जो प्राप्त होता है, उसके बारे में अगर हम पुनर्विचार करने लगेंगे तो कुल मिला कर समाज का बहुत बड़ा अहित होगा और हानि होगी। इस बात का उल्लेख मैंने इसलिये किया है कि हर मामले में एक न्यायप्रिय एग्रीज, प्रेजिटिकल एग्रीज, प्रेगमैटिक एग्रीज और आइडलिस्टिक एग्रीज का बहुत बढ़िया सम्मिश्रण मैंने उसमें पाया। मैं आपके साथ, प्रधान मंत्री जी और विपक्ष के श्री रंगा जी की भावनाओं के साथ अपने को समबद्ध करते हुए, दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर श्री के० एस० हेगड़े के बारे में कहे गए कथन से हमारा दन और मैं पूर्णतया आपके साथ हूँ तथा हम उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

मुझे निजी तौर पर श्री हेगड़े को एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, इस समाज के माननीय सदस्य तथा अन्ततः इस धृतीत समाज के एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष के रूप में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री हेगड़े के सम्पर्क में आने वाला हर व्यक्ति हमारे संबैधानिक ढाँचे, तथा इसमें निहित मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों में उनके गहन विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक महत्वपूर्ण विनिर्णय दिये तथा 'कैपाक' के केस में अपने निर्णय में उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बहुत ऊँचाई पर पहुँचा दिया, इसे न्यायशास्त्र में एक दीप स्तम्भ माना जाता है। हमें उनको ऐसे अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में जानने का अवसर भी प्राप्त हुए जिन्होंने इस समाज की कार्यवाही को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उस समय समाज के किसी भी वर्ग को कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसा सदस्य है जिसे समाज में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया। मैं उस समय एक संसदीय समिति का अध्यक्ष था तथा मुझे कई अवसरों पर विभिन्न मामलों पर उनसे चर्चा करने का सुअवसर मिला और मैं उन्हें महायक पाया तथा उनके सुझाव रचनात्मक होते थे। मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। मैं आनी पार्टी तथा अपनी तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त करता हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, श्री के० एस० हेगड़े के दुःखद निधन पर मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा कही गई बातों से मैं तथा मेरी पार्टी के सभी सदस्य सहमत हैं।

महोदय, मुझे निजी तौर पर उनके साथ काम करने का सौभाग्य तो नहीं मिला लेकिन मैंने अन्य लोगों से अध्यक्ष के रूप में उनकी योग्यता के बारे में सुना है, वह यहाँ पर न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि से आए थे और मेरे विचार से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है कि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। मैं समझती हूँ कि आज के परिवेश में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए तथा इस गुण का अनुकरण करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ।

डा० लम्बि बुरे (कस्कर) : अध्यक्ष महोदय, आप से यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि हमारे मृतपूर्व अध्यक्ष श्री के० एस० हेगडे अब नहीं रहे। अभी-अभी हमारे प्रधानमंत्री तथा प्रो० रंगा, श्री बाबसाहेब और मेरे अन्य साथियों ने उनकी न्यायिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में उनकी सेवाओं का उत्सव किया है। उन्होंने न्याय व्यवस्था में ही न्याय सुनिश्चित नहीं किया बल्कि राजनैतिक जीवन में भी न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने 1977 के कठिन समय में इस सभा की अध्यक्षता की तथा उन्होंने एक उत्कृष्ट अध्यक्ष के रूप में भी समाज का संचालन बहुत सावधानीपूर्वक से किया तथा बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया; जैसा कि रंगा जी ने कहा है, उन्होंने राज्य सभा तथा लोकसभा में भी अनेक महत् उठाए हैं। वह कृषकों के हितों का संरक्षण किया। उन्होंने एक न्यायपूर्ण के रूप में भी बहुत अच्छा न्याय दिया वह अब हमारे बीच नहीं रहे।

मैं अपनी पार्टी और स्वयं अपनी ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री नानो भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने ग्रुप की ओर से श्री हेगडे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं अपने अन्य साथियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ तथा श्री हेगडे के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (बंबेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाव द्वारा तथा प्रधानमंत्री और अन्य साथियों द्वारा मृतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री हेगडे के निधन पर व्यक्त किए गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे उनके निधन पर बहुत दुःख हुआ है। वह बहुत ही ईमानदार तथा चरित्रवान व्यक्ति थे। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्टनीय कार्य किया तथा वह न सिर्फ कर्नाटक तथा 'दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे बल्कि बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। वह 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे तथा मोरारजी से मैं उस समय लोकसभा में था। उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही का प्रक्षेत्रनीय ढंग से संचालन किया और इस सभा की गरिमा को कायम रखा।

हमें बहुत अरुणः है तथा मैं अपनी तथा अपनी पार्टी मुस्लिम लीग की तरफ से शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ तथा उनकी आत्मा को शान्ति की कामना करता हूँ।

श्री संजुहीन सोब (बाराबतुला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री, आपके द्वारा तथा प्रो० रंगा जी और अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ।

यद्यपि मुझे श्री हेगडे को एक मिष्ठान्त वाले नेता के रूप में जानने का मौका तो मिला लेकिन इस सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें जानने का मौका मुझे नहीं मिला।

महोदय, हम केन्द्रीय कक्ष में इस उच्च पद पर आसीन रह चुके व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। मैंने स्वर्गीय श्री हेगडे के बारे में यह सुना कि वह एक न्यायाधीश के रूप में तथा इस पुनीत सभा के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत साहसी व्यक्ति थे। मैंने सुना कि कभी-कभी जब विधिवेत्ता तथा कानून के विषयान्तर उच्च पदों पर आसीन होते हैं तो बड़े सीमित दायरे में कार्य करते हैं। मैंने श्री हेगडे के एक और अमूर्त गुण के बारे में भी सुना है कि विभिन्न मुद्दों के मामले में बहुत अधिक सतर्क नहीं थे। उनमें मौल्यता तथा अत्यधिक विवेक था और उन्होंने इस उच्च पद की गरिमा बढ़ाई। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

कुमारी मायाबती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने, माननीय प्रधान मंत्री जी और मुझे सीनियर माननीय सदस्यों ने श्री हेगड़े जी की काबलियत और इन्सानियत पर काफी विस्तार से तो नहीं, लेकिन बहुत ही संक्षेप में इस सदन के सामने जानकारी रखी है। मैंने तो उनको कभी सुना नहीं है। न मुझे उन्हें देखने का मौका मिला, लेकिन अखबारों के माध्यम से और मंगजीन्स के माध्यम से मुझे उनके बारे में जानकारी मिलती रही है।

मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से श्री हेगड़े जी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करती हूँ।

[अनुबाव]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके इस सभा के नेता तथा सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री के० एस० हेगड़े को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि आपने कहा है, वह भारतीय न्यायपालिका के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और अन्ततः वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गए थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर गहन चिन्तन किया तथा 'दि ब्राइसिस ऑफ जस्टिसियरी' नामक एक पुस्तक भी लिखी। वह एक योग्य सांसद थे। जैसा कि आपने कहा है, वह राज्य सभा तथा इस सभा के भी सदस्य रहे तथा उन्होंने अनेक संसदीय समितियों में उल्लेखनीय योगदान किया।

महोदय, मुझे उनकी अध्यक्षता के अन्तर्गत 1977 में इस सभा में कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुझे उनके द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ याद हैं जो तत्काल सभा के लिए बहुत ज्ञानवर्धक थीं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विनिर्णय भी दिये हैं जो हमारे देश की संसदीय प्रक्रियाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करेगी।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 28 मई 1990 के ग्यारह बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.20 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 28 मई, 1990/7 ज्येष्ठ, 1912

(शक) के ग्यारह बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एण्ड सन्स, 7117/18 पहाड़ी घीरज, दिल्ली-110006